• सिंधिया को भाजपा में मिलेगी तवज्जो? • बुंदेलखंडः रोटी के लिए अवैध खनन

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

www.akshnews.com

लॉकडाउन है सिर्फ जुगाड़

वर्ष 18, अंक-13 | 1 से 15 अप्रैल 2020 | मूल्य 25 रूपये

R.N.I NO.HIN/2002/8718 M.P. BPL/642/ 2015-17

जुगाड़ से सरकार तो बना ली...

क्या दाग धो पाएंगे

शिवराज?

राष्ट्रीय पाक्षिक

अक्स की ओर से

हिन्दू नववर्ष

एवं

चैत्र नवरात्रि

की आप सभी को

हार्दिक शुभकामनाएं...

इस अंक में

राजपथ

10-11 | सिंधिया को भाजपा में मिलेगी तवज्जो?

कांग्रेस को 18 साल देने वाले ग्वालियर के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भाजपा के हो चुके हैं। राजमाता के बाद वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे पहले से ही भाजपा में हैं। वहीं ज्योतिरादित्य यानि महाराज भी अब भाजपा की आवाज...

लालफीताशाही

12 | भूखे न रह जाएं बच्चे?

मप्र में नोवेल कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए 14 मार्च से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। बच्चों को पोषण देने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने 17 मार्च को एक आदेश में बच्चों को टेक होम राशन...

स्वास्थ्य

14-15 | लॉकडाउन है सिर्फ जुगाड़!

इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है। पूरे विश्व में 7 लाख से अधिक लोग इस महामारी की चपेट में आए हैं। इनमें से 33,993 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में 1300 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि 45 की मौत हो चुकी है।

मुद्दा

16 | कहां हैं माननीय?

दुनिया के लगभग सभी देशों में कोरोना की प्रतिछाया के दुष्परिणाम सामने हैं। आज दुनिया पर महामारी का प्रकोप है। कोरोना जिसका इलाज अभी वैज्ञानिकों के पास नहीं है, ऐसे में यह तो होना ही था कि हमारी सरकार जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन और कर्फ्यू के रास्ते पर चल पड़े।

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

मप्र में शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच दिया है। भाजपा को अबकी बार सत्ता कांग्रेसियों की आपसी फूट के कारण मिली है। 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने भाजपा को नकार दिया था। इसकी एक वजह यह थी कि भाजपा की 15 साल पुरानी सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप थे। खुद शिवराज सिंह चौहान पर कई आरोप थे। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या इस बार शिवराज सिंह चौहान अपने ऊपर लगे दाग धो पाएंगे?

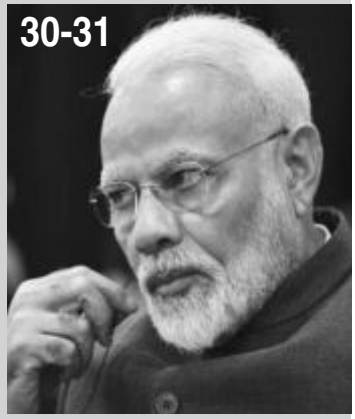

सियासत

32-33 | टूट रहा सब्र का बांध

देश की राजनीति के मौजूदा हालातों को देखते हुए यह लाख टके का सवाल है कि आखिर राहुल गांधी की टीम के सदस्य अब क्या करेंगे? राहुल के करीबी दूसरी पीढ़ी के ये नेता राज्यसभा न जाने का दंश मन में दबाए पूरे 5 साल क्या रह सकेंगे? वैसे तो इस टीम के कैप्टन और राहुल...

राजस्थान

36 | क्या पायलट करेंगे विद्रोह?

जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ा है, सियासी गलियारों में ये चर्चा छिड़ गई है कि युवा नेता सचिन पायलट भी कांग्रेस से दूरी बना सकते हैं। सिंधिया के करीबी माने जाने वाले राजस्थान के उप-मुख्यमंत्री पायलट के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी जल्द...

बिहार

38 | जातिगत राजनीति का सच

बिहार की सियासत में जाति एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन पूरी तरह नहीं। जातीय जनगणना के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने वाले बिहार की राजनीति में जातियों के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। बिहार में सवा दो सौ से ज्यादा...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

अफसरों को फुटबाल बनाती सरकारें

म प्र में पिछले 15 माह से जिस तरह के हालात दिख रहे हैं उस पर कवि दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां याद आती हैं-

अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार,
घर की हर दीवार पर चिपके हुए हैं इश्तहार।

दरअसल, मप्र की राजनीति में यह देखने को मिल रहा है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की सरकार पर जो आरोप लगाती है वही पार्टी जब सत्ता में आती है तो वह भी वही करती है जो दूसरी पार्टी ने किया होता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के 15 माह के शासनकाल को केवल तबादलों के लिए याद रखा जाएगा। लेकिन वर्तमान सरकार ने भी अपनी शुरुआत जिस तरह तबादलों के साथ की है, उससे तो यह साफ हो गया है कि सरकार कोई भी हो वह अफसरों को फुटबाल ही समझती है। एक सरकार आती है तो वह अपने मनपसंद अफसरों को उनकी पसंद की जगहों पर बैठाती है और जब दूसरी सरकार आती है तो वह उन अफसरों को चमकाकर अपनी पसंद के अफसरों को बैठाती है। इस परिदृश्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे अच्छे अफसर इन्हें मिलते नहीं हैं या अच्छे अफसर इनके एजेंडे में फिट नहीं बैठते हैं? यह कहना गलत होगा कि फलां सरकार अपनी मर्जी से अपने चहेते अफसरों को नियुक्त करती है। यह छांटो और चुनो की प्रक्रिया हर सरकार में रही है। आगे भी रहेगी। हर अफसर और सरकार अपना विश्वस्त और वफादार मातहत चुनता है। विश्वसनीयता और वफादारी का पैमाना स्वक्षेत्रवाद, स्वधर्मवाद, स्वजातीयवाद से भी प्रभावित हो सकता है और इन सबसे परे पेशेवराना गुणों से भी। पर स्वक्षेत्र, स्वधर्म और स्वजातीयता एक मानवीय प्रवृत्ति है। पर यह देखना भी सरकार के मुखिया का दायित्व है कि वह अपनी कोर टीम चुनते समय इन सबको तरजीह देना किन्हीं कारणों से जरूरी भी हो तो शीर्ष, संवेदनशील और महत्वपूर्ण पदों पर साफ सुथरी छवि के नौकरशाह या अफसरों को ही नियुक्त किया जाए। यह सभी जानते हैं कि अफसर जो भी हो वह वही करता है जो सरकार चाहती है। ऐसे में समझ में नहीं आता है कि फिर सरकार अफसरों को ताश के पत्तों की तरह क्यों फेटती रहती है। यह भी समझ से परे है कि किसी सरकार को कुछ ही अफसर क्यों पसंद आते हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है वे अफसर बस इसी सरकार के होकर रह गए हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि अपने पसंदीदा अफसर को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकारें उसके गुण-दोष का भी ध्यान नहीं देती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छे और अविवादित अफसर कम हैं या नहीं हैं। वे अच्छी खासी संख्या में हैं पर जैसी की हवा चल जाती है वे जानबूझकर थोड़ा इस धूल गर्दे से दूर रहने लगते हैं। जिसे हम लॉ प्रोफाइल कहते हैं वैसे वे हो जाते हैं। सरकार को भी 'जो अक्सर चाटुकारों से घिरी नजर आती है' वह इन चाटुकारों की दीवार के पार देख भी नहीं पाती, तो कुछ इन चाटुकारों का दबाव, कुछ स्वार्थपूर्ति की लिप्सा, कुछ अपने दल के एजेंडा पूर्ति की महत्वाकांक्षा और कुछ जी जहांपनाह टाइप के अधिकारी, सरकार को कुछ देखने भी नहीं देते। यह एक विचित्र प्रकार का दूरदृष्टिदोष है। नतीजा, सरकार को भुगतना पड़ता है। एक अच्छे शासक को भी ऐसी दरबारी टीम विवादित बना देती है। यह सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वह भविष्य में ऐसे पेशेवर अफसरों का चयन करे भले ही वे सरकार के मुखिया या दल के एजेंडे की कसौटी पर खरे नहीं उतरें पर उनकी योग्यता सत्यनिष्ठा और प्रोफेशनल क्षमता संदिग्ध न हो। सरकार कोई भी हो सरकार का मूल तत्व यही नौकरशाही होती है। सरकार के मुखिया का ही यह कौशल होता है कि वह कैसे उपयुक्त स्थान के लिए उपयुक्त अफसर का चयन करता है। नौकरशाही को सनक और राजनीतिक मर्जी से नहीं हांका जा सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो इसका खामियाजा अंत में राजनैतिक नेतृत्व ही भुगतता है। अमूमन अफसरों का कुछ खास नहीं बिगड़ता है।

-राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 18, अंक 13, 1 से 15 अप्रैल, 2020

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2015-17

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:-** इंद्रकुमार, **जयपुर:-** आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:-** संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ :-** मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
094259 85070, (मंदसौर) धर्मवीर रत्नावत
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-
फोन : 011 25495021, 011 25494676
मुंबई : बी-1, 41 शिव पावर्ती चेम्बर प्लाट नंबर 106-110 सेक्टर-21
नेरूल, नवी मुंबई-400706 मो.-093211 54411
कोलकाता : 70/2 हजरा रोड कोलकाता
फोन-033 24763787, मोबाइल: 09331 033446
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
फोन- 0141 2295805, मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई,
मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिंलटर निपानिया, इंदौर
मोबाइल - 094251 25096

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

ग्राहक क्यों भुगतें?

देश में बैंकिंग घोटाले सामने आने के बाद अब हाल यह है कि कई बैंक दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए हैं। वर्तमान में यस बैंक की स्थिति नाजुक है। बैंक की बदहाल स्थिति का खामियाजा उन ग्राहकों को भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने अपनी कमाई की रकम बैंक में जमा करवाई है।

● **राहुल जैन,** इंदौर

नकेल कसना जरूरी

प्रदेश में इन दिनों फर्जी कंपनियों से जनता परेशान है। लोग कड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं और ये फर्जी कंपनियां उन्हें बहला-फुसलाकर कहीं भी इन्वेस्ट करने को कह देती हैं। ऐसे में आम आदमी की जमापूंजी डूब जाती है। सरकार को इस बारे में ठोस कदम उठाना चाहिए।

● **भावेश चौहान,** ग्वालियर

घर में ही रहें

दुनियाभर में कोरोना वायरस का खौफ है। भारत में भी कोरोना के मरीजों में बढ़ोत्तरी हो रही है। ऐसे में हर एक व्यक्ति के लिए अपने और अपने परिवार की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। लोगों का घर पर रहना ज्यादा जरूरी है। ऐसे वक्त में यही सबसे सही कदम है।

● **राम प्रसाद,** भोपाल

किसानों को मिले फसलों का उचित दाम

देश का किसान फसल को उगाने के लिए कई महीनों तक लगातार खेतों में मेहनत करता है। तब कहीं जाकर हम सुकून से घर में खाना खा पाते हैं। लेकिन दुविधा यह है कि अन्नदाता कहे जाने वाले किसान को आज भी अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिलता। पूरे सारे देश का पेट भरने वाले किसानों के लिए सरकार को और अधिक सुविधाएं लागू करनी चाहिए। कृषि उपजों की बिक्री के लिए एक सुविधाजनक मंच बनाने की जरूरत है ताकि अंतिम उपभोक्ताओं तक किसानों की पहुंच बढ़ाई जा सके। किसान सीधे अपनी फसल वहां तक पहुंचाए, जिससे वे बिचौलियों से बचा रहे और उसको अपनी फसल का सही दाम मिल सके।

● **राजेंद्र वर्मा,** जबलपुर

महिलाओं का हौंसला बढ़ाने की जरूरत

भारत में महिलाओं को पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तो कहा जाता है, लेकिन आज भी कई लोग इसके खिलाफ हैं। उद्योग के क्षेत्र में महिलाओं का हौंसला बढ़ाने की जरूरत है, न कि उन्हें कमजोर साबित करने की। इंदिरा गांधी, किरण बेदी जैसी महिलाएं सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत हैं। कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो दफ्तर में काम करने के बाद अपने घर को भी संभालती हैं। ऐसी महिलाएं भी अन्य के लिए भी प्रेरणा स्त्रोत हैं।

● **रुबीना शेख,** नई दिल्ली

सम्मान जरूरी है

पार्टी कोई भी हो नेता का सम्मान जरूरी होता है। भाजपा में भी ऐसे कई नेता थे जो पार्टी में सम्मान न मिलने के कारण दूसरी पार्टी में चले गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी यही किया। उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस में उनका भविष्य नहीं है तो वे भाजपा में चले गए। मध्यप्रदेश कांग्रेस के कई नेता व मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुनना ही नहीं चाह रहे थे, न ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनके भाषणों पर ज्यादा ध्यान दिया।

● **भालेन्द्र सिंह,** गुना

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

खतरे की आहट

राजस्थान में अशोक गहलोत ने बसपा के छह विधायकों को पार्टी में शामिल कर भाजपा की तुलना में ताकत बढ़ा रखी है। पर इन दिनों तख्ता पलट का नया खेल तो किसी को भी पलट सकता है। दल बदल के बजाय अब तो विधायकों से इस्तीफे दिलाने की नई तरकीब अपनाई जाने लगी है। गुटबाजी से तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार भी अछूती नहीं है। पर सियासत में आने से पहले जादूगरी करते रहे गहलोत असंतोष को मध्य प्रदेश की तरह सतह पर नहीं आने दे रहे। दूसरे उनके विरोधी सचिन पायलट ज्योतिरादित्य की तरह पैदल भी नहीं हैं। वे सूबे के उपमुख्यमंत्री यानी सरकार में नंबर दो तो हैं ही। भाजपा में जाना भी चाहेंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तो मिलने से रही। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र में कुछ विधायकों की नाराजगी साफ दिख रही थी। बसपा से आए छह विधायकों के अलावा 13 निर्दलीय भी गहलोत को राहत दे रहे हैं। यानी 200 के सदन में फिलहाल गहलोत को 118 का समर्थन है। सूबे की तीन राज्यसभा सीटों में से यहां कांग्रेस को दो मिल जाएंगी। भाजपा को एक सीट का घाटा होगा। गहलोत ने फिर पासा फेंका है कि वे जल्दी ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी करेंगे और मलाईदार पदों पर नियुक्तियां भी। अब देखना यह है कि उनका यह दाव कितना काम आता है।

भाजपा में क्षत्रपों की मजबूती

भाजपा में अब प्रादेशिक क्षत्रपों को एक रणनीति के तहत मजबूत किया जा रहा है। करीब छह साल पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भाजपा की कमान संभालने के बाद ऐसा लग रहा था कि राज्यों में पुराने सारे क्षत्रप नेता निपट जाएंगे और बिल्कुल नया नेतृत्व तैयार होगा, जो मोटे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व की कठपुतली की तरह होगा। पर अब यह कहानी पूरी तरह से पलट गई है। अब भाजपा राज्यों में अपने क्षत्रपों को मजबूत कर रही है। जैसे कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा हैं। पिछले साल येदियुरप्पा की भी फिर से सरकार में वापसी हुई। वहां भी भाजपा आलाकमान की पसंद कोई और नेता था। एक तो येदियुरप्पा की उम्र ज्यादा हो गई है और दूसरे उनके ऊपर कुछ मुकदमे भी हैं। इसके अलावा वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकालीन नेताओं में से हैं और उनका अपना मजबूत आधार है। वे प्रदेश की राजनीति के लिए केंद्रीय नेतृत्व के करिश्मे पर निर्भर नहीं हैं। उन्होंने अपने दम पर 2008 में पहली बार भाजपा की सरकार बनवाई थी। ध्यान रहे अब तक दक्षिण भारत में सिर्फ कर्नाटक में भाजपा सरकार बना पाई है और वह भी येदियुरप्पा की वजह से। ऐसे ही भाजपा ने झारखंड में बाबूलाल मरांडी की वापसी कराई है। मप्र में शिवराज की वापसी हुई है।

जावलकर से नाराज सतपाल

धर्मगुरु सतपाल महाराज के शिष्यों की संख्या करोड़ों में बताई जाती है। उनके प्रवचनों की भारी डिमांड न केवल भारत बल्कि विदेशी मुल्कों में भी रहती है। लेकिन राजनीति में सतपाल लगातार हाशिए में सिमटते जा रहे हैं। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए महाराज को उम्मीद थी कि भविष्य में वे ही भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाजपा ने अपने पुराने चावल त्रिवेंद्र की ताजपोशी कर डाली। मन काटकर महाराज को त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल में शामिल होना पड़ा। अब खबर है कि राज्य का पर्यटन मंत्रालय संभाल रहे सतपाल महाराज के आदेश उनके ही विभागीय अधिकारी नहीं सुन रहे। सरकार के विज्ञापनों और पोस्टर-बैनर आदि में महाराज को जगह नहीं दी जा रही है। 2021 में होने जा रहे कुंभ की तैयारियों में भी महाराज की कोई भूमिका तय नहीं की गई है। चर्चा जोरों पर है कि पिछले दिनों खफा हो महाराज ने अपने विभागीय सचिव दिलीप जालवकर की जमकर क्लास ली। खबर हालांकि यह भी है कि जावलकर ने मंत्रीजी को दो टूक कह डाला कि जब तक सीएम दफ्तर से आदेश नहीं मिलते वे उनकी फोटो विज्ञापन आदि में चस्पा नहीं कर पाएंगे।

भारी संकट के दौर में

देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारी संकट के दौर से गुजर रही है। हालात इतने खराब हैं कि जहां एक तरह पार्टी के छत्रप खुलेआम बगावत पर उतरे आए हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल भी कांग्रेस को भाव नहीं दे रहे। हरियाणा में पार्टी के दिग्गज नेता भूपिन्दर हुड्डा ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा को राज्यसभा भेजने के निर्णय का खुला विरोध कर अपने बेटे दिपिंदर हुड्डा को राज्यसभा प्रत्याशी बना डाला तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने खाली हो रही दो राज्यसभा सीटों में से एक सीट मांग रही कांग्रेस को साफ मना कर डाला। राजद ने दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर डाले हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस के राज्य प्रभारी आरपीएन सिंह को राज्यसभा भेजने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने अपने पिता शिबू सोरेन को राज्यसभा भेजने का फैसला ले लिया। तमिलनाडु में डीएमके ने भी कांग्रेस को दरकिनार कर दिया है। तो असम में आईआईयूडीएफ के बदरूदीन अजमल ने कांग्रेस को समर्थन देने से साफ इंकार कर दिया है।

केजरी के पद-चिन्हों पर ममता

दिल्ली की जनता ने नि:संदेह आम आदमी पार्टी को दोबारा से प्रचंड बहुमत सरकार की परफॉरमेंस पर दिया लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि परफॉरमेंस के साथ केजरीवाल का हिंदुत्व मॉडल भी इन चुनावों में पार्टी की जीत का एक बड़ा कारण रहा। केजरीवाल यकायक ही बड़े हनुमान भक्त बन भाजपा पर भारी पड़ गए। शाहीन बाग के मुद्दे पर वे खामोश रहे ताकि भाजपा चुनावों को हिंदू बनाम मुस्लिम न करा दे। अब खबर है कि पश्चिम बांगल की सीएम ममता भी अपना ट्रैक बदल रही हैं। इन दिनों राज्य का धुआंधार दौरा कर रहीं ममता ने मंदिरों में जाना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों उड़ीसा में आयोजित पूर्वोत्तर परिषद की बैठक के बाद ममता ने जगन्नाथ मंदिर जाकर भगवान के आगे शीश नवाया। हालांकि नागरिकता संशोधन कानून का ममता अब भी पुरजोर विरोध कर रही हैं। लेकिन हिंदू वोट बैंक को भी वे अब साधने में जुट गई हैं।

जमा होने लगी आंकड़ेबाजों की टीम

प्रदेश में सत्ता बदलते ही आंकड़ेबाज अफसरों की पौ बारह हो गई है। क्योंकि ऐसे अफसरों का एक बार फिर से सत्ता के केंद्र बिंदु में जमावड़ा होने लगा है। जिस तरह इन अफसरों का एक-एक करके जमावड़ा हो रहा है, उससे लोगों को अभी से डर लगने लगा है कि ये लोग सरकार की खटिया खड़ी न कर दें। यह डर इसलिए लग रहा है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान भी ऐसे अफसरों का जमावड़ा सत्ता के केंद्र बिंदु में था। ये अफसर मुख्यमंत्री को खुश रखने के लिए केवल आंकड़ेबाजी का खेल खेला करते थे। इस बार भी ऐसे अफसरों का एक ही जगह जमावड़ा होने लगा है। वहीं प्रशासन की कमान भी ऐसे ही एक साहब को मिल गई है, जो न किसी से मिलते हैं और न ही कुछ बोलते हैं। इनके अलावा अभी हाल ही में एक और अफसर को वहां पर पदस्थ किया गया है। ये जितने अधिकारी सत्ता के केंद्र में पदस्थ किए जा रहे हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो केवल कागजी घोड़े दौड़ाने में माहिर हैं। इनसे अफसर ही नहीं जनप्रतिनिधि भी परेशान होंगे, क्योंकि ये सभी लकीर के फकीर हैं। इससे प्रशासनिक व्यवस्था बेपटरी होने का भी डर अफसरों को सता रहा है। अब देखना यह है कि अफसरों का यह कुनबा मुख्यमंत्री को प्रसन्न रखने के लिए आंकड़ों का किस तरह का खेल खेलता है और इससे प्रदेश को क्या लाभ या हानि होती है।

जाते-जाते बचे आईजी

प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी में पदस्थ पुलिस के बड़े साहब के लिए नवागत डीआईजी भाग्यशाली साबित हुए हैं। दरअसल, पुराने डीआईजी के कारण आईजी साहब का भी बोरिया बिस्तर बंधने की तैयारी हो गई थी। पहले सरकार ने डीआईजी को चलता किया और उनकी जगह पूर्व में पदस्थ रहे साहब को पुनः डीआईजी बनाया गया। उसके बाद आईजी को बदलने की तैयारी चल रही थी, तभी यह बात सामने आई कि जिन पूर्व डीआईजी को आईजी बनाकर भेजने की तैयारी चल रही है उनका नए पदस्थ डीआईजी से छत्तीस का आंकड़ा है। फिर क्या था, सरकार को सलाह दी गई कि अगर दोनों अफसरों को एक ही जगह पदस्थ किया जाएगा तो इनकी आपसी लड़ाई से प्रशासनिक व्यवस्था और चरमरा जाएगी। वह भी कोरोना वायरस से ग्रसित इंदौर जैसे महत्वपूर्ण शहर में, अगर प्रशासनिक अधिकारियों के बीच मनमुटाव जैसी स्थिति रही तो सामंजस्य से काम नहीं हो पाएगा। इसलिए वर्तमान आईजी की पदस्थापना होते-होते बच गई। दरअसल, इंदौर इस समय कोरोना वायरस की चपेट में है। यहां स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई है। इसलिए सरकार ने पहले यहां के कलेक्टर और फिर डीआईजी को बदल दिया है।

चिट्ठी-पतरी से कट रहे दिन

कुछ समय पहले तक सरकार में व्यस्त रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री का दिन चिट्ठी-पतरी में कट रहा है। दरअसल, माननीय के हाथ से सत्ता जाने के बाद उनके पास कोई विशेष काम बचा नहीं है। वैसे तो वह सत्ता जाने के साथ ही दिल्ली कूच करना चाहते थे लेकिन कोरोना वायरस ने उनकी मंशा पर पानी फेर दिया। यही नहीं इस कारण पीसीसी का काम भी रुका हुआ है। ऐसे में वे करें तो क्या करें? उन्होंने चारा न देखते हुए भोपाल में ही डेरा डाल रखा है। लेकिन यहां उनके पास काम नहीं है। ऐसे में वे ट्विटर पर ट्वीट करके या फिर सरकार को चिट्ठी लिखकर उसे सुझाव देने और घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे बता दें सत्ता में रहते हुए भी उनका जनता से कोई सरोकार नहीं था। वे ट्वीट और पत्रों के माध्यम से ही जनता से चर्चा करते रहते थे। अब तो सत्ता भी नहीं है इसलिए वे बाहर निकलें भी तो कैसे? एक तो कोरोना वायरस ने सबको घर में समेटकर रख दिया है। उस पर अब उनके पास सत्ता वाला तामझाम भी नहीं रह गया है। सो वे केवल चिट्ठी-पतरी से दिन काट रहे हैं। यही हाल उनके तथाकथित सखा और पूर्ववर्ती सरकार के तथाकथित सुपर सीएम का भी है। अपने हाथों अपनी लुटिया डुबाने वाले ये माननीय भी आए दिन ट्वीट और चिट्ठी-पतरी लिखते रहते हैं। कभी-कभी तो इनकी चिट्ठियां इतनी लंबी हो जाती हैं कि लोग समझ जाते हैं कि इनके पास इसके अलावा और कोई काम नहीं है।

कोरोना ने बचाया

सत्ता बदलते ही प्रदेश के मैदानी इलाकों में पदस्थ अफसरों की रात की नींद हराम हो गई थी। लेकिन कोरोना वायरस के फैलान ने इन अफसरों को थोड़ी राहत दी है। दरअसल, पूर्ववर्ती सरकार में कई अफसरों ने गांधीजी के बलबूते अपने मनपसंद जिलों में कलेक्टरी और एसपी की कुर्सी हासिल की थी। इन अफसरों को खुली छूट दी गई थी कि कुर्सी पाने के लिए उन्होंने जितनी लक्ष्मी चढ़ाई है उसे सूद सहित वापस पाने के लिए मनमाफिक कमाई कर सकते हैं। लेकिन सत्ता बदलते ही ऐसे अफसरों के होश उड़ गए। उन्हें डर सताने लगा कि आज नहीं तो कल उनका तबादला कर दिया जाएगा। ये अफसर अपने तबादले की आस लगाए बैठे थे कि कोरोना वायरस का तेजी से फैलाव हुआ और उन्हें कुछ की राहत मिल गई, क्योंकि सरकार ऐसी स्थिति में तबादले के पक्ष में नहीं है। यही हाल परिवहन चौकियों पर तैनात अफसरों का भी है। कई अफसर तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आधी रकम भी नहीं निकाली है। अब देखना यह है कि कोरोना उन्हें कितने दिन तक राहत पहुंचाता है।

पुलिस अधिकारी का कब्जा

मप्र में भले ही सरकारें बदलती रहें, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली करीब-करीब एक जैसी ही रहती है। तभी तो एक सरकार की देखादेखी दूसरी सरकार वैसा ही करती है। इसका नजारा प्रदेश के जनसंपर्क एवं सूचना केंद्र में भी विगत कुछ सालों से देखने को मिल रहा है। तू डाल-डाल, मैं पात-पात की तर्ज पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में स्थित सूचना केंद्र की कमान एक राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी के हाथों सौंप दी। हालांकि मैडम अभी भी उस पद पर बैठी हैं। लेकिन संभावना जताई जा रही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा तैनात की गई उक्त महिला अधिकारी को जल्द ही चलता कर दिया जाएगा। सवाल उठता है कि आखिर पूर्ववर्ती सरकार ने मैडम के सूचना केंद्र की जिम्मेदारी देकर ऐसी कौन सी गलती की है कि वर्तमान सरकार उसमें बदलाव करेगी। ज्ञातव्य है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में भी भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी को जनसंपर्क का डायरेक्टर बनाया गया था। कांग्रेस ने उसी का अनुसरण ही तो किया है।

भारत के पास कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए असाधारण क्षमता है, क्योंकि उसके पास चेचक और पोलियो जैसी महामारी को खत्म करने का अनुभव है। ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत दुनिया को रास्ता दिखाए।

● **माइकल जे रेयान**

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस जिस बहाने के साथ छोड़ी है वह ठीक नहीं है। उन्होंने राजनीतिक मूल्यों का ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैंने जनता से जो वादे किए हैं उन्हें हर हाल में पूरा करूंगा। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैंने वादा किया था कि चुनाव जीतूं या हारूं, मैं उनकी सेवा करता रहूंगा। इसलिए मैं जनता की सेवा में लगा रहूंगा।

● **दिग्विजय सिंह**

भारत में कोरोना वायरस की स्थिति गंभीर है। प्रधानमंत्री ने हमें 21 दिन तक संभलकर रहने को कहा है। इसलिए हमें उनके निर्देशों का पालन करना होगा। मेरा अनुरोध है कि अगर हम सब एकजुट होकर इसका सामना करेंगे, कोरोना को हराएंगे, तब ही इससे बाहर आ पाएंगे। इसलिए आप सभी कृपा करके अपने घर में ही रहें।

● **सचिन तेंदुलकर**

टोक्यो ओलंपिक को स्थगित करना हमारी मजबूरी है। कोरोना वायरस जिस तरह खतरनाक बना हुआ है, उससे यह आयोजन कराना भी खतरनाक होता। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हमारी बात मानी है और ओलंपिक का आयोजन एक साल के लिए टाल दिया है।

● **शिंजो आबे**

जब मेरी बहन शमिता ने मोहब्बतें से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, तो मुझे हमेशा लगता था कि वह खूबसूरत और गोरी है, वह बेहतर ऐक्ट्रेस और डांसर है, तो मुझे तब ऐसा लगा था कि शमिता के आ जाने के बाद मुझे कोई काम नहीं देगा। यही नहीं जब शमिता पैदा हुई थी तो मैं बहुत असुरक्षित महसूस करती थी। क्योंकि मैं सांवली और शमिता गोरी थी। कभी-कभी मैं उसे चिकोटी काटकर रुला देती थी। यह मेरी जलन थी। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। मेरी बहन पर मुझे गर्व है। मैं चाहूंगी कि वह एक सफल अभिनेत्री बने।

● **शिल्पा शेट्टी**

वाक्युद्ध

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से लड़ने के लिए 50 मिनट तो भाषण दे दिया, लेकिन रोज कमाने-खाने वालों की रोजी-रोटी के लिए एक शब्द नहीं कहा। 21 दिन ये अपने परिवारों का पेट कैसे पालेंगे। सरकार को इस स्थिति में न्यूनतम आय योजना को लागू करना चाहिए। यह योजना वक्त की मांग है।

● **रणदीप सिंह सुरजेवाला**

इस संकट की घड़ी में भी कांग्रेस को राजनीति ही नजर आ रही है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया है तो सरकार ने लोगों के लिए कुछ न कुछ सोचा ही होगा। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने 15 हजार करोड़ रुपए दिए हैं और आगे भी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

● **मनोज तिवारी**

15 साल बाद कांग्रेस को मिली सत्ता 15 माह में ही हाथ से निकल गई। दरअसल, इसके लिए स्वयं कांग्रेसी जिम्मेदार हैं। कुछ नेताओं की चालाकी से हाथ आया मौका निकल गया।

अब खिसियाए होए क्या...

ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग से कांग्रेस सरकार गिरा देने वाले शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर कामकाज शुरू भी कर दिया है और उधर कांग्रेसी खासतौर से दिग्विजय सिंह खिसियाए हुए सिंधिया को कोसे जा रहे हैं। यह देखा जाए तो एक बुजुर्ग नेता का बेवजह का प्रलाप है जिस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। प्रदेश में दिग्गी राजा के उपनाम से मशहूर दिग्विजय सिंह देखा जाए तो इस बार खुद ही अपनी **चालाकी और खुराफात** का शिकार होकर रह गए हैं। उनके किए की सजा खुद उनका गुट भी भुगत रहा है। उनके समर्थक मंत्री जो कल तक जमीन रौंदते चलते थे अब घरों में दुबके अपने इर्द-गिर्द जमा 2-4 लोगों की भीड़ को अपने मंत्रित्वकाल के संस्मरण सुनकर गम गलत कर रहे हैं। जो हुआ उसके जिम्मेदार क्या **अकेले दिग्विजय** हैं इस सवाल का जवाब हां में ही निकलता है। उनका बैर सिंधिया से था जिसे भुनाने उन्होंने टंगड़ी राज्यसभा चुनाव को लेकर अड़ाई थी कि प्रथम वरीयता में मैं ही जाऊंगा। अनदेखी के शिकार चल रहे सिंधिया को यह गंवारा नहीं था लिहाजा उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वॉइन कर ली और अपने समर्थक 22 विधायकों को भी भगवा खेमे के नीचे ले गए।

अब कारवां गुजर जाने के बाद भी दिग्विजय का रोना-गाना जारी है कि मंत्री पद और राज्यसभा में जाने के लालच में सिंधिया ने कांग्रेस की बुरी गत कर दी इसके लिए प्रदेश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। अब यह कौन उन्हें समझाए कि प्रदेश की जनता को न तो उनसे और न ही कांग्रेस से कोई वास्ता या लगाव है। होता तो यह नौबत ही न आती और 2018 के चुनाव में कांग्रेस को वोटर 114 के आंकड़े पर लटकाकर नहीं रखता। तकनीकी तौर पर देखें तो जनता ने बेहद सटीक फैसला लिया था जिसके माने और मैसेज यह था कि तीन गुटों में बंटी कांग्रेस को अगर वाकई जनता का भला करना है तो वह अपनी अंदरूनी कलह को नियंत्रित करे नहीं तो भाजपा एक बेहतर विकल्प है ही जिसे 109 सीटें मिली थीं और कुल वोट भी कांग्रेस से ज्यादा मिले थे। सवा साल में ही कांग्रेसी लड़ पड़े और सरकार चली गई। कमलनाथ ने वहैसियत मुख्यमंत्री शुरुआत तो जोरदार की थी लेकिन धीरे-धीरे वे दिग्विजय के जाल में फंसते चले गए और उनके बहकावे में आकर सिंधिया के बारे में यह राय कायम कर ली कि जो आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद चाह रहा है वो कल को सीएम की कुर्सी भी मांग सकता है। कमलनाथ और सिंधिया के बीच दिग्विजय ने मंथरा का काम तो कर डाला लेकिन एक जगह गच्चा खा गए। इस जगह उनका यह अंदाजा था कि सिंधिया कांग्रेस में रहते अनदेखी और बेइज्जती बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन किसी भी कीमत पर भाजपा में नहीं जाएंगे। अब नजारा यह है कि सिंधिया शिवराज के गले में हाथ डाले घूम रहे हैं और कमलनाथ-दिग्विजय सोच ही रहे हैं कि प्लानिंग में कहां कमी रह गई।

सिंधिया का कद और पूछ-परख भाजपा में जाने से बढ़े ही हैं, यह देख भी इन बुजुर्गों के कलेजों पर नाना प्रकार के सांप लोट रहे हैं जिसमें घी उनकी अब कुछ न कर पाने की असमर्थता डाल रही है। सिंधिया को कोस कर इन्हें आत्मिक शांति तो मिल रही है लेकिन समर्थन नहीं मिल रहा। दिग्विजय सिंह जमीनी नेता कभी नहीं रहे, साल 1993 में मुख्यमंत्री पद के दौड़ में वे कहीं नहीं थे लेकिन अपने राजनैतिक गुरु अर्जुन सिंह की कृपा से सीएम बन गए थे। 1998 का चुनाव भी अर्जुन सिंह की ही वजह से कांग्रेस जीती थी। 2003 में महज 38 सीटों पर कांग्रेस सिमटी थी तो इसकी वजह दिग्विजय सिंह का कुशासन ही था ।

राहुल गांधी को यह बात समझ आ गई थी कि दिग्विजय की इमेज अब 25 सीटें जिताने के काबिल भी नहीं रह गई है इसलिए उन्होंने 2018 में दिग्विजय को बेरहमी से धकिया दिया था और कमलनाथ-सिंधिया को आगे कर जीत हासिल की थी। सार्वजनिक सभाओं में तो राहुल दिग्विजय सिंह की तरफ देखते भी नहीं थे। दिग्विजय सिंह अपनी इस बेइज्जती को भूले नहीं और उन्होंने सिंधिया और कमलनाथ के बीच की खाई को और गहरा कर अपनी खुन्नस निकाल भी ली। एक और निर्गुट कांग्रेसी विधायक के मुताबिक अब लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं। **सिंधिया को कोसना उन्हें और ज्यादा प्रचार देना और लोकप्रिय बनाना है।** कमलनाथ और दिग्विजय को गंभीरता से इस बात पर विचार करते रणनीति बनानी चाहिए कि अब उनका मुकाबला कांग्रेस वाले सिंधिया से न होकर भाजपा वाले सिंधिया से है।

● **सुनील सिंह**

भरोसा खोते दिग्विजय

दिग्विजय सिंह पर अब कोई भरोसा नहीं कर रहा जिनके बारे में मजाक में नहीं बल्कि गंभीरता से यह कहा जाने लगा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे दिग्विजय ने ठगा नहीं। इस कहावत में दम लाने अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह का उदाहरण खुद कुछ कांग्रेसी देते हैं कि दिग्विजय ने उन्हें ही नहीं बख्शा और अब तो खुद उनके बेटे जयवर्धन सिंह का भविष्य भी खतरे में पड़ गया है। कमलनाथ तो नए उदाहरण हैं ही। कमलनाथ गुट के कुछ लोग दिग्विजय की फितरत को समझते उनसे दूरी बनाने लगे हैं। कमलनाथ समर्थक एक पूर्व मंत्री ने इस प्रतिनिधि से नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा, अब कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस की बागडोर संभालेंगे लेकिन वे सफल हों इसके लिए जरूरी है कि दिग्विजय सिंह को दूर रखा जाए। बेहतर तो यह होगा कि उनके टूटते गुट का विलय हमारे गुट में हो जाए। ऐसा कैसे होगा, इस सवाल पर मंत्री ने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि इसके लिए जरूरी है कि दिग्विजय सिंह को राज्यसभा में जाने से रोका जाए। इसके लिए भी जरूरी यह है कि कमलनाथ खेमे के कुछ विधायक जोखिम उठाते हुए प्रथम वरीयता वोट कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार फूल सिंह बरैया को करें जिन्हें दिग्विजय सिंह के कहने पर ही खड़ा किया गया है। मंत्री के मुताबिक कभी बसपा के प्रमुख रहे बरैया दलित हैं और ग्वालियर चंबल संभाग के ही हैं। उनके राज्यसभा में जाने से दलित वोटों का झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ेगा और सिंधिया का प्रभाव यहां कम होगा।

सोनिया, राहुल और प्रियंका के बाद गांधी परिवार के चौथे सदस्य के रूप में जाने जाते थे सिंधिया। सिंधिया के लिए भाजपा में जाना मजबूरी हो सकती है लेकिन भाजपा के लिए ऐसी कोई मजबूरी नहीं, दिग्विजय और कमलनाथ ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि महाराज साहब को कांग्रेस में घुटन मसहूस होने लगी थी।

सिंधिया को भाजपा में मिलेगी तवज्जो?

कांग्रेस को 18 साल देने वाले ग्वालियर के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भाजपा के हो चुके हैं। राजमाता के बाद वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे पहले से ही भाजपा में हैं। वहीं ज्योतिरादित्य यानि महाराज भी अब भाजपा की आवाज को बुलंद करेंगे। लेकिन क्या भाजपा में सिंधिया की महत्वाकांक्षाओं को सम्मान मिलेगा? वहीं सवाल यह भी उठता है कि ऐसा भी क्या हुआ जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा का दामन थामने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे जुड़े दो बड़े पहलुओं को समझा जाना जरूरी है। पहला पहलू कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी से जुड़ा है तो दूसरा सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कमजोरियों से। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के एकमात्र ऐसे नेता थे जिनकी गांधी परिवार में बिना रोक-टोक एंट्री थी। एक अर्थ में वो सोनिया, राहुल और प्रियंका के बाद गांधी **परिवार के चौथे सदस्य के रूप में जाने जाते थे।** कांग्रेस में इतनी मजबूत स्थिति में होने के बाद भी ज्योतिरादित्य घुटन महसूस कर रहे थे। उनकी घुटन का कारण मध्यप्रदेश की सियासत के दो बड़े और पुराने चेहरे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ रहे। दोनों की जोड़ी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि महाराज साहब को अपने ही मध्य प्रदेश और कांग्रेस में घुटन महसूस होने लग गई।

अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ राज्यसभा में जाने को लेकर ज्योतिरादित्य इतने अधीर हो गए थे कि उन्होंने अपनी मातृ पार्टी को नमस्ते कह दिया। यहां तक कि वो अपने प्रिय सखा राहुल गांधी से भी मिलने नहीं गए। सिंधिया ने तो इतना तक कह दिया कि उन्होंने समय मांगा था लेकिन गांधी परिवार से उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया। अगर ऐसा रहा है तो फिर वाकई सिंधिया का कांग्रेस में कोई खास महत्व नहीं बचा था, लेकिन क्या भाजपा में सिंधिया की महत्वाकांक्षाओं को सम्मान मिलेगा?

नहीं, ऐसा लगता नहीं है, सिंधिया के लिए भाजपा में जाना मजबूरी हो सकती है लेकिन भाजपा के लिए ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि वो सिंधिया की शर्तों को ज्यों का त्यों माने। हां, सिधिंया को भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति में मौका जरूर मिल सकता है। राज्यसभा के बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया जा सकता है लेकिन यह सिंधिया के लिए कोई नई बात नहीं है। वो चार बार सांसद रहने के साथ कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनके जीवन के लिए यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। दूसरी बात भाजपा में समर्पित नेताओं की लंबी फेहरिस्त है, जो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। इन नेताओं को साइड में करके कोई भी भाजपा में अपना स्थान नहीं बना सकता। यह तो जग जाहिर है कि भाजपा अपने महत्वपूर्ण दायित्व संघ पृष्ठभूमि के नेताओं को ही सौंपती है।

ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को तत्कालिक सियासी फायदा तो भाजपा से मिल सकता है, लेकिन लंबे समय में ज्योतिरादित्य को भाजपा में बड़ा मुकाम मिलना मुश्किल है। खुद सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे मध्य प्रदेश में भाजपा की नेता हैं लेकिन बड़ी भूमिका में नहीं है। वहीं उनकी एक और बुआ वसुंधरा राजे दो बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रहने के बाद भी भाजपा में जिन पस्थितियों से गुजर रही हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। वसुंधरा के कहने से न तो राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष तय हुआ और न ही संगठन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का उन्हें मौका मिल पा रहा है। असल में कांग्रेस और भाजपा की राजनीतिक पृष्ठभूमि में बड़ा भारी अंतर है। कांग्रेस का कमजोर दौर चल रहा है इसलिए कोई भी नेतृत्व को आंखे दिखा सकता है या फिर पार्टी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे सकता है। वहीं भाजपा का दौर सुदृढ़ चल रहा है। इस समय भाजपा किसी भी दूसरी पार्टी के मुकाबले बहुत मजबूत स्थिति में है। यही कारण है कि वसुंधरा राजे को खामोशी के साथ केंद्रीय नेतृत्व के निर्णयों के अनुसार चलना पड़ रहा है।

सिंधिया का सरकार में दिखने लगा असर

मध्यप्रदेश में इतिहास खुद को दोहरा रहा है। करीब 52 वर्ष पहले द्वारिका प्रसाद मिश्र की कांग्रेसी सरकार गिराने के बाद राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने गोविंद नारायण सिंह की सरकार में जिस तरह अपना असर कायम किया, अब शिवराज सरकार में वही असर राजामाता के पौत्र व पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिखने लगा है। शुरुआत सिंधिया के पसंदीदा अफसर की तैनाती से हुई है और यह संकेत हैं कि उनके इलाकों में उनकी मर्जी के ही अफसर तैनात होंगे। कमलनाथ ने सिंधिया से तकरार बढ़ने के बाद उनके चहेते अफसर ग्वालियर नगर निगम के आयुक्त संदीप माकिन को हटा दिया था। शिवराज सरकार ने संदीप को फिर ग्वालियर में ही तैनाती दे दी है। इसके अलावा सिंधिया के खिलाफ चल रही आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) जांच का नेतृत्व करने वाले प्रभारी डीजी सुशोभन बनर्जी को भी हटाकर साइड लाइन करते हुए सागर भेज दिया गया है। कमलनाथ सरकार ने सत्ता का संग्राम शुरू होते ही ग्वालियर और गुना के कलेक्टर को भी हटा दिया था।

अगर भाजपा में सिंधिया की हैसियत का आंकलन करें तो सबसे पहले उन्हें मप्र के दिग्गज नेताओं से पार पाना होगा। इन नेताओं में नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, प्रभात झा, जयभान सिंह पवैया, नरोत्तम मिश्रा, यशोधरा राजे सिंधिया प्रमुख हैं। नरेंद्र सिंह तोमर मध्यप्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। तोमर ग्वालियर चंबल संभाग के दिग्गज नेता हैं। सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव राज्य के इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। अभी तक तोमर ही इस क्षेत्र से भाजपा के बड़े नेता रहे हैं। भाजपा की ओर से कभी सीएम पद के दावेदार और अन्य मामलों में तोमर का नाम ही सबसे आगे रहता है। तोमर के वैसे सिंधिया परिवार से अच्छे और करीबी रिश्ते भी रहे हैं। लेकिन अब जब सिंधिया भाजपा में शामिल हो गए हैं तब ऐसा माना जा रहा है कि यहां के समीकरण तेजी से बदलेंगे। दोनों नेता एक-दूसरे के सामने चुनौती बनकर उभरेंगे। दोनों नेताओं के बीच अपने समर्थकों को तवज्जो देने की गुटबाजी चलती रहेगी।

मध्यप्रदेश में भाजपा का फिलहाल सबसे बड़ा चेहरा शिवराज सिंह चौहान ही हैं। जिन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन सिंधिया के पार्टी में शामिल होने के बाद उनकी लोकप्रियता में कमी आ सकती है। सिंधिया जनता के बीच सक्रिय हैं और युवाओं में उनका अच्छा क्रेज है। इस कारण शिवराज और सिंधिया एक-दूसरे लिए चुनौती साबित होंगे। पिछले चुनावों में भाजपा ने यह नारा भी दिया था कि माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। लेकिन अब मध्यप्रदेश की सियासत में कई मायने बदलते हुए नजर आएंगे। प्रभात झा भी मध्यप्रदेश भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। झा की भाजपा के साथ-साथ संघ में अच्छी खासी पकड़ है। झा जब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थे तब से लेकर अब तक लगातार कांग्रेस और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोलते रहे हैं। झा ने कई बार सिंधिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से लेकर सियासी हमले तक किए, लेकिन सिंधिया ने कभी भी प्रभात झा को अपने कद का नेता नहीं माना। वहीं कभी उनके हमलों का जवाब देना तक उचित नहीं समझा। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री

जयभान सिंह पवैया और ज्योतिरादित्य सिंधिया की लड़ाई मध्यप्रदेश के राजनीतिक गलियारों में जगजाहिर है। पवैया की प्रदेश में राजनीति केवल सिंधिया के विरोध पर टिकी रही है। पवैया ने पहले माधवराव सिंधिया का विरोध किया, फिर उनकी मृत्यु के बाद ज्योतिरादित्य का खुलेआम विरोध करने लगे। राज्य की सियायत में सिंधिया को लेकर सबसे ज्यादा विरोधी बोल पवैया ने ही बोले हैं। लेकिन सिंधिया ने आज तक पवैया के आरोप का जवाब देना तक उचित नहीं समझा। पवैया ग्वालियर से ही आते हैं। वे 1998 के लोकसभा चुनाव में माधवराव सिंधिया और 2004 के लोकसभा चुनाव में गुना लोकसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चुनौती दे चुके हैं। लेकिन दोनों ही चुनावों में पवैया को हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन अब जब सिंधिया ने भाजपा का दामन थाम लिया है तो पवैया के सामने भी उनके अस्तित्व को लेकर संकट होगा। वहीं सिंधिया को भी उनके साथ तालमेल बैठाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा।

नरोत्तम मिश्रा का कद भारतीय जनता पार्टी में पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ा है। ग्वालियर चंबल में नरेंद्र सिंह तोमर के बाद नरोत्तम मिश्रा का नाम दूसरे नंबर पर आता है। शिवराज सरकार में कई अहम मंत्री पदों पर रहे नरोत्तम मिश्रा सिंधिया के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी पकड़ रखते है। इसके अलावा दिल्ली हाइकमान और प्रदेश के सभी बड़े नेताओं से उनके अच्छे संबंध जगजाहिर हैं। नरोत्तम के ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ-साथ उनकी दोनों बुआ यशोधरा राजे सिंधिया और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया से भी बेहद मधुर संबंध हैं। दतिया स्थित मां पीताम्बरा शक्ति पीठ भी नरोत्तम मिश्रा के निर्वाचन क्षेत्र में ही आता है। यहां आए दिन पूजा और हवन के लिए राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सिंधिया परिवार के लोग आते-जाते रहते हैं। सिंधिया की भाजपा में एंट्री नरोत्तम मिश्रा के बढ़ते कद को कम कर सकती है। वह सिंधिया अब ग्वालियर चंबल के भाजपा के बड़े नेता हो जाएंगे।

पूर्व मंत्री और यशोधराराजे सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया की छोटी बुआ हैं। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भाजपा में शामिल होने के लिए चला था तब यशोधरा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा, 'मुझे खुशी है और मैं उन्हें बधाई देती हूं। यह घर वापसी है। माधवराव सिंधिया ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जनसंघ से की थी। ज्योतिरादित्य की कांग्रेस में उपेक्षा की जा रही थी।' सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद यशोधराराजे के कद पर भी असर पड़ेगा। ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया घराने में पहला नाम ज्योतिरादित्य का हो जाएगा। इसका सीधा असर यशोधरा के राजनीतिक रसूख से लेकर पार्टी में महत्व तक में पड़ेगा।

● **अरूण दीक्षित**

कांग्रेस मानती है कि कभी न कभी होगा भूल का एहसास

कांग्रेस में भी लोग इस इंतजार में हैं कि सिंधिया को अपनी 'भूल' का मलाल हो। पार्टी छोड़ भाजपा में इज्जत और पद पाने की उनकी कोशिश पर कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार ट्वीट कर तंज कस रहे हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया को-ऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत सम्मान दिया। आज उनके भाजपा प्रवेश से ही पता चल गया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ही नदारद थे। उन्होंने भाजपा में जाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। यह सभी नेता उन्हें पचा नहीं पाएंगे और सहन नहीं कर पाएंगे। 'सिंधिया के सामने मध्यप्रदेश के दिग्गज नेताओं में असंतोष बढ़ेगा ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। लेकिन भाजपा इसे सिरे से खारिज कर रही है। भाजपा का कहना है कि पार्टी में गुटबाजी के लिए कोई स्थान नहीं है। वे आगे कहते हैं, 'भारतीय जनता पार्टी में कद कम होने और ज्यादा होने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। जिसे जो काम मिला है वह उसका कद है। कद का मापदंड भाजपा में नहीं है। उनके साथ आने से ग्वालियर चंबल संभाग में ओर तेजी आएगी।'

भूखे न रह जाएं बच्चे?

म प्र में नोवेल कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए 14 मार्च से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। बच्चों को पोषण देने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने 17 मार्च को एक आदेश में बच्चों को टेक होम राशन जारी रखने के आदेश दिए, लेकिन जमीन पर इस आदेश का अमल होता नहीं दिख रहा है। इससे पहले सत्ता को लेकर चले खेल की वजह से इस पर निर्णय नहीं लिया जा सका था।

शिवपुरी जिले के सामाजिक कार्यकर्ता अजय सिंह यादव बताते हैं कि उनके इलाके में दिसंबर 2019 से टेक होम राशन की आपूर्ति नहीं हुई जिससे बच्चों तक पोषण आहार नहीं पहुंचाया जा रहा है। इस जिले का पोहरी सहरिया आदिवासी बाहुल्य विकासखंड है, जहां लंबे समय तक कुपोषण के कारण बच्चों की मृत्यु के मामले दर्ज होते रहे हैं। पन्ना जिले के सामाजिक कार्यकर्ता युसूफ बेग ने बताया कि कुछ आंगनबाडी केंद्रों में पिछले दिनों टेक होम राशन बंटा, किंतु दो हफ्तों से गरम पका हुआ पोषण आहार बंद कर दिया गया है। 3 से 6 साल के बच्चों को टेक होम राशन नहीं दिया जा रहा है। निवाड़ी जिले के सामाजिक कार्यकर्ता मस्तराम सिंह घोष ने बताया कि **शासन** के निर्देशानुसार सभी हितग्राहियों को टेक होम राशन दिए जाने की व्यवस्था नहीं बन पाई है। इसी तरह की स्थिति उमरिया, सतना और रीवा जिले में भी है जहां टेक होम राशन नहीं बांटा जा सका है। ये सभी सामाजिक कार्यकर्ता भोजन के अधिकार अभियान से जुड़े हैं और अपने इलाकों में पोषण को लेकर काम करते हैं।

मध्यप्रदेश में काम कर रही संस्था भोजन के अधिकार अभियान ने पोषण आहार बांटने की जमीनी हकीकत को सरकार के साथ साझा किया है। भोजन के अधिकार अभियान के सचिन कुमार जैन ने कहा है कि संक्रमण से लड़ने के लिए खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना भी सबसे बड़ी जरूरत है, इसमें स्थानीय लोगों, स्वसहायता समूहों को शामिल नहीं किया गया है। जबकि इस वक्त वह भी अपनी सामाजिक भूमिका निभा सकते हैं। मध्यप्रदेश में 42.8 प्रतिशत बच्चे कम वजन के हैं और 42 प्रतिशत बच्चे स्टंटिंग कुपोषण से प्रभावित हैं। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि 9 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे अति गंभीर कुपोषण के शिकार हैं और 56 प्रतिशत महिलाएं खून की कमी की शिकार हैं। प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से संक्रमण का बहुत गहरा असर पड़ता है। कोरोना कोविड-19 से निपटने की नीति बनाते समय बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की जरूरत है। मध्यप्रदेश में 97,135 आंगनबाडी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिनमें शामिल 89,70,403 हितग्राहियों को पोषण आहार दिया जाना है। पोषण आहार पाने वाले बच्चों में 6 माह से 3 वर्ष तक के 34,37,973 बच्चे और 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के 38,54,035 बच्चे शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में इस वक्त 7,49,815 गर्भवती महिलाएं हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त नरेश पाल से टेक होम राशन की आपूर्ति को लेकर जानकारी लेनी चाही लेकिन वो जानकारी देने के लिए उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, मध्यप्रदेश के स्कूल में भी पिछले 10 दिनों से मिड-डे मील नहीं दिया जा रहा है। हालांकि, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि कुल 65 लाख 91 हजार विद्यार्थियों के खाते में मध्यान्ह भोजन के लिए 156 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि भेजी जाएगी।

नोवेल कोरोना वायरस की महामारी को फैलने से रोकने के लिए मध्यप्रदेश में भी देशभर की तरह लॉकडाउन का आव्हान किया गया है। यहां कई प्रमुख शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसे में आम लोगों को खाने-पीने से लेकर चिकित्सकों को इलाज के उपकरणों की समस्या भी सामने आ रही है। ग्रामीण इलाकों तक सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों के पास सुरक्षा के पर्याप्त उपकरण नहीं हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश के 40 से अधिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक अभियान 'आम इंसान की सुरक्षा में सरकार की जिम्मेदारी तय करने की एक मुहिम' चलाई है। इन कार्यकर्ताओं में मेधा पाटकर, सचिन कुमार जैन, अनिल सद्गोपाल, राकेश दीवान जैसे कई नाम शामिल हैं। संगठनों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस आपदा से प्रभावी रूप से निपटने के लिए कुछ सलाह दी है। पत्र में लिखा है कि नोवेल कोरोना वायरस का प्रकोप आने वाले चार से 8 हफ्तों में और भी विकराल हो जाएगा। हमारे देश के ज्यादातर लोगों की सामाजिक-आर्थिक हालत और सार्वजनिक व्यवस्थाओं की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह जरूरी है कि सरकार द्वारा हर स्तर पर कुछ बुनियादी फैसले लेकर सामाजिक-आर्थिक असुरक्षाओं से बचाया जाए।

● **विशाल गर्ग**

पत्र में खाद्य सुरक्षा की भी मांग

इस पत्र में सार्वजनिक स्थानों की साफ-सफाई के साथ निजी साफ-सफाई के लिए वंचित वर्गों के लिए साबुन, पानी, सेनिटाइजर के पर्याप्त उपलब्धता की मांग की गई है। पत्र में लिखा है कि निम्न आय वर्ग की बस्तियों या ग्रामीण टोलों के दलित, आदिवासी, विमुक्त जनजातियों, अल्पसंख्यकों, किसानों, खेतिहर मजदूरों, दिहाड़ी मजदूरों, वृद्धाश्रमों, ट्रांसजेंडर समुदाय और दूसरे ऐसे वंचित समुदायों को जरूरी राशन (चावल, दाल, आटा, तेल, नमक, मसाले, आलू, प्याज, दूध व अन्य सामग्री), प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयां (विटामिन सी, मल्टीविटामिन आदि) और सफाई की सामग्री (साबुन आदि) का वितरण किया जाए। छह साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, किशोरियों, बुजुर्गों और अन्य प्रकार के संवेदनशील श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों के पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर खास ध्यान रखा जाए। पत्र में आशंका जताई गई है कि कोरोना वायरस की आपदा अभी लंबे समय तक रह सकती है, इसे देखते हुए गरीबी रेखा से ऊपर रह रहे परिवारों को भी जरूरी राशन आदि मुहैया कराने के इंतजाम किए जाएं।

निर्माण कार्यों में लगे मजदूर, रेहड़ी-पटरी, खोमचे और रिक्शा चलाने वाले श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग है जो रोज कमाता है और रोज परिवार का पेट भरता है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के बाद ऐसे लाखों दिहाड़ी मजदूरों के समक्ष रोजीरोटी का संकट खड़ा हो गया है।

इनकी कौन लेगा सुध

कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी दुनिया त्राहि-त्राहि कर रही है। देश में भी कोहराम मचा हुआ है। उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। इस कारण बड़ी संख्या में मजदूर शहरों से गांवों में पहुंच गए हैं। लेकिन इन मजदूरों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। एक तरफ प्रदेश सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए कारगर कदम उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ शहरों में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए बकायदा अफसरों की टीम बनाकर मॉनीटरिंग की जा रही है। लेकिन गांवों की ओर किसी का ध्यान नहीं है। सबसे हैरानी की बात यह है कि प्रदेश के आसपास के राज्यों में कोरोना की दहशत फैलते ही ये मजदूर गांव तो पहुंच गए लेकिन इनकी जांच तक नहीं हो पाई।

सरकार ने कोरोना को लेकर शहरों पर पूरा फोकस कर रखा है। सभी संसाधन शहरी क्षेत्र में पीड़ित और संदिग्धों की जांच में लगे हैं, जबकि गांवों में लाखों की संख्या में मजदूर दूसरे राज्य और बड़े शहरों से बिना जांच के वापस गांव लौट रहे हैं। फिलहाल गांवों में हालत से निपटने के लिए सरकार के पास कोई प्लान नहीं है।

प्रदेश के करीब 54 हजार गांवों में करीब साढ़े पांच करोड़ की आबादी बसती है। इस आबादी में गरीब, मजदूर की बड़ी संख्या है। साथ ही गांवों में पढ़े-लिखे बेराजगारों की बड़ी संख्या है। जो रोजगार के लिए बड़े शहर या दूसरे राज्यों में कंपनी, होटल, मॉल, दुकान आदि में नौकरी करते हैं। साथ ही हाईराइज बिल्डिंग, सड़क, भवन निर्माण से जुड़े कार्यों में मजदूरी करते हैं। कोरोना के चलते 14 अप्रैल तक देश लॉकडाउन होने के बाद शहरों में सभी निर्माण कार्य, मॉल, होटल, दुकान बंद हैं। ऐसे में ज्यादातर बेरोजगार युवा, मजदूर अपने गांव लौट रहे हैं। सड़क एवं रेल यातायात बंद होने की स्थिति में मजदूर पैदल या फिर ट्रैक्टर-ट्रॉली से प्रदेश, जिले के बॉर्डर तक आ रहे हैं। हाल ही में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा के बड़े शहरों से मजदूर अपने गांव लौटे हैं। खास बात यह है कि इनकी अभी तक किसी तरह की मेडिकल जांच नहीं हुई है। अभी तक प्रदेश सरकार की गांवों में मेडिकल परीक्षण की कोई तैयारी नहीं है।

जिन राज्यों से मप्र के मजदूर वापस लौटे हैं, उनमें कोरोना वायरस का प्रभाव ज्यादा है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में कोरोना पीड़ित मिले हैं। मप्र के मजदूर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र में मजदूरी के लिए जाते हैं। इन शहरों से मजदूरों के आने से गांवों के बाशिंदों की चिंता बढ़ गई है। खासकर आदिवासी जिलों में तो सबसे अधिक चिंता देखी जा रही है। ये चिंताएं इसलिए भी ज्यादा हो गई हैं, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य जिलों से हजारों लोग अन्य राज्यों में मजूदरी या अन्य काम करते हैं, जो अब कोरोना के खौफ से वापस लौटने लगे हैं। आदिवासी बहुल जिला श्योपुर में अभी तक ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, लिहाजा बाहर से आने वाले मजदूर बिना जांच के ही सीधे अपने गांव और कस्बों में समुदाय के बीच पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी जिले में कोरोना का कोई पॉजीटिव या संदिग्ध मरीज नहीं मिला है, लेकिन श्योपुर के पड़ोसी मुरैना जिले में इस तरह का प्रकरण सामने आने के बाद अब लोग चिंतित हैं। प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य और पिछड़े जिले श्योपुर के हजारों लोग अन्य राज्यों में काम करते हैं। इनमें कराहल, वीरपुर और विजयपुर तहसील क्षेत्रों के हजारों लोग गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और केरल जैसे राज्यों में विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। इनमें अधिकांश लोग मजदूरी कार्य में हैं, लेकिन बढ़ते कोरोना के प्रभाव के चलते ये लोग अब इन राज्यों से वापस श्योपुर की ओर रुख कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश तो आदिवासी समाज के लोग हैं, जिनमें जागरुकता और शिक्षा का अभाव है। ऐसे में श्योपुर में प्रवेश करते वक्त ही इनकी स्क्रीनिंग नहीं होने से चिंताएं और बढ़ जाती है। यही वजह है कि सोशल मीडिया सहित जनप्रतिनिधियों द्वारा भी अब बाहर से आने वाले मजदूरों की जांच के लिए प्रक्रिया शुरू करने की मांग उठ रही है।

● **अरविंद नारद**

निजी सेक्टर बंद, घर लौटे युवा

देश व्यापी लॉकडाउन से पहले दक्षिण भारतीय राज्यों के कई जिलों में लॉकडाउन कर दिया था। इसके बाद उन राज्यों के बड़े शहर, दिल्ली, मुंबई, चैन्नई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों आईटी, बैंकिंग एवं अन्य निजी सेक्टरों में काम करने वाले युवा अपने गृह नगर लौट आए हैं। इनमें से भी ज्यादातर का मेडिकल परीक्षण नहीं हुआ है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर आज पूरा देश चिंतित है। वहीं इस वायरस के संक्रमण को लेकर छोटे-छोटे रेलवे स्टेशनों से लगे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। क्योंकि बीते एक सप्ताह के दौरान देश के बड़े-बड़े महानगरों में काम करने वाले लोग वापस अपने गांव आए हुए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि छोटे-छोटे स्टेशनों पर कोरोना के संक्रमण की जांच की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण यह मजदूर बिना कोई जांच के ही घरों में पहुंच गए हैं। इनमें ज्यादातर दिल्ली, गुडगांव, नोएडा, पुणे, गुजरात, हरियाणा से आए लोग शामिल हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जिन राज्यों से ये मजदूर वापस आए हैं उन राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। ऐसे में इन मजदूरों की जांच होना भी अनिवार्य है।

लॉकडाउन है सिर्फ जुगाड़!

कोरोना वायरस पूरी दुनिया में खौफ का दूसरा रूप बन गया है। भारत में भी कोरोना वायरस के नए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज सामने नहीं आया है। भारत में इस बीमारी को रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है। 14 अप्रैल तक पूरे देश में लॉकडाउन है। इससे देश में स्थिति नियंत्रण में है लेकिन यह इस वायरस से बचने का बस जुगाड़ भर है। भारत सहित पूरे विश्व को इस वायरस से बचने के लिए कोई कारगर दवाई या टीका खोजना होगा। वरना यह महामारी स्पेनिश फ्लू से भी खतरनाक हो जाएगी।

कोरोना यानि 1000 गुना जुकाम। यह जुकाम इतना भयानक होता है कि निमोनिया में तबदील हो जाता है। अगर इसका समय पर इलाज नहीं होता है तो पीड़ित की मौत हो जाती है। इस समय पूरी दुनिया इसी कोरोना वायरस की चपेट में है। पूरे विश्व में 7 लाख से अधिक लोग इस महामारी की चपेट में आए हैं। इनमें से 33,993 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में 1300 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि 45 की मौत हो चुकी है। भारत में वायरस का पहला केस वुहान से 31 जनवरी को केरल में आया था। तब से मध्य मार्च तक पूरे भारत में वायरस प्रदेश-दर-प्रदेश पसरा और अचानक एक दिन जब 'भारत बंद' का फैसला हुआ तो वह युद्ध मैदान में वायरस से लड़ने के लिए मेडिकल फोर्स, हथियारों, टेस्ट-अस्पतालों से धावा बोल हमले का बिगुल बजाकर नहीं, बल्कि इस जुगाड़ू सोच में है कि घरों में बंद होने से वायरस मर जाएगा। जुगाड़ कामयाब हुआ तो वाह और नहीं तो श्मशान घाट पर बैठकर लोग सोचेंगे कि इससे ज्यादा भला क्या हो सकता था! मौत नहीं टाल सकते!

ऐसे वुहान, इटली, स्पेन, न्यूयार्क या दुनिया के किसी भी देश में नहीं हुआ। वहां लॉकडाउन सचमुच में टेस्ट और मेडिकल महाअभियान का जंग बिगुल था। कार्ययोजना और रोडमैप से लॉकडाउन शुरू हुआ। लड़ाई के पूरे रोडमैप के साथ। मतलब टेस्ट से मौत तक याकि दाहसंस्कार के रोडमैप के साथ है। उस नाते रोडमैप का पहला बिंदु टेस्टिंग है। मगर भारत में लॉकडाउन के बाद भी टेस्टिंग ऊंट के मुंह में जीरा है। कोरोना वायरस चीन की गलतियों के कारण आज पूरे विश्व में तबाही मचाए हुए है। चीन की वुहान लैब में इबोला, निपाह, सॉर्स और दूसरे घातक वायरसों पर रीसर्च कर रहे वैज्ञानिक अपने माइक्रोस्कोप में एक अजीब सा वायरस नोटिस कर रहे थे। मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा वायरस पहले कभी नहीं देखा गया था। इसके जेनेटिक सिक्वेंस को गौर से देखने पर पता चल रहा था कि ये चमगादड़ के करीबी हो सकते हैं। वैज्ञानिक हैरान थे क्योंकि इस वायरस में वो सार्स वायरस के साथ समानता को देख पा रहे थे। जिसने 2002-2003 में चीन में महामारी ला दी थी और दुनियाभर में 700 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उस वक्त भी ये बताया गया था कि सार्स छूने और संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से फैलता है। लेकिन तब चीन इस वायरस को छुपा ले गया था।

दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में वुहान की सी-फूड मार्केट के इर्द-गिर्द रहने वाले कई लोग बुखार से पीड़ित होने शुरू हो गए। इनके टेस्ट के लिए सैंपल लैब में भेजे गए। जिसके बाद ये सैंपल वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरलॉजी नेशनल बायोसेफ्टी लैब के पास पहुंचे। यहां वैज्ञानिक के माइक्रोस्कोप जो उन्हें दिखा रहे थे। वो आने वाले जानलेवा ग्लोबल खतरे का संकेत था। मगर चीनी अधिकारियों ने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को

जांच के अपर्याप्त साधन

भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां इसके जांच की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। यहां 10 लाख लोगों के पीछे 16 टेस्ट का औसत है, जबकि जिन देशों ने आपातकाल, लॉकडाउन से जंग शुरू की उसमें दक्षिण कोरिया में 6 हजार टेस्ट का औसत है तो न्यूयार्क में लॉकडाउन से पहले प्रति 10 लाख आबादी पर 16 टेस्ट थे और लॉकडाउन के बाद 12 मार्च को 1,145 और 21 मार्च को 6,276 की टेस्टिंग थी। अमेरिका में तीन दिन पहले औसत प्रतिदिन टेस्टिंग 1280 लोगों की थी तो इटली में लॉकडाउन के बाद 25 मार्च को 5268 टेस्ट प्रतिदिन थे। जबकि 130 करोड़ लोगों के भारत में 25 मार्च तक कुल ही टेस्ट 25,144 थे। जाहिर है भारत में तालाबंदी जुगाड़ में हम वायरस को छुपाए बैठे हैं। जिस दिन भारत में प्रति दस लाख के पीछे सौ टेस्ट भी होने लगेंगे और नतीजों में फुर्ती आई नहीं कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा प्रभावित देश होने का ग्राफ बनने लगेगा।

बदनामी और अफरा-तफरी के माहौल से बचने के लिए खामोश करा दिया। नए साल के जश्न में दुनिया और चीन डूबे थे। और ठीक उनकी नाक के नीचे ये वायरस लगातार फैलता जा रहा था। 7 से 14, 14 से 21, 21 से 42 होते। ये तादाद हजार तक जा पहुंच गई। मगर चीन इस पर रोकथाम के बजाय इस जानलेवा बीमारी को दुनिया से छुपाने में ही लगा रहा।

डॉ. ली वेनलियांग इस बीच लगातार अपने डॉक्टर साथियों और लोगों को इस जानलेवा वायरस से ना सिर्फ आगाह कर रहे थे। बल्कि पीड़ितों को आइसोलेशन वार्ड में रखकर अपने तौर पर इलाज भी कर रहे थे। इस बीच ये खबरें चीन से निकलकर दुनिया तक पहुंचने लगी। चीन ने भी अब तक मान लिया कि उसके मुल्क को कोरोना नाम की एक महामारी ने जकड़ लिया है। फरवरी में अचानक खबर आई कि कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले डॉक्टर ली की मौत हो गई है। हालांकि सरकार विरोधी गुटों का ये मानना था कि चीन ने उन्हें इस महामारी का खुलासा करने की सजा दी है। आज चीन की एक गलती का खामियाजा पूरा विश्व भुगत रहा है। भारत में ज्यों-ज्यों कोरोना वायरस का टेस्ट बढ़ेगा, भारत के आंकड़ों के आगे अमेरिका, स्पेन, इटली की श्मशान की खबरें सामान्य लगने लगेंगी। लेकिन क्या यह रियलिटी वायरस से लड़ने की सरकार और जनता की लड़ाई के रोडमैप की असलियत नहीं होनी चाहिए? क्यों भारत के टीवी चैनल, मीडिया, नैरेटिव और भारत के लोग यह हल्ला नहीं बना रहे हैं कि बिना टेस्ट के हम कोरोना से नहीं लड़ सकते हैं। बिना युद्धस्तरीय मेडिकल टेकओवर, स्टेडियम-मैदानों को टेस्ट ग्राउंड, अस्पतालों में कनवर्ट किए हम महानगरों को मरघट बना डालेगें? तुरंत हर तहसील, हर जिले को उनकी सीमाओं में बांधकर उन्हें टेस्ट से लेकर अंत्येष्टि की गाइडलाइन में पाबंद बनाओ।

हां, हम यमदूत वायरस से तभी लड़ सकते हैं जब जागकर, होशोहवास में लड़ाई लड़ें। सीएनएन के ग्लोबल टाउनहाउस प्रोग्राम में स्पेन की रिपोर्ट में बताया गया है कि वहां प्रशासन ने वायरस के मरीज मृतकों के दाह संस्कार को रोक दिया, क्योंकि जगह और कर्मचारी की कमी से फिलहाल प्राथमिकता लड़ना है, समझ नहीं पड़ रहा कि करें तो क्या करें! कितनी दहला देने वाली बात है यह! लेकिन इटली और स्पेन जैसे महाविकसित व भारत से असंख्य गुना अधिक मेडिकल सुविधाओं, संजीदगी, अनुशासन, चुस्त सिस्टम वाले देश में यदि आज मृतकों की अंत्येष्टि भी मुश्किल चुनौती हो गई है तो गरीब, पिछड़े भारत में आने वाला वक्त क्या सिनेरियो लिए हुए होगा, यह क्या समझ नहीं आना चाहिए। क्या जुगाड़ में ही वक्त काटेंगे?

तभी इटली, स्पेन, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश वायरस से वेंटिलेशन पर गए लोगों को ही बचाने में फेल होते दिख रहे हैं पर मृत्यु दर न्यूनतम रखते हुए। विकसित देशों में मृत्यु दर संक्रमित लोगों में एक से दो प्रतिशत के बीच अटकेगी जबकि भारत सहित तीसरी दुनिया के बाकी देशों में कोरोना वायरस से बनने वाली मृत्यु दर तीन-चार प्रतिशत पहुंच जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए क्योंकि इन देशों की वायरस के खिलाफ लड़ाई बिना संसाधन, बिना हथियार, बिना तैयारियों के है। अमेरिका, स्पेन, इटली आदि विकसित देश लॉकडाउन के बाद घरों से वायरस को निकाल उसे अस्पताल ले जाकर लड़ने का फोकस बनाए हुए हैं जबकि भारत में तालाबंद के साथ लोगों को, वायरस को घरों में लड़ने के लिए रामभरोसे छोड़ा जा रहा है। अब इस बिंदु पर यह फुलस्टॉप बनता है कि हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास टेस्ट किट, लैब, अस्पताल, वेंटिलेशन, बख्तरबंद पीपीई पोशाक आदि याकि सार्वजनिक-निजीमेडिकल व्यवस्था का कुल जोड़ ही जब जर्जर है और दुनिया के बाजार की खरीदारी की मारामारी में ताबड़तोड़ सामान मंगवा सकना अपने लिए मुश्किल है तो करें तो क्या करें? इस पर फिर विचार करेंगे।

● **अक्स टीम**

दुनिया में तबाही मचाने वाले अन्य वायरस

स्वाइन फ्लू, एच1एन1: एक खतरनाक वायरस की वजह से होने वाला संक्रमण है। इस वायरस ने 2009 में पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। इस दौरान स्वाइन फ्लू की वजह से दुनियाभर में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।

इबोला: इबोला एक खतरनाक वायरस है। जो कि 2014 से 2016 तक पश्चिम अफ्रीका में काफी जानलेवा साबित हुआ था। इस वायरस से करीब 11 हजार लोगों की जिंदगी खत्म हो गई थी। यह वायरस सबसे पहले 1976 में देखा गया था।

सार्स: अभी चीन में फैल रहे नोवेल कोरोना वायरस की तरह ही सार्स भी कोरोनावायरस का एक प्रकार है। जिसका प्रकोप 2003 में पूरी दुनिया में फैला था। सार्स एक खतरनाक वायरस है। जिसने 26 देशों के लोगों को अपना शिकार बनाया था और करीब 774 लोगों की मौत का कारण बना था।

मर्स: मर्स भी सार्स की तरह कोरोनावायरस का एक प्रकार है। जो कि सबसे पहले 2012 में सऊदी अरब में पाया गया। यह वायरस सबसे पहले चमगादड़ों में होता है, जो कि किसी तरह ऊंटों में फैल गया। इन्हीं संक्रमित ऊंटों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क में आने से यह वायरस इंसानों में आया है।

स्पेनिश फ्लू-1918: दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस स्पेनिश फ्लू ने दुनिया की करीब एक तिहाई आबादी को अपना शिकार बना लिया था। यह वायरस सबसे पहले यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स और एशिया के कुछ हिस्सों में देखा गया था। जिसने करीब 2 करोड़ से 5 करोड़ लोगों की जिंदगी खत्म कर दी थी।

कांगो फीवर: कांगो फीवर एक तरह का खतरनाक बुखार है। जो संक्रमित जूं के काटने या संक्रमित जानवर के खून के संपर्क में आने से फैलता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि अब तक इसका कोई सटीक इलाज सामने नहीं आया है।

जीका वायरस: जीका वायरस एक वायरल संक्रमण है। जो मुख्य रूप से मच्छर के काटने से होता है। मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटकर वायरस को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है। भारत में हर साल लगभग पांच हजार मामले जीका वायरस के आते हैं। गर्भवती महिला को जीका होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है।

एचआईवी-एड्स: एचआईवी-एड्स का पहला मामला 1976 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में देखने को मिला था। एचआईवी की वजह से अब तक दुनियाभर में अनुमानित 3 करोड़ 20 लाख लोगों की जान जा चुकी है।

डेंगू बुखार: मच्छरों से फैलने वाले डेंगू बुखार से हर साल 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं। भारत और थाइलैंड जैसे देशों में डेंगू का खतरा काफी बड़ा है। डेंगू से रक्त वाहिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या रिसने लगती हैं। रक्तप्रवाह से प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है।

कहां हैं माननीय?

'लूट' को रोकना आपका दायित्व है

कोरोना महामारी की घबराहट फैलते ही बाजार बंद करा दिए गए, कर्फ्यू लागू है। अब चारों तरफ आवश्यक वस्तुओं में मानो लूट सी मच गई है। टमाटर 50 रुपए, आलू 40 रुपए बिकने लगा है। हर जरूरी सामान महंगा हो गया। यह अनायास महंगाई लूट का दूसरा स्वरूप है जिसे रोकने में सरकार असहाय है। मास्क, सेनिटाइजर जरूरी सामान की कालाबाजारी शुरू हो गई, क्योंकि लोगों को यह लगता है की लूट सके तो लूट। अगरचे, हमारे प्रमुख नेता सदशयता दिखाएं, स्वयं आगे आकर लोगों से मिलें, कोरोना का भय त्याग कर समस्या देखें, हॉस्पिटल के हालात देखें, व्यवस्था करें तो कितना अच्छा हो। यह काम जिलाधीश, अफसरों पर छोड़ना आप कितना जायज मानते हैं। संयोगवश ही माना जाए, लेकिन मोबाइल पर वस्तु सेवा कर (जीएसटी) 18 प्रतिशत तक पहुंचा दिया गया है। स्पष्ट है कि मंदी के दौर में बीमारी और महंगाई दोनों मार रही हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र चीनी कलपुर्जे की कमी से संकट में है। इसके अलावा मास्क समेत अनेक आवश्यकताएं चीनी सामान से पूरी होती हैं, जिनके कम होने से मुनाफाखोरी को अच्छी खासी जगह मिल गई है।

दुनिया के लगभग सभी देशों में कोरोना की प्रतिछाया के दुष्परिणाम सामने हैं। आज दुनिया पर महामारी का प्रकोप है। कोरोना जिसका इलाज अभी वैज्ञानिकों के पास नहीं है, ऐसे में यह तो होना ही था कि हमारी सरकार जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन और कर्फ्यू के रास्ते पर चल पड़े। मगर इस सब के बीच जो सार तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं उसके आधार पर यह कहना समीचीन होगा कि जो अनुशासन, समझदारी और सौहार्द, मानवता दिखाई देनी चाहिए वह समाज में दिखाई नहीं दे रही। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण ने लोगों को बेचैन कर दिया है। संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। लगातार 21 दिन का लॉकडाउन होने के कारण बाजारों में महंगाई की मार आ गई है। नवरात्र में फलों की डिमांड बढ़ने से महंगाई और बढ़ गई है। सबसे ज्यादा महंगाई फल एवं सब्जियों पर है। लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। बाजारों में फल एवं सब्जियां काफी महंगी हो गई हैं। छोटे दुकानदारों ने 10 से लेकर 20 रुपए किलो तक के भाव बढ़ा दिए हैं। पिछले दो सप्ताह में सब्जियों और फलों के दामों में इजाफा हुआ है। आलू, प्याज, अन्य हरी सब्जी, और फलों में सेब, केला, अंगूर, पपीता, चीकू, संतरा अन्य फल काफी महंगे हैं। मजबूरन लोगों को महंगी सब्जियां खरीदनी पड़ रही हैं।

सरकार का जो दायित्व होता है उसे निभाने में कोताही दिखाई दे रही है। जनवरी 2020 में ही कोरोना की दस्तक सुनाई दी थी, मगर इसके बावजूद सरकार ने वही गलतियां की जो आम आदमी करता है। जिस सूझबूझ, तत्परता की दरकार सरकार से थी उसमें केंद्र और राज्य सरकारों ने चूक की। 'नमस्ते ट्रंप' कार्यक्रम हो या वेंटिलेटर, चिकित्सा व्यवस्था में कसावट का मामला, सरकार हर जगह फ्लॉप हुई है। अगरचे यही गलतियां कोई और करता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे कभी माफ नहीं करते और सारा देश सर पर उठा लेते, ऐसे में कोरोना संदर्भ में विपक्ष के रूप में कांग्रेस की भूमिका सराहनीय है।

चाहे वे मंत्री हों या जनसेवा का चोला, व्रत धारण करने वाले हमारे नेता। आज कोरोना वायरस अटैक के दरम्यान घरों में कैद हो गए हैं। घर से बाइट, स्टेटमेंट जारी हो रहे है। हम तो यही कहेंगे अगर आप नेता हैं, मंत्री हैं तो आपने जनता जनार्दन की सेवा का व्रत लिया है, जनता ने आप को वोट दिया है। ऐसे में नेता, मंत्रीगण का कर्त्तव्य है कि सर्व-सुरक्षा के साथ जनता के बीच पहुंचे और उनकी समस्याओं को हल करने का दायित्व निर्वहन करें।

प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री! आपका कर्तव्य यह नहीं है कि कर्फ्यू, लॉकडाउन करके आप चैन की बांसुरी बजाते रहें। चौराहे पर पुलिस लोगों को कंट्रोल करे, डंडे बरसाए। इससे समस्या का हल नहीं होगा। आवश्यकता, संवेदनशीलता के साथ लोगों को अपना परिवार मानते हुए इस भीषण विकट स्थिति में लोगों की मदद करना। मदद की उदात्त भावना नेता, मंत्रीगण, प्रशासन में दिखाई देनी चाहिए न ही किसी बैरी, शत्रु का भाव दिखाई पड़ता रहे और यह भावना सदासयता में दिखाई देनी चाहिए मगर दुर्भाग्य कि यह हममें नहीं है। मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्स जब इस पेशे में आते हैं तो यह भावना सेवा, समर्पण की होनी चाहिए। नेता, मंत्री को ही देखिए मगर क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है? यह बेहद दुखद स्थितियां हैं।

कोरोना महामारी के इस भीषण काल में कोई मंत्री एक महीने की तनख्वाह दे रहा है, तो कोई तीन महीने की। एक-एक लाख रुपए, तो कोई दस लाख रुपए। ठीक है पैसे की अहमियत है, पैसा बहुत कुछ है मगर यह मंत्रीगण, नेताजी भूल गए हैं कि आप जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। आप घरों से निकलकर जनता के पास पहुंचे और उनके आंसू पोंछें, लाखों दिहाड़ी कमाने वालों को क्या दो वक्त की रोटी नसीब हो रही है, क्या गरीब, आम आदमी ने खाना खाया है। यह देखना भी आपका परम कर्त्तव्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप सच्चे अर्थ में जनप्रतिनिधि या मंत्री नहीं हैं। अब चुनाव के समय आप कैसे घर-घर जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्चते हैं, शराब-मुर्गा बांटते हैं। हाथ जोड़ते हैं सच्चे अर्थ में हाथ जोड़ने गले लगाने का वक्त आज है।

भारत में वर्तमान समय को राष्ट्रीय आपदा की घड़ी माना गया है। यूं तो दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत की स्थिति काफी नियंत्रण में नजर आ रही है। देश में सबसे पहला मरीज केरल में जनवरी माह में मिला था, जो चीन से आया था और अब वह ठीक हो चुका है। हाल-फिलहाल जो मरीज सामने आ रहे हैं, वे चीन की बजाय उन देशों से आए हुए हैं, जहां लापरवाही से कोरोना वायरस का प्रवेश हुआ है।

● **कुमार विनोद**

ब्याज घटने की असली वजह?

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज को घटाकर तीन फीसदी कर दिया। ब्याज दरों में यह कटौती उन जमाकर्ताओं के लिए बुरी खबर है जिनके बचत खाते एसबीआई में हैं और उनमें रिटायरमेंट या बच्चों की शादी के लिए इकट्ठा किया गया फंड है। देश के सबसे बड़े बैंक की ओर से ब्याज दरों में कटौती यानी बचतों पर कैंची अन्य बैंकों पर भी चलेगी। बैंकों में आपकी जमा पर मिलने वाला रिटर्न दरअसल बैंकों के लिए कॉस्ट ऑफ फंड (पूंजी की लागत) है। यदि बैंक आपको जमा पर ऊंची ब्याज दर का भुगतान करेगी तो निश्चित तौर पर घर या कार के लिए मिलने वाला कर्ज भी महंगा होगा। अर्थव्यवस्था के मौजूदा परिदृश्य में जब बैंकों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कर्ज देने का दबाव है तब जमा पर ऊंचा रिटर्न दे पाना बैंकों के लिए मुश्किल है। इसके अलावा सरकारी बैंकों में जमा की आमद और कर्ज बांटने की रफ्तार में बड़ा अंतर है। अप्रैल 2019 से दिसंबर 2019 के दौरान एसबीआई ने कुल दो लाख करोड़ से ज्यादा (2,03,739 करोड़) की जमा पूंजी जुटाई, जबकि इस अवधि में बैंक ने कुल 21,862 करोड़ रुपए के कर्ज बांटे। यह कुल जमा का सिर्फ 10.7 फीसदी ही है।

अब बैंक के नजरिए से समझिए तो कर्ज की मांग न होने पर बैंक को इन जमाओं पर तो ब्याज देना ही है। पहले से अर्थव्यवस्था में सुस्ती और उसके बाद कोरोना का असर कर्ज की मांग को और कमजोर कर सकता है। यस बैंक के दिक्कत में फंसने के बाद निजी बैंकों पर लोगों का डोलता भरोसा सरकारी बैंकों में जमाओं को पहाड़ और ऊंचा कर सकता है। सुस्त मांग और बढ़ती जमा के दबाव में बैंकों के पास जमा पर रिटर्न घटाना ही अंतिम विकल्प बचता है क्योंकि बैंकों में जमा लेने से तो मना किया नहीं जा सकता है। कर्ज की मांग सुस्त होने का असर न केवल एसबीआई बल्कि सभी सरकारी बैंकों में देखने को मिल रहा है। अप्रैल 2019 से दिसंबर 2019 के दौरान सभी सरकारी बैंकों ने कुल 25,530 करोड़ रुपए का कर्ज दिया, जबकि सरकारी बैंकों में कुल जमा 4,08,733 करोड़ रुपए की रही। आने वाले दिनों में कोरोना का असर बढ़ा तो कर्ज की मांग को और चोट पहुंच सकती है ऐसे में हमारी जमा पर और कैंची न चले इसकी दुआ कीजिए।

उधर, आयकर की नई व्यवस्था में कर छूट का लाभ पाने के लिए आपको सभी रियायतें छोड़नी होंगी। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने यह भी समझाया कि नई व्यवस्था के तहत 15 लाख रुपए की आय वाले लोगों को 78,000 रुपए कम टैक्स चुकाना होगा। नई व्यवस्था लाई गई है और वित्त मंत्री उसमें कर बचत का लाभ बता रही हैं यानी सरकार चाहती है कि करदाता नई व्यवस्था को अपनाएं। सरकार की मंशा इसके पीछे केवल कर बचाने के लिए की जाने वाली बचत को हतोत्साहित करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा करदाता के हाथ में हो और वे इसे खर्च करके टूटी खपत की मरहम पट्टी कर सकें। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में खपत की सबसे ज्यादा करीब 60 फीसदी हिस्सेदारी है। सुस्त अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए खपत के पहिए का चलना जरूरी है। क्योंकि निजी निवेश (जो जीडीपी में दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखता है) भी खपत बढ़ने की ही राह तक रहा है।

नई व्यवस्था और इसके पीछे सरकार की मंशा तो समझ ली, लेकिन करदाताओं के लिए नई व्यवस्था कितने काम की है यह बड़ा सवाल है। देश में 92 फीसदी लोग कर बचत के लिए 2 लाख रुपए से कम बचाते हैं। केवल आयकर बचाया जा सके इसके लिए यूलिप, एलआईसी जैसे उत्पादों में निवेश करते हैं। इसकी कितनी जरूरत है और यह निवेश कितना फायदेमंद है इस पर विचार किए बिना। ये करदाता निश्चित तौर पर अपनी सालाना आय का एक हिस्सा टैक्स के रूप में देकर बचे हुए को अपने मन मुताबिक खर्चना चाहेंगे। लेकिन नई व्यवस्था नौकरीपेशा लोगों के लिए खास आकर्षक नहीं है। क्योंकि उनके बस में सैलरी से कटने वाला पीएफ, कंपनी की ओर से दी गई हेल्थ पॉलिसी का प्रीमियम आदि नहीं होता। वहीं एचआरए आदि का फायदा नियोक्ता बेसिक सैलरी के आधार पर देता है। ये चीजें सैलरी से कटना अनिवार्य हैं। ऐसे में नौकरीपेशा लोगों के लिए नई व्यवस्था फायदेमंद है या नहीं यह उनके वेतन से होने वाली अनिवार्य कटौती के बाद ही तय किया जा सकता है। जिन लोगों ने होमलोन ले रखा है या जिनके बच्चों की स्कूल फीस 80-सी में बचत का बड़ा हिस्सा लेती है वे भी नई व्यवस्था को अपनाने से कतराएंगे। क्योंकि वे पहले से इसका लाभ ले रहे हैं और रातोंरात कुछ नहीं बदल सकते। नई व्यवस्था निश्चित तौर पर बचत (एलआईसी, यूलिप, ईएलएसएस, बचत योजनाएं) और रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को हतोत्साहित करेगी। क्योंकि बीते कुछ वर्षों में न तो रियल एस्टेट और न छोटी बचत योजनाएं रिटर्न देने के मामले में कोई खास आकर्षित कर पाई हैं।

● **नवीन रघुवंशी**

कितने करदाता की कसरत?

जिन व्यक्तिगत करदाताओं के लिए यह पूरी कसरत की जा रही है वे देश में हैं कितने यह जानना भी जरूरी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एसेसमेंट ईयर 2018-19 में कुल 8.46 करोड़ करदाता थे, यहां यह समझना जरूरी है कि सरकार करदाता मानती किसको है? सरकार उन सभी लोगों को करदाता मानती है जो आयकर रिटर्न फाइल करते हैं या जिनकी आय पर टीडीएस कटा हो। लेकिन यह सही नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति ने रिटर्न भरा हो उसकी कर देनदारी भी बनती हो। इसी तरह जिस व्यक्ति का टीडीएस कटा हो उसने आयकर रिटर्न फाइल किया हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं। एसेसमेंट ईयर 2018-19 में कुल 5.53 करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया लेकिन उनमें से 2.24 करोड़ लोगों ने कोई टैक्स जमा नहीं किया। यानी कुल 3.29 करोड़ लोग ऐसे हैं जो देश में कर भी देते हैं और आयकर रिटर्न भी फाइल करते हैं। इसी तरह देश में 2.93 करोड़ लोग (8.46 करोड़-5.53 करोड़) ऐसे हैं जिनका टीडीएस कटा लेकिन उन्होंने कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया। यानी व्यक्तिगत करदाताओं की कुल संख्या 2.93+3.29 = 6.22 करोड़ है। 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश में महज 6.22 करोड़ व्यक्तिगत करदाता हैं, जो खपत को बढ़ाने और कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

हमेशा तिरंगा गमछा गले में डाले रहने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के गले में अब भगवा गमछा नजर आने लगा है। सिंधिया ने जिस दिन अपने गले में भगवा गमछा डाला उसी दिन तय हो गया था कि मप्र की कांग्रेस सरकार अधिक दिन नहीं टिक पाएगी और 20 मार्च को 15 माह पुरानी कमलनाथ सरकार गिर गई। लेकिन सिंधिया के गले में भगवा गमछा पहनवाने और उनके समर्थकों को कांग्रेस से तोड़कर भाजपा में लाने के लिए पार्टी के 6 नेताओं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, संजय पाठक, अरविंद भदौरिया और सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले जफर इस्लाम को लगाया गया था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे ऑपरेशन पर नजर रखे हुए थे।

भाजपा का ऑपरेशन लोटस

मप्र में 2018 में हुए विधानसभा चुनावों के बाद से ही राज्य में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। इस राजनीतिक अस्थिरता के लिए भले ही कांग्रेस और कमलनाथ भाजपा और केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं लेकिन इस अस्थिरता के पीछे असली कारण कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी असंतोष था जिसे पार्टी समय रहते नहीं संभाल पाई। उधर कांग्रेस की इसी अस्थिरता का फायदा उठाने के लिए भाजपा ने ऑपरेशन लोटस शुरू किया।

कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में लाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन लोटस के लिए एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जिस पर सिंधिया और भाजपा आलाकमान भरोसा कर सके। काफी सोच विचार करके भाजपा ने पार्टी प्रवक्ता जफर इस्लाम को ऑपरेशन लोटस की कमान सौंपी। ज्योतिरादित्य को भाजपा तक लाने और फिर गृहमंत्री अमित शाह व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने वाले कोई और नहीं, बल्कि भाजपा प्रवक्ता **जफर इस्लाम** हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को गिराने में भाजपा ने अपने 6 नेताओं को लगाया था जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, संजय पाठक, अरविंद भदौरिया और सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले जफर इस्लाम लगाया गया था। इसके बाद मध्य प्रदेश स्तर की राजनीति में सारे समीकरणों को साधने के लिए नरोत्तम मिश्रा ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं संजय पाठक और विश्वास सारंग ने भोपाल से लेकर बेंगलुरु तक मोर्चा संभाले रखा। 9 मार्च को जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से आखिर बगावत कर दी तो उससे करीब एक महीने पहले से ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा के बड़े नेता आपस में संपर्क में थे। गृहमंत्री अमित शाह मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के बड़े नेता नरेंद्र सिंह तोमर, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा के महासचिव डॉ. अनिल जैन के बीच 11 फरवरी से लगातार बैठकें हो रहीं थी। इन बैठकों में मध्य प्रदेश में सरकार पलटने के फॉर्मूले पर चर्चा हो रही थी। यह वह समय था जब बजट सत्र का पहला हिस्सा खत्म हो रहा था। 11 फरवरी को गृहमंत्री अमित शाह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के फॉर्मूले पर सहमति दे दी थी और आगे की बातचीत के लिए धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा डॉ. अनिल जैन की अगुवाई में एक टीम बना दी थी। टीम का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे थे।

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 21 फरवरी को भाजपा नेताओं को 24 कांग्रेस विधायकों की सूची सौंपी। इसके बाद लगभग यह तय हो गया कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को टाटा बाय-बाय कहने के मूड में आ गए हैं। इन विधायकों से संपर्क का जिम्मा भाजपा ने नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, विश्वास सारंग को सौंपा गया। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के निकट सहयोगी मदद कर रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस नेतृत्व से राज्य में प्रदेश अध्यक्ष का पद या राज्यसभा की सीट चाहते थे, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी सिंधिया को ना तो प्रदेश अध्यक्ष का पद और ना ही राज्यसभा की सीट देने के पक्ष में थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की इस मंशा को समझ गए थे। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामने का मन भी बना चुके थे और इसके लिए 5 मार्च की तारीख भी तय हो गई थी।

भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह तमाम कांग्रेस विधायकों को लेकर गुड़गांव पहुंचने लगे थे। यह कांग्रेस विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के थे इनमें एंदल सिंह कंसाना, जसवंत जाटव, मुन्नालाल गोयल, रघुराज सिंह कंसाना, गिरिराज दंडोतिया, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर शामिल थे। इनके साथ ही बसपा से रामबाई और संजीव सिंह के अलावा समाजवादी

नड्डा ने आते ही अभियान को दी हर झंडी

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 114, भाजपा ने 109, बसपा ने 2, सपा ने 1 और चार निर्दलीय जीते थे। कमलनाथ ने सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी। कांग्रेस ने सरकार तो बना ली लेकिन सरकार गठन के बाद से ही मुश्किलों का सामना कर रही थी। शाह की अगुवाई में भाजपा इसे गिराने का कोई सक्रिय प्रयास नहीं कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक, जेपी नड्डा भाजपा अध्यक्ष बने तो उन्होंने संघ से मिले फीडबैक के बाद शिवराज सिंह चौहान को ऑपरेशन लोटस शुरू करने की अनुमति दी। शिवराज ने भूपेंद्र सिंह, अरविंद भदौरिया और रामपाल सिंह के साथ अपनी योजना पर काम शुरू किया। नरोत्तम मिश्रा को भी शामिल किया गया। सिंधिया से संपर्क किया गया और बातचीत शुरू हुई।

पार्टी के राजेश शुक्ला उर्फ बबलू और निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भी शामिल थे। इन विधायकों को 5 मार्च की रात गुड़गांव की होटल ग्रैंड में ठहराया गया, लेकिन इस बड़े उलटफेर की खबर दिग्विजय सिंह को लग गई और और वे अपने बेटे जयवर्धन और एक अन्य मंत्री जीतू पटवारी के साथ गुड़गांव के होटल में जा धमके। कुछ कांग्रेस विधायक वहां से स्थिति बिगड़ती देख चुपचाप निकल लिए जबकि बसपा विधायक रामबाई को जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी अपने साथ लेकर आए और ऑपरेशन लोटस की यह पहली कोशिश विफल हो गई। लेकिन भाजपा और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हार नहीं मानी। सिंधिया के तेवर और कड़े हो गए इस बार उन्होंने जो योजना बनाई वह ऐसी थी कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई।

8 मार्च और 9 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान की कई दौर की बैठकें हुईं। यह बैठकें दिल्ली के गोल्फ कोर्स इलाके में गुप्त ठिकाने पर हुईं। इस दौरान यह सभी नेता अपने स्टाफ और सरकारी ड्राइवर को भी अपने घरों पर छोड़कर गुप्त ठिकाने पर मिलते थे। 8 मार्च की बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा में भेजे जाने पर सहमति बन गई। इसके बाद 8 मार्च की रात को भिंड, ग्वालियर और मुरैना के सिंधिया खेमे के विधायकों को दिल्ली लाने का ऑपरेशन शुरू हुआ। फिर जब दोबारा ऑपरेशन लोटस शुरू हुआ तो तीन विधायकों प्रद्युम्न सिंह तोमर जो कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी थे, ओपीएस भदौरिया को ग्वालियर के जयविलास पैलेस से सबसे पहले अपने साथ लिया गया। इस ऑपरेशन में नरोत्तम मिश्रा ने अहम भूमिका निभाई। इसके बाद मुन्नालाल गोयल, इमरती देवी, गिर्राज दंडोतिया, सुरेश धाकड़, महेंद्र सिंह सिसोदिया जैसे तमाम दूसरे विधायकों को एक के बाद एक लेते हुए यह लोग दिल्ली की तरफ बढ़ लिए।

इस बार इस ऑपरेशन की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद संभाल रखी थी और उनके पीए पाराशर खुद विधायकों के साथ कॉर्डिनेट कर रहे थे। 8 मार्च के ऑपरेशन की कानों कान खबर किसी को नहीं हुई। सुबह 4 बजे के आसपास सिंधिया खेमे के 17 विधायक पलवल के पास एक रिसॉर्ट में शिफ्ट कराए गए। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया सुबह 5 बजे इन विधायकों से मिलने उस रिसॉर्ट में पहुंचे। सिंधिया ने अपने खेमे के विधायकों के साथ 2 घंटे लंबी चर्चा की। उन्होंने अपने कट्टर विधायकों की काउंसलिंग की। उन्हें समझाया कि क्यों इस सरकार से बाहर निकलना है और कमलनाथ की सरकार गिराना जरूरी है। आखिरकार सभी विधायक अपने नेता के साथ खड़े हो गए।

9 मार्च की सुबह इन विधायकों को बेंगलुरु ले जाने के लिए तीन चार्टर प्लेन तैयार थे। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन चार्टर प्लेन को समय पर तैयार रहने के आदेश दिए थे। तकरीबन दोपहर के 12 बजे के आसपास यह विधायक एयरपोर्ट पहुंचकर चार्टर प्लेन में बैठ चुके थे। 3 बजे यह चार्टर प्लेन बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर उतरे तो वहां भाजपा के विधायक निंबा वाली ने इनका स्वागत किया और इन्हें सीधे बेंगलुरु के बाहरी इलाके में फॉर्म स्प्रिंग रिसॉर्ट में ठहरा दिया गया। इस दौरान शाम को 5 बजे के आसपास ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस नेतृत्व को अपना इस्तीफा दे चुके थे। इस्तीफा भेजने के बाद उनकी मुलाकात गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई। सबकुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक ही चल रहा था। मध्य प्रदेश में सरकार गिराने का जो फॉर्मूला तय हुआ था, उसके तहत कम से कम 27 विधायकों को साथ लेने का फार्मूला तय हुआ था। इनमें से 22 विधायक सिंधिया खेमे के थे, बाकी पांच विधायक, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और निर्दलीय थे। 9 मार्च की रात ऑपरेशन लोटस लगभग आधा रास्ता तय कर चुका था। अब सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधायकों के इस्तीफे देने की औपचारिकता बची थी। 10 मार्च का दिन खास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसलिए चुना, क्योंकि इसी दिन 75 साल पहले उनके पिता माधव राव सिंधिया का जन्म हुआ था। 10 मार्च की सुबह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गृहमंत्री अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उसके बाद तय कार्यक्रम के मुताबिक बेंगलुरु में मौजूद सिंधिया खेमे के 19 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया। बाद में सिंधिया खेमे के तीन और विधायकों ने भी विधानसभा अध्यक्ष को अपने इस्तीफे भेज दिए और इस तरह ऑपरेशन लोटस अपने अंजाम तक पहुंचता हुआ दिखाई देने लगा।

● **राजेश बोरकर**

ऐसे टूटा सिंधिया के सब्र का बांध

मध्य प्रदेश में जब 13 दिसंबर 2018 को 15 साल बाद शिवराज के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को शिकस्त देकर कांग्रेस की सरकार बनी और सिंधिया की तमाम कोशिशों, जोड़-तोड़ के बावजूद पार्टी आलाकमान ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। तभी से सिंधिया खिन्न थे, मलाल इस बात का था कि चुनाव उनके नाम और चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री पद की मलाई कमलनाथ के हाथ लगी। राज्य में सरकार बनी तो आरोप यह लगा कि सिंधिया गुट से सबसे कम विधायकों को मंत्री बनाया गया। सिंधिया के सब्र का नतीजा ये रहा कि कमलनाथ-दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी नहीं बनने दिया। उसके बाद राज्यसभा की बारी आई तो पहली सीट पर दिग्विजय सिंह का नाम आगे कर दिया गया। दूसरे के लिए प्रियंका गांधी से लेकर दीपक सक्सेना तक के नाम हवा में तैराए जाने लगे। सत्ता और संगठन में लगातार उपेक्षा से आहत ज्योतिरादित्य सिंधिया के सब्र का बांध आखिर टूट ही गया। उपेक्षा से आहत सिंधिया ने पिछले कुछ दिनों से आर-पार की लड़ाई के तेवर अपना लिए थे। बीते फरवरी में अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण और किसानों की कर्जमाफी के मुद्दे पर आंदोलनकारियों के बीच से ज्योतिरादित्य ने अपनी ही सरकार को खुली चुनौती दे डाली थी कि अगर कमलनाथ सरकार ने अपने चुनावी वचन पत्र का पालन नहीं किया तो वह सड़क पर उतरेंगे। इसका जवाब मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से बेहद तल्खी भरा आया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सरकार वचन पत्र का पालन कर रही है, जिसे सड़क पर उतरना हो, उतर जाए। हम डरने वाले नहीं हैं। यह बात सिंधिया को नागवार गुजरी। सुलह के लिए दिग्विजय सिंह के साथ उनकी मीटिंग भी नाकाम हो गई। जब तक बात संभलती, तब तक पानी सिर से ऊपर निकल चुका था।

जलसंकट की आहट

वर्ष 2019-20 में हैंडपंप स्थापना के लक्ष्य

मंडलवार	लक्ष्य (बसाहटों की संख्या)	उपलब्धि
भोपाल	864	527
नर्मदापुरम	805	506
इंदौर	1410	1220
खरगोन	500	391
उज्जैन	1120	950
ग्वालियर	775	528
चंबल	730	311
सागर	430	316
पन्ना	450	367
जबलपुर	715	469
रीवा	585	401
छिंदवाड़ा	1375	585
शहडोल	250	239
महायोग	10,009	6,810

वर्ष 2019 में अतिवृष्टि के कारण महीनों जलमग्न रहने वाले मप्र में अभी से जल संकट की आहट सुनाई देने लगी है। दरअसल, केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूबी) ने मप्र के 18 जिलों सहित देश के 256 जिलों की पहचान की है जहां भू-जल का अतिदोहन हुआ है। मप्र में भू-जल का अतिदोहन होने वाले 18 जिलों के करीब 4000 से अधिक गांवों में अभी से जलसंकट गहराने लगा है। सीजीडब्ल्यूबी ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार अभी से नहीं चेती तो स्थिति भयानक हो जाएगी। इस रिपोर्ट के बाद जब प्रदेश में नलजल योजनाओं की स्थिति का आंकलन किया गया तो यह तथ्य सामने आया कि कमलनाथ सरकार ने अपने 13 माह के शासनकाल में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यही नहीं पिछले 15 सालों में लगभग 35,000 करोड़ रुपए खर्च हुए लेकिन पानी सिर्फ छह फीसदी ग्रामीण आबादी को ही मिल रहा है।

22 मार्च को विश्व जल दिवस था। लेकिन मप्र में सरकार नहीं होने और कोराना के कारण जनता कर्फ्यू होने के चलते जल संरक्षण को लेकर कोई दावे तो नहीं हो सके, लेकिन पूर्व में किए गए बड़े-बड़े दावों की पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया है कि पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में नलजल योजनाओं पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में सरकार ने 10,009 बसाहटों में हैंडपंप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन इस दौरान केवल 6,810 ही हैंडपंप लगाए जा सके। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का दावा है कि प्रदेश में जलसंकट की स्थिति से निपटने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। विभाग के अनुसार, प्रदेश में कुल 16,105 नलजल योजनाएं स्थापित की गई हैं, जिनमें से 15,037 चालू हैं और 1,068 बंद हैं। वहीं जल निगम द्वारा 36 नलजल योजनाएं संचालित हैं और उसका दावा है कि सभी चालू हैं। वहीं विभागीय सूत्रों का कहना है कि कागजों पर तो नलजल योजनाएं दुरुस्त हैं लेकिन स्थिति इसके विपरीत है। प्रदेशभर में करीब पांच हजार नलजल योजनाओं की स्थिति इतनी खराब है कि वे केवल शोभा की वस्तु बनी हुई हैं।

पीएचई अफसरों की मानें तो जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे यह तथ्य सामने आया है कि गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी लगभग 4,000 गांवों में पेयजल संकट मंडरा सकता है। पिछले वर्ष जून में 146 नगरीय निकाय ऐसे थे, जहां रोजाना पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी तो 378 नगरीय क्षेत्रों में से 32 नगरीय निकायों में टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया गया था। इस बार भी वही स्थिति निर्मित हो रही है।

उधर, ग्रामीण विकास विभाग प्रदेश की लगभग 100 किलोमीटर बहने वाली 40 नदियों पर काम कर रहा है। इस काम का लक्ष्य है सूखे महीनों में इन 40 नदियों के प्रवाह को बढ़ाना। उनके पुराने बारहमासी चरित्र को बहाल करना। इसे हासिल करने के लिए जिस गाइडलाइन पर काम किया जा रहा है, उसके तहत नदी कछार की सीमा से लेकर मुख्य नदी के पास तक, परंपरागत तालाबों की तर्ज पर गहरे और बड़े आकार के तालाबों का निर्माण किया जाना है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक वर्षाजल का संचय और गहराई के कारण भू-जल रीचार्ज करना है। लेकिन यह योजना कब परवान चढ़ेगी पता नहीं।

● **विकास दुबे**

पंचायतों की आर्थिक हालत कमजोर

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर हर ग्रामीण घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए हर घर नल, हर नल जल की योजना बनाई है। जल जीवन मिशन के तहत साल 2024 तक देश के सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। लेकिन विगत छह माह से प्रदेश की किसी भी पंचायत में 14वें वित्त आयोग की राशि नहीं डालने से मूलभूत काम ठप पड़े हैं। पंचायतों में पैसा नहीं होने की वजह से कई ग्राम पंचायतों में स्थानीय स्तर के काम रुके हुए हैं। खासकर नलजल योजनाओं का काम अधर में हैं। गर्मी का मौसम आने को है और ऐसे में पेयजल वितरण में भी परेशानी होगी। ग्राम पंचायतों में जर्जर पानी की टंकियों तथा टैंकरों की रिपेयरिंग के लिए भी राशि नहीं है। अधिकांश ग्राम पंचायतों में नलजल योजना के तहत लगाई मोटर व पाइपलाइन खराब है, उनके रखरखाव के लिए भी राशि चाहिए। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि दिसंबर माह तक यह राशि मिल जाती है, लेकिन इस वर्ष मार्च माह आधा बीत गया, लेकिन राशि नहीं आई है। अगर राशि मार्च में भी नहीं मिली तो इसके लैप्स होने की संभावना है।

जल के दोहरे संकट से निपटने का समय... नीति आयोग के अनुसार, देश के सामने पानी की दोहरी समस्या है-एक तरफ पानी की कमी है, दूसरी तरफ स्वच्छ जल की अनुपलब्धता है। वर्ष 2030 तक करीब 40 फीसदी भारतीयों के पास पीने का पानी नहीं होगा। इस संकट का मुकाबला करने के लिए सरकार पहले से ही रणनीति बना रही है। प्रधानमंत्री ने जहां लोगों से जल संरक्षण में योगदान करने का आग्रह किया है, वहीं जल शक्ति मंत्रालय को 2024 तक देश के सभी घरों में नलों के जरिए स्वच्छ पानी पहुंचाने का काम सौंपा गया है। पर देश दूसरी जिस बड़ी समस्या का सामना कर रहा है, वह है स्वच्छ पेयजल जन-जन तक पहुंचने में कमी। मप्र में ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में सरकार ने 10,009 बसाहटों में हैंडपंप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन इस दौरान केवल 6,810 ही हैंडपंप लगाए जा सके। ऐसे में इस गर्मी में भी लोगों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ेगा।

अपराध भी लॉकडाउन

कोरोना से बचाव के लिए लोग घरों में कैद हैं। राजधानी भोपाल सहित पूरा प्रदेश लॉकडाउन है। कुछेक लोग अब भी बाहर निकलने को परेशान हैं लेकिन पुलिस का ऐसा पहरा है कि कोई दूर-दूर तक नहीं भटक रहा। इसका असर यह हुआ कि लॉकडाउन में मप्र अपराध मुक्त हो गया है। सिर्फ अपराध पर ही रोक नहीं लगी बल्कि सड़क हादसे भी रुक गए हैं। स्थिति यह है कि अपराध के मामले में अव्वल रहने वाले इंदौर और भोपाल में 80 फीसदी अपराध कम हो गया है। इससे पुलिस को भी राहत मिली है।

गौरतलब है कि एनसीआरबी की जब भी रिपोर्ट आती थी, मप्र बलात्कार, हत्या और चोरी-डकैती में सबसे आगे रहता था। लेकिन 24 मार्च से लॉकडाउन होने के कारण अपराधों के ग्राफ में एकाएक कमी आ गई है। इसकी एक वजह यह है कि अपराधियों में भी कोरोना वायरस का भय समा गया है और दूसरी वजह यह है कि पुलिस 24 घंटे चौकन्नी है। पहले 24 घंटे अपराधों की पड़ताल और उन्हें सुलझाने में व्यस्त रहने वाली पुलिस अब कोरोना वायरस के खिलाफ अभियान में जुटी हुई है।

केवल अपराधों में ही नहीं बल्कि सड़क हादसों में कमी आई है। जहां भोपाल और इंदौर में रोजाना दर्जनों सड़क हादसे होते थे वहीं अब कभी-कभार एकाध मामले ही आ पाते हैं। दरअसल, लॉकडाउन के बाद लोग घरों में हैं। इसका नतीजा यह है कि एक भी सड़क हादसे में किसी की मौत की सूचना नहीं है। शहर में वाहन चोरी की घटनाएं भी थम गई हैं। 24 मार्च से पहले शहर में बाइक चोरी करने वाले गैंग इस तरह सक्रिय थे कि रोजाना आधा दर्जन से अधिक बाइक चोरी करते थे। कोरोना के बाद सख्ती बढ़ी तो बाइक चोरी की घटनाएं भी कम हो गईं। पहले शहर में रोज किसी न किसी के साथ लूट, चोरी, मारपीट की एफआईआर दर्ज होती थी लेकिन अब अपराध की जगह पुलिस प्रीवेंटिव एक्ट की कार्रवाई कर रही है। पुराने शहर में पुलिस महामारी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई कर रही है।

सनसनीखेज घटनाओं से ज्यादा पुलिस आपसी विवाद सुलझाने में परेशान रहती थी। रोजाना 100 से ज्यादा मामले आपसी मारपीट, पड़ोसी से विवाद, पति-पत्नी में विवाद, शराब पीकर विवाद की सूचनाएं मिलती थीं। डायल 100 की पुलिस के अलावा थानों पर भी ऐसे मामलों की बहुतायत होती थी। लेकिन कोरोना के कारण यह सब थम गया है। दरअसल, हर तरफ कोरोना (कोविड-19) का खौफ है, इससे बचने के लिए हर कोई घरों में रहकर इससे मुक्ति पाना चाहता है। बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो संकट और जान जोखिम के इस समय में लड़ाई-झगड़े, चोरी, छेड़छाड़ और अवैध शराब के परिवहन में लगे हैं। लॉकडाउन और कोरोना के डर से जिले में अपराधों में कमी तो आई है, किंतु कुछ बदमाश अब भी सड़क पर घूम रहे हैं। खासकर शराब तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं।

राजधानी सहित अन्य शहरों में पुलिस इस कदर सतर्क है कि हर आने-जाने वाले की जांच हो रही है। ऐसे में अपराधियों के मंसूबे परवान नहीं चढ़ पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की सतर्कता को देखकर शहर के लोग भी उनका मनोबल बढ़ाने आगे आ रहे हैं। कई जगह तो लोग चौराहों पर तैनात पुलिस के जवानों को चाय-नाश्ता भी पहुंचा रहे हैं।

कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो अब इसका असर सामान्य जनजीवन पर नहीं बल्कि वनों की सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। कहीं भी पेड़ काटे जा रहे हैं। इमारती लकड़ी की तस्करी की आशंका बढ़ गई है। दरअसल वन विभाग में बीट गार्ड की संख्या पहले भी कम रही है। ऐसे में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए सूचना तंत्र विकसित की गई थी। गांव से जंगल के रास्ते या आसपास आवागमन करने वाले ग्रामीणों से वन विभाग के बीटगार्ड का संपर्क होता था। जंगल में किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियां होने पर सूचना विभाग को पहुंच जाती थी और जंगल कटने से पहले से संदिग्धों को या तो भगा दिया जाता था या फिर अपराध करते ही पकड़ लिया जाता था। अब लॉकडाउन में ग्रामीणों का निकलना बंद हुआ तो विभाग को जानकारी मिलना बंद हो गई। नुकसान यह हुआ कि जंगल में पेड़ कटने लगे।

● कुमार राजेन्द्र

इनकी सेवा को सलाम

कोरोना वायरस से एक तरफ पूरी दुनिया डरी सहमी है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस, प्रशासन, चिकित्सक, निकायों के अधिकारी-कर्मचारी, सफाई कर्मी बधाई के हकदार हैं क्योंकि इस विषम स्थिति में भी यह पूरी ईमानदारी के साथ अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। खासकर पुलिस जिस तरह सुबह से लेकर रात-रातभर सड़क पर खड़े होकर लॉकडाउन का पालन करवा रही है इसके लिए उन्हें सलाम। इस समय कई शहरों का पारा 35 के पास पहुंच गया है। ऐसे में पुलिस के जवान सूनी सड़कों के चौराहों पर ड्यूटी दे रहे हैं। आलम यह है कि इनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो अपने घर भी नहीं जा रहे हैं। राजधानी भोपाल के कई थानों का स्टाफ मुश्किल से 4 से 5 घंटे सो पा रहा है। कुछ थानों में तो स्टाफ ने रसोई बनानी शुरू कर दी है ताकि वे स्वयं के साथ ही जरूरतमंदों को भी खाना खिला सकें। पुलिस के अधिकारी और जवान जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने में भी जुटे हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं में लगे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी अपना पूरा समय मरीजों की सेवा में बिता रहा है। इनकी सतर्कता और मेहनत का ही परिणाम है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा मप्र में कोरोना वायरस से संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है।

विकास कार्य ठप

कोरोना वायरस महामारी इस सदी का सबसे बड़ा वैश्विक संकट है। इसका विस्तार और गहराई बहुत ज्यादा है। इस सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से पृथ्वी पर 7.8 अरब लोगों में से हर एक को खतरा है। इस बीमारी ने पूरे विश्व के जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है और सभी बाजारों को बाधित कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी से पैदा वित्तीय और आर्थिक संकट 2008-2009 की बड़ी मंदी के प्रभाव से ज्यादा हो सकता है। बर्लिन की दीवार के गिरने या लेहमैन ब्रदर्स के पतन की तरह कोरोना वायरस महामारी भी एक बड़ी घटना है। इसके दूरगामी परिणामों की हम आज केवल कल्पना ही कर सकते हैं।

अगर भारत के संदर्भ में देखें तो कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन से देश की पूरी अर्थव्यवस्था ही लॉक हो गई है। विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं। फैक्ट्री और निर्माण कार्य बंद होने से मजदूर पलायन कर रहे हैं। पलायन कर रहे मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। सरकारों ने मजदूरों के तीन महीने की खाने-पीने की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। मप्र सहित कई राज्यों ने मजदूरों के खातों में पैसे भी डाल दिए हैं। इससे मजदूरों की आर्थिक स्थिति तो सही हो जाएगी लेकिन देश का क्या होगा?

लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक भारत में 37.2 करोड़ लोगों की श्रमशक्ति है। इनमें से 22.8 फीसदी वैतनिक कर्मचारी, 24.9 फीसदी अनौपचारिक मजदूर और बचे हुए 52.2 फीसदी लोग स्वरोजगार से जुड़े हैं। अगर संख्या की बात करें तो 8.5 करोड़ वैतनिक कर्मचारी, 9.3 करोड़ अनौपचारिक मजदूर और 19.4 करोड़ लोग स्वरोजगार से जुड़े हैं। कोरोना वायरस के कारण सबके काम प्रभावित हुए हैं। अगर 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खत्म भी किया जाता है तो पलायन कर चुके मजदूरों को वापस आने में महीनों लग सकते हैं। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी।

मप्र में कोरोना वायरस के हमले से मेट्रो, स्मार्ट सिटी जैसे कई प्रोजेक्ट भी खतरे में पड़ गए हैं। एक दर्जन से ज्यादा स्मार्ट प्रोजेक्ट लॉकडाउन के कारण जहां पूरी तरह से ठप हो गए हैं। शहरभर में एक दर्जन से ज्यादा छोटे, बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनमें से कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्हें मई, जून और दिसंबर 2020 तक पूरे करने हैं, लेकिन कोरोना के कारण अब शायद ही दिसंबर तक प्रोजेक्ट पूरे हो पाए। जानकारों की मानें तो इससे उबरने में ही करीब 3 से 4 माह लगेंगे। केंद्र सरकार ने पहले चरण में स्मार्ट प्रोजेक्ट पूरे करने की समय-सीमा अप्रैल 2022 तक निर्धारित की है, लेकिन देशभर में जिस तरह से आर्थिक अस्थिरता का महौल बना है उसे देखते हुए विकास और निर्माण कार्य के लिए मिलने वाला आवंटन अब खटाई में पड़ता दिख रहा है।

कोरोनो वायरस ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के उन आर्थिक दोषों को भी उजागर किया है, जिनकी अभी तक शांति काल में अनदेखी करना बहुत आसान था। कोविड-19 महामारी वैश्विक आर्थिक गति की दिशाओं को भले ही मौलिक रूप से नहीं बदलेगी लेकिन यह कुछ ऐसी प्रवृत्तियों की गति को और तेज कर देगी, जो पहले से ही चल रही हैं। कोरोना वायरस विश्व के औद्योगिक विनिर्माण के मौजूदा मूल सिद्धांतों को कमजोर कर रहा है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप से समस्याओं से घिरी हुईं थीं। कोविड-19 ने अब इनमें से कई सप्लाई लिंक्स को तोड़ दिया है। कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में फैक्ट्रियां बंद होने से दूसरे निर्माताओं, अस्पतालों, फार्मेसियों, सुपर मार्केट और खुदरा स्टोरों में उत्पादों की कमी हो गई है। ई-कॉमर्स की दिग्गज अमेजन के प्लेटफार्म से जुड़ी केवल 45 प्रतिशत चीनी कंपनियां ही अभी सामानों की सप्लाई कर रही हैं। इसके कारण अमेजन ने इटली और फ्रांस में गैर जरूरी सामानों की आपूर्ति के आर्डर लेना रोक दिया।

वैश्वीकरण ने कंपनियों को दुनियाभर में विनिर्माण करने और वेयरहाउसिंग की लागतों को दरकिनार करते हुए अपने उत्पादों को बाजार में सीधे पहुंचाने की अनुमति दी है। कुछ दिनों से अधिक समय तक आलमारियों में पड़े रहने वाले सामानों को बाजार की विफलता माना जाता था। आपूर्ति किए जाने वाले सामानों को सावधानी से और वैश्विक स्तर पर निर्धारित स्थानों पर भेजना पड़ता है। कोविड-19 ने साबित कर दिया है कि वायरस न केवल लोगों को संक्रमित कर सकते हैं, बल्कि पूरी आर्थिक प्रणाली को ध्वस्त कर सकते हैं।

कोरोना वायरस महामारी के कारण अगर आने वाले समय में पश्चिमी देशों के व्यवसायों और एशियाई और अफ्रीकी देशों के श्रम बल की श्रृंखला कमजोर पड़ती है तो लंबी अवधि में संभवत: वैश्विक अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता घट जाएगी। इसके बदलने से वर्तमान अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बड़े दबाव में आ जाएगी। जो साफतौर पर पश्चिमी विकसित देशों के पक्ष में झुकी हुई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का यह जोखिम विशेष रूप से विकासशील देशों, आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों और गरीब लोगों के एक बड़े हिस्से के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इससे उनके लिए नई संभावनाओं और अवसरों का मार्ग खुल सकता है। इसके परिणाम-स्वरूप वैश्विक पूंजीवाद में एक नाटकीय नया चरण आ सकता है। जिसमें आपूर्ति श्रृंखलाओं को आस-पास ही रखा जाता है और भविष्य के आपात व्यवधानों से बचने के लिए गोदामों को ज्यादा सामान से भरा रखा जाता है। यह कंपनियों के हाल के मुनाफे में कटौती कर सकता है, लेकिन पूरी आर्थिक प्रणाली को अधिक लचीला बना सकता है। महामारी के बाद ज्यादा से ज्यादा कंपनियां अब यह जानने का प्रयास करेंगी कि उनकी मूल आपूर्ति कहां से आती है। सरकारें भी घरेलू उद्योगों की घरेलू बैकअप योजनाओं और भंडार के लिए रणनीतिक उद्योगों पर विचार कर रही हैं। इससे लाभप्रदता में गिरावट जरूर आएगी, लेकिन आपूर्ति स्थिरता में वृद्धि होने का उद्देश्य पूरा होना चाहिए।

● **धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया**

रोटी के लिए अवैध खनन

अवैध खनन बुंदेलखंड में रोजगार के लिए तरस रहे गरीब-गुरबों के लिए यह दो वक्त की रोटी का 'जुगाड़' बन गया है। रेत खनन से मिल रहे रोजगार की वजह से वे अब कमाने परदेस नहीं जाते। बुंदेलखंड में नदियों और खेतों में पड़ी बालू का अवैध खनन चरम सीमा पर है। जहां नदियों में भारी-भरकम मशीनों से खनन किया जा रहा है, वहीं नदियों की तलहटी वाले खेतों की बालू किसान या तो समझौते में माफियाओं को बेच रहे हैं या फिर खुद ई-रिक्शा और मोटरसाइकिल से फेरी लगाने वालों को बेची जा रही है। गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मप्र के छह जिलों में हजारों परिवारों को बालू के अवैध खनन से रोजगार मिला हुआ है और ये परिवार अपनी दो वक्त की रोटी का 'जुगाड़' इसी से कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई जगह तो साग-सब्जी की तरह अब नदी के किनारे 'बालू मंडी' भी लगनी शुरू हो गई है। वहां से ई-रिक्शा और मोटरसाइकिल वाले बालू खरीदकर बाजार में बेच रहे हैं। इन्हीं बालू मंडियों के अगल-बगल चाय, समोसा और परचून की अस्थायी दुकानें भी हैं। नरैनी तहसील क्षेत्र के गौर-शिवपुर गांव के नन्ना निषाद बताते हैं कि उनके गांव में करीब पचास युवक ऐसे हैं, जो मोटरसाइकिल से यह धंधा करते हैं। ये लोग किसानों के खेतों से 10 रुपए प्रति बोरी कीमत में बालू खरीदकर नरैनी कस्बे में उसे 35 रुपए प्रति बोरी की दर से बेचकर प्रतिदिन करीब 800 रुपए कमा रहे हैं। इससे उनके परिवार का दैनिक खर्च और खाने-पीने का जुगाड़ आराम से हो जाता है।

बदहाली से जूझ रहे बुंदेलखंड में एक तरफ जहां ज्यादातर आबादी को दो जून की रोटी मयस्सर नहीं है, तो वहीं **रेत और पत्थर का** अवैध खनन करने वाले माफिया खनिज से मालामाल हो रहे हैं। इनसे जुड़े अन्य सरकारी और गैर सरकारी लोग अवैध खनन की इस गाढ़ी मलाई का जमकर मजा ले रहे है। खनन में सत्ता पक्ष के लोगों के शामिल होने से प्रशासन भी खनन माफिया के सामने बौना साबित हो रहा है। महोबा में पहाड़ों को जमींदोज करके ये खनिज माफिया रातोंरात अमीर तो बन जाते हैं लेकिन प्रकृति से छेड़छाड़ का खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ता है। दैवीय आपदाओं से ग्रस्त बुंदेलखंड में खनिज संपदा की लूट मची हुई है जिसे रोकने में न तो प्रशासन कामयाब हो रहा है और न शासन। योगी सरकार को तीन साल पूरे हो गए हैं, लाख कोशिशों के बाद आज भी अवैध खनन बदस्तूर जारी हैं। जिले से आज भी प्रतिदिन अवैध बालू और गिट्टी से लदे सैकड़ों ट्रकों की आवाजाही होती है और पूरी रात अवैध खनन का खेल चलता है। अवैध खनन के पूरे खेल में कहीं न कहीं प्रशासनिक दखल अंदाजी भी रहती है। बुंदेलखंड का महोबा जनपद ग्रेनाईट पत्थरों की अपार खनिज संपदा से भरपूर है। खनिज के इस भंडार पर माफियाओं और सफेद पोशों की गिद्ध रूपी नजर हमेशा रहती है और सरकारी मुलाजिमों से साठ-गाठ करके ये माफिया अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। आपको बता दें कि महोबा चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहां का कबरई क्षेत्र प्रदेश में पत्थर मंडी के नाम से जाना जाता है। कबरई में इन पहाड़ों का पट्टा कराकर अवैध रूप से पहाड़ों में हैवी ब्लास्टिंग की जाती है जिसे लाखों रुपए की कीमत के पत्थरों को क्रेशर के माध्यम से गिट्टी बनाकर माफिया करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जबकि यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पहाड़ों में हैवी ब्लास्टिंग गैर कानूनी है। बावजूद इसके सफेदपोश लोगों की शह पर ये धंधा बखूबी चल रहा है। इन पहाड़ों में काम करने वाले मजदूर उड़ती डस्ट से जहां एक ओर टीबी का शिकार हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ों से गिरकर मजदूरों की मौत होना एक आम बात है। लेकिन प्रशासन और खनिज विभाग सिर्फ खानापूर्ति ही कर रहा है। ऐसे में महोबा में हो रहे अवैध खनन के चलते यहां से पहाड़ों का वजूद मिटता जा रहा है। यूं तो बुंदेलखंड के सभी जनपदों में खनन कार्य होता रहता है। जालौन, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट में नदियों का सीना चीरकर खनन किया जाता है। पहाड़ों पर हो रहे खनन में सत्ता पक्ष के लोगों के शामिल होने की बात भी लोग दबी जुबान में बता रहे हैं। लेकिन कोई भी खुलकर बोलने से डरता है। एक आंकड़े की बात करें तो एक वर्ष में तकरीबन आधा सैकड़ा मजदूरों की मौतें हो जाती हैं। ये वो मौतें है जिनका न तो कोई मुकदमा होता है और न ही इनके परिवार को पहाड़ धारकों द्वारा उचित मुआवजा दिया जाता है। बस दबाव से मामले शांत हो जाते है। यही हाल रहा तो पहाड़ों का नामों-निशान भी मिट जाएगा। महोबा की पत्थर मंडी में पहाड़ पट्टेधारक खादी और खाकी से गठजोड़ कर पहाड़ों को निस्तनाबूद कर रहे हैं।

● **सिद्धार्थ पांडे**

पहाड़ों पर जारी है अवैध खनन

महोबा में तकरीबन दो सैकड़ा पहाड़ हैं जिनमें खनन कार्य मनको के विपरीत जारी है। समाजसेवी संगठन और जानकार पहाड़ों पर हो रहे खनन को घटक बताते हैं और इसके दुष्परिणाम होने की बात कहते हैं लेकिन इन चेतावनियों से परे शासन और प्रशासन इस अवैध कारोबार पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। पहाड़ों पर खनन और क्रेशर से उठती डस्ट खेतों को बंजर कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बालू में शासन-प्रशासन की सख्ती से बालू की दरों में बढ़ोत्तरी हुई है। घाटों के पट्टे ई-टेंडरिंग होने से इस पर लगाम तो लगी है मगर कई स्थानों से चोरी छिपे बालू डंप की जा रही है। नतीजन बालू के दाम आसमान छू रहे हैं। एक वर्ष पूर्व ट्राली भरी बालू 1700 रुपए तक की मिल जाती थी आज वह 3500 की भी बमुश्किल मिल पा रही है। आम आदमी सहित सरकारी काम और ठेकेदार भी इस समस्या से परेशान हैं। महोबा की गिट्टी उद्योग नगरी कबरई से प्रतिदिन हजारों की तादात में ट्रकों से गिट्टी प्रदेश के अन्य जिलों में पहुंचाई जाती है। वर्तमान में महोबा जिले में गिट्टी के 85 व मोरंग का एक वैध पट्टा संचालित है। लेकिन जिले में कबरई और उसके आसपास के क्षेत्रों में गिट्टी के लिए सैकड़ों की तादाद में पहाड़ों पर अवैध ब्लास्टिंग कर माइनिंग की जाती है। तो वहीं बालू माफियाओं द्वारा पूरी रात अवैध बालू का खनन किया जाता है। खास बात तो यह है कि चंद्रावल बांध के लिए पूर्व सरकार में 19 खदानों को बंद करने के आदेशों के बावजूद भी इन खदानों में चोरी छिपे खनन हो रहा है। सत्ता की हनक और शासन में ऊंची पकड़ रखने वाले अवैध खनन व्यावसायियों पर कहीं न कहीं प्रशासन को भी नतमस्तक होना पड़ता है। कहीं न कहीं इस तरह के लोग सरकार की छवि धूमिल करने में लगे हुए हैं।

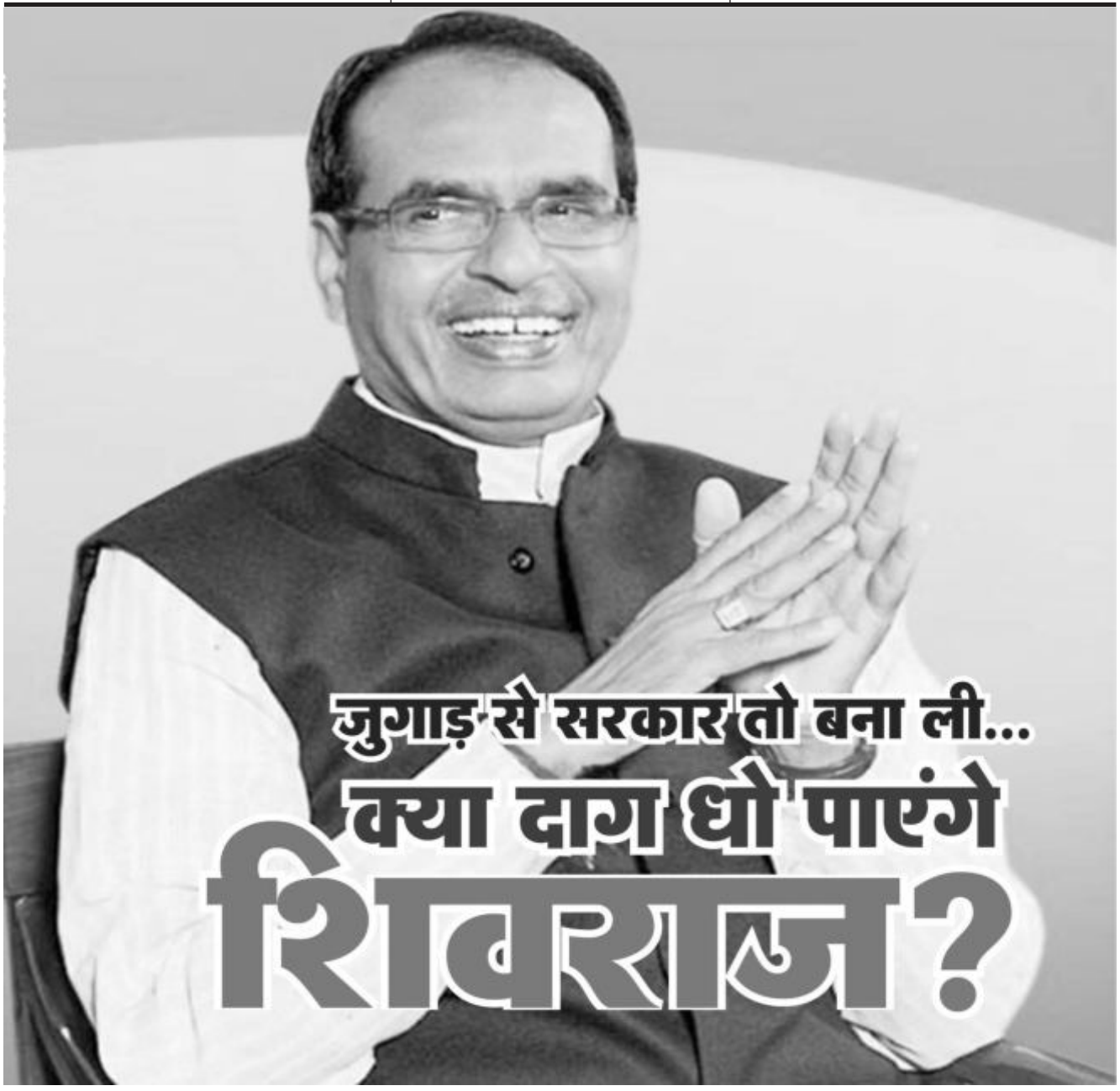

जुगाड़ से सरकार तो बना ली... क्या दाग धो पाएंगे शिवराज?

मप्र में शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच दिया है। भाजपा को अबकी बार सत्ता कांग्रेसियों की आपसी फूट के कारण मिली है। 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने भाजपा को नकार दिया था। इसकी एक वजह यह थी कि भाजपा की 15 साल पुरानी सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप थे। खुद शिवराज सिंह चौहान पर कई आरोप थे। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या इस बार शिवराज सिंह चौहान अपने ऊपर लगे दाग धो पाएंगे?

● राजेंद्र आगाल

गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ते वक्त शिवराज ने कहा था कि **'टाइगर जिंदा है, लौटकर जरूर आऊंगा'**। अपनी कही हुई बात को सच साबित करते हुए मध्यप्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए प्रदेश की सत्ता की कमान अपने हाथ में ले ली है। 2005 से 2018 तक लगातार 13 साल में तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह ने 23 मार्च को रात 9 बजे राजभवन में चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस तरह शिवराज सिंह के मध्यप्रदेश के 32वें मुख्यमंत्री बनने के साथ ही प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है, जब किसी ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। प्रदेश में शिवराज सिंह के अलावा अब तक अर्जुन सिंह और श्यामाचरण शुक्ल तीन-तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सत्ता संभालते ही शिवराज सिंह चौहान के सामने चुनौतियों का पहाड़ है।

वर्तमान समय में देश और दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही है। ऐसे में शिवराज के सामने प्रदेश को इस संक्रमण से बचाने की चुनौती है। इस चुनौती से पार पाते ही उनके सामने आर्थिक तंगी होगी। इस स्थिति में शिवराज को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। साथ ही अपनी पूर्ववर्ती सरकार पर लगे भ्रष्टाचार और अपने ऊपर लगे दाग को धोने की भी चुनौती रहेगी। गौरतलब है कि अगस्त 2019 में शिवराज सिंह चौहान ने जब राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर कमलनाथ की सरकार पर हमला किया था कि मेरा मध्यप्रदेश ऐसा नहीं था, आपने मध्यप्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया है। उस पर कमलनाथ ने कहा था कि आपकी सरकार के समय लगे दागों को धोने में लगा हूं। आखिर वे कौन-से दाग थे, जिन्हें धोने की बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की थी। आज यह सवाल प्रदेश की जनता के मन में उठ रहा है।

इन पर उठते रहेंगे सवाल

अगर कांग्रेस के आरोपों की मानें तो भाजपा के पूर्व के 15 साल के शासनकाल में 197 बड़े घपले-घोटाले हुए थे। इनमें से कुछ के छींटे शिवराज सिंह चौहान और उनके परिजनों पर भी पड़े थे। इनमें डंपर कांड, अवैध रेत खनन, व्यापमं, परिवहन आरक्षक भर्ती, नर्मदा किनारे पौधरोपण, ई-टेंडरिंग, मंदसौर किसान गोलीकांड ऐसे मामले थे जिसने सरकार की साख गिरा दी थी। वहीं शिवराज सिंह चौहान द्वारा अधिकारियों-कर्मचारियों के एक वर्ग को खुश करने के लिए 'कोई माई का लाल' कहना, अधिकारियों को चमगादड़ की तरह टांग देना ये ऐसे मामले हैं जो इस बार भी शिवराज के लिए चुनौती बनेंगे। विपक्षी कांग्रेस ही नहीं जनता भी चौथी बार मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान से जवाब मांगेगी, कि उन्होंने इसके लिए क्या किया।

अलग तरीके की सरकार कैसी?

शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही कहा था कि अब तक प्रदेश में जिस तरह सरकार चल रही थी आगे उस तरह नहीं चलेगी। मैं अलग तरीके से सरकार चलाऊंगा। ऐसे में हर एक के मन में यह सवाल उठ रहा है कि वह अलग तरीके की सरकार कैसी होगी। क्योंकि प्रदेश की साढ़े सात करोड़ आबादी ने उन्हें 13 साल सरकार चलाते देखा है। उस समय उनके शासन में ऐसा कुछ अलग नजर नहीं आया जिससे यह कहा जा सके कि उनकी शासन प्रणाली अलग तरह की रही है। एक बात जरूर है कि इस बार उनको सत्ता वोट देने वाले न सही, वोट लेने वालों के ही दम पर मिली है। यानि कांग्रेस के बागियों के कारण वे मुख्यमंत्री बन पाए हैं।

तीसरी पारी जैसी न हो सरकार

उमा भारती और बाबूलाल गौर के आधे-अधूरे वाले कार्यकाल के दौर में जब शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता संभाली थी, तब लग रहा था कि भाजपा को सरकार चलाना ही नहीं आता। क्योंकि जब शिवराज ने मुख्यमंत्री पद पाया उस समय उनके पास प्रशासनिक अनुभव नगण्य था। वे मुख्यमंत्री जैसे बड़े संवैधानिक पद पर सीधे आए थे। लेकिन उन्होंने सारे कयासों को दरकिनार कर मुख्यमंत्री के रूप में ऐसी सियासी पारी का आगाज किया जो सुखद रही और उन्हें एक लंबी रिकार्डतोड़ पारी खेलने का मौका मिला। जाहिर है वह सब उनकी योग्यता, सहजता, जनता से करीबी और मेहनत का नतीजा था। शुरू के 8 साल का वह समय वाकई एक सच्चे जन प्रतिनिधि के कामकाज का अनुभव कराने में सफल रहा था। यही वजह रही कि शिवराज के चेहरे के कारण ही राज्य की जनता ने लगातार तीसरी बार यहां भाजपा की सरकार बनने का रास्ता साफ किया था। लेकिन उनकी तीसरी पारी ऐसी बिगड़ी कि वह लगातार बिगड़ती चली गई।

शिवराज सरकार की तीसरी पारी में बड़े-बड़े भ्रष्टाचार उजागर होने लगे। खुद मुख्यमंत्री और उनके नाते-रिश्तेदारों पर आरोप लगने लगे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान में एक दंभ भी नजर आया। वे मध्यप्रदेश ही नहीं देशभर में जहां भी जाते उनके भाषणों में अहंकार झलकने लगा था। आलम यह था कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने कई बार मुख्यमंत्री, सरकार और नौकरशाहों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। लेकिन अब सरकार के मुखिया के ही कदम बहक गए हों तो सरकार और नौकरशाह कैसे नहीं बहकते। इसका परिणाम यह हुआ

ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे

फिल्म शोले का गीत 'ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे' शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर पर सटीक बैठता है। दोनों के बीच दोस्ती का ही परिणाम है कि शिवराज सिंह चौहान को चौथी बार भी मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। दरअसल, मध्यप्रदेश की राजनीति में एक समय शिवराज और तोमर की जोड़ी काफी चर्चित थी। शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में नरेंद्र सिंह तोमर दो बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इन दोनों नेताओं में जितना सामंजस्य दिखा उतना अन्य किसी नेता में नहीं दिख पाया है। दोनों की जोड़ी ने प्रदेश में कई चुनाव और उपचुनाव आसानी से जीते हैं। ऐसे में जब कांग्रेस की सरकार जाने के बाद मप्र के मुख्यमंत्री की दौड़ शुरू हुई तो दावेदारों की कतार लग गई। इस दावेदारी में नरेंद्र सिंह तोमर स्वयं भी थे। लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने अपने मित्र शिवराज सिंह चौहान का नाम आलाकमान के सामने प्रस्तुत कर दिया।

शिवराज ही क्यों?

15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस 15 माह में ही सत्ता से बाहर हो गई। इसकी वजह यह रही कि एक तरफ जहां कांग्रेस में शुरू से फूट रही, वहीं दूसरी तरफ भाजपा उनके बीच की खाई को और बढ़ाती रही। कांग्रेसियों के बीच लगातार बढ़ती खाई को बढ़ाने और उसे और गहरी करने में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पाले में लाकर सत्ता पलट कर दी। लेकिन जब सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने की बारी आई तो लॉटरी शिवराज सिंह चौहान के नाम लग गई। दरअसल, प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह और शिवराज सिंह चौहान दावेदार बताए जा रहे थे। लेकिन आलाकमान ने शिवराज के नाम पर मुहर लगा दी। दरअसल, शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं उनमें विरोधियों को साधने की अपूर्व क्षमता है। वे मिलनसार नेता हैं। साथ ही जो अन्य नेता सीएम पद के दावेदार थे, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिनका पूरे प्रदेश में जनाधार हो। यही नहीं विपक्ष में होने के बाद भी शिवराज लगातार सक्रिय रहे। आलाकमान द्वारा केंद्रीय संगठन में उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद भी उन्होंने मप्र से मुंह नहीं मोड़ा। वे संघ की पसंद भी हैं। सबसे बड़ी बात शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता, राजनीतिक और सामाजिक समीकरण ने उनका साथ दिया और अब वो चौथी बार प्रदेश के सीएम बने। मध्य प्रदेश में उनका बड़ा जनाधार है। कमलनाथ सरकार में रहे जिन 22 कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं उन पर अभी उपचुनाव होना है। जबकि 2 सीटों आगर मालवा और जौरा सीट का उपचुनाव पहले से प्रस्तावित है। ऐसे में उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए शिवराज जैसा लोकप्रिय चेहरा सामने होना जरूरी है। शिवराज का नाम तय होने की एक वजह जातिगत समीकरण भी माना जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष पद पर अभी ब्राह्मण और सामान्य वर्ग से क्रमशः वीडी शर्मा और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव हैं। इसलिए सामान्य वर्ग के सीएम पद के संभावित नाम नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा पर मुहर लगना मुश्किल था। शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग से आते हैं। इन्हीं सब कारणों ने शिवराज की राह आसान कर दी। शिवराज को मुख्यमंत्री बनाए जाने की एक और वजह है कोरोना वायरस का संकट। प्रदेश का खजाना खाली है, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान भलीभांति जानते हैं कि किस तरह इस संकट की घड़ी में काम किया जा सकता है। वे इस संकट से निपटने के लिए जुट गए हैं और औद्योगिक घरानों से इस संकट की घड़ी में सहयोग करने की अपील कर चुके हैं।

कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया।

माई का लाल भूले नहीं लोग

शिवराज सिंह चौहान के तीसरे कार्यकाल में कई अप्रिय घटनाएं हुईं, जिसने उस जनता के अंतस को झंकझोर दिया जो उन पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। शिवराज सिंह चौहान को अपने बीच का व्यक्ति समझने वाली जनता उन्हें अपना दुश्मन समझने लगी। जो शिवराज बिना भेदभाव के हर जन को अपना समझते थे उन्होंने वोट बैंक की खातिर यह बोल दिया कि कोई माई का लाल...। उनके इस कथन से प्रदेश में आक्रोश इस कदर पनपा कि लोग अपने दोस्त को भी दुश्मन समझने लगे। शिवराज ने चौथी बार सत्ता संभाली है तो उन्हें एक बार वक्त निकालकर 'कोई माई का लाल...' वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। क्योंकि प्रदेश की जनता माई का लाल भूली नहीं है।

यही नहीं उन्हें अपने पिछले पांच साल के कार्यकाल का एक बार स्मरण जरूर करना चाहिए। जिससे यह साफ हो जाएगा कि उनके इर्द-गिर्द किस तरह के लोगों की टोली कुण्डली मारकर बैठी थी। जिनके सुझाव पर शिवराज सिंह चौहान ने ऐसी घोषणाएं की, जो पूरी तो नहीं हुईं, लेकिन उनकी साख गिरा गईं। यही नहीं इस दौरान उन्हें अपनी छवि चमकाने के लिए खजाना लुटाने का शौक कुछ इस कदर चढ़ा कि वे प्रदेश को लगभग पौने 2 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डुबो गए थे। हद तो तब हो गई, जब खुद को किसान पुत्र बताकर गौरवान्वित होने वाले शिवराज के शासनकाल में मंदसौर में किसानों को गोली खानी पड़ी। यही नहीं इस दौरान किसानों को खुश करने के लिए शुरू की गई भावांतर योजना का हश्र भी देखना होगा। जिससे उन्हें सबक मिलेगा कि उन्होंने अपने आखिरी पांच साल किस तरह शासन किया।

5 साल जनता की नहीं सुनी

शिवराज सिंह चौहान ने चौथी पारी में अलग तरीके की सरकार चलाने की बात तो कही है, लेकिन उन्हें अपने आखिरी पांच साल के शासनकाल का भी अध्ययन करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने जनता की एक नहीं सुनी और अपने चहेतों के चंगुल में फंसे रहे। इस दौरान एक तरफ उन्होंने नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नर्मदा परिक्रमा की, दूसरी तरफ नर्मदा में खुलेआम अवैध खनन होता रहा। आलम यह था कि चौहान लिखे डंपर रात-दिन रेत लेकर दौड़ रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अगर कोई अधिकारी उन डंपर को रोक देता था तो उसका तत्काल तबादला हो जाता था। नर्मदा की छाती पर जेसीबी रात-दिन चलती रही और वे दावे करते रहे कि नर्मदा में अवैध खनन बिल्कुल नहीं हो रहा है।

शिवराज सिंह चौहान की साख अपने साले संजय सिंह मसानी के कारण भी गिरी। कांग्रेसी नेता बताते हैं कि जब शिवराज सांसद थे और वे साउथ एवेन्यू में रहते थे, उस वक्त मसानी के पास केवल दो टैक्सी थीं। शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकार में संजय का दखल बढ़ गया था। सूत्र यह भी बताते हैं कि रेत और बॉक्साइट के खनन के कारण वे चर्चा में आए। बताया जाता है कि बालाघाट में संजय के संरक्षण में जमकर अवैध खनन हुआ। लेकिन बाद में यही संजय शिवराज सिंह चौहान को धोखा दे गए। इसलिए शिवराज सिंह चौहान को अपनी चौथी पारी में जहां अपने पूर्व के दाग धोने की चुनौती है वहीं एक ऐसी सरकार चलाने का उदाहरण भी देना होगा जिससे लोग उनकी पुरानी गलतियों को भूल सकें। हालांकि वर्तमान में उनके सामने कोरोना वायरस से निपटने की चुनौती है और वे इस दिशा में बेहतरीन काम कर रहे हैं।

अधर में मंत्रिमंडल!

मप्र की सत्ता पर शिवराज सिंह चौहान काबिज होने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन मंत्री बनने की चाहत रखने वाले विधायकों और नेताओं को करीब एक महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है। देश में कोरोना के बढ़ते खतरों को देखते हुए 14 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉकडाउन है। ऐसे में शिवराज का कैबिनेट गठन लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही संभव है। उधर, मंत्री बनने की आस लगाए बैठे नेताओं में बेचैनी बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण के मामले मध्य प्रदेश में भी तेजी से आ रहे हैं। राज्य में अब तक कोरोना वायरस से 64 लोग पीड़ित हैं और 5 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा सूबे में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले पिछले दिनों में सामने आए हैं। इससे शिवराज सरकार की चिंता बढ़ गई। ऐसे में शिवराज सरकार की पहली प्रथामिकता कोरोना वायरस को हराना है न कि मंत्रिमंडल का गठन और विस्तार।

शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा था, मेरे और भाजपा की सरकार के सामने फिलहाल मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती कोरोना वायरस को फैलने से कैसे रोका जाए, ये है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकेत भी दे दिए हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही कैबिनेट गठन और मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने भाजपा विधायकों को पहले ही कह रखा है कि सभी अपने-अपने घरों और विधानसभा क्षेत्र में रहें। अब तो 14 अप्रैल तक लॉकडाउन भी है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। इस हिसाब से सरकार में मुख्यमंत्री सहित ज्यादा से ज्यादा 35 विधायक मंत्री बन सकते हैं। शिवराज की नई सरकार में सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कवायद होगी। क्षेत्रीय स्तर पर प्रदेश के सभी संभागों से मंत्री बनाने के साथ सामाजिक समीकरण के स्तर पर क्षत्रिय, ब्राह्मण, पिछड़े, अनुसूचित जाति और आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व दिए जाने की संभावना है।

कमलनाथ सरकार के 6 मंत्रियों समेत 22 विधायकों के इस्तीफा देने से ही मध्य प्रदेश में शिवराज को सरकार बनाने का अवसर मिला। इनमें प्रभुराम चौधरी, तुलसी सिलावट, इमरती देवी, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर और महेंद्र सिंह सिसोदिया मंत्री थे, जिन्होंने इस्तीफा देकर भाजपा की सरकार तो बनवा दी। ऐसे में अब किए गए वादों को पूरा करने की बारी शिवराज सरकार और भाजपा की है। इस लिहाज से शिवराज सरकार में भी इनका मंत्री बनना पूरी तरह से तय है। इसके अलावा कांग्रेस से बगावत करने वाले बिसाहूलाल सिंह, ऐंदल सिंह कंसाना, हरदीपसिंह डंग और राज्यवर्धन सिंह भी मंत्री पद के दावेदारों में शामिल हैं। इन नेताओं ने कमलनाथ सरकार से बगावत ही इसीलिए की थी, क्योंकि कमलनाथ ने इन्हें मंत्री नहीं बनाया था। ऐसे में इन्हें साधकर रखने के लिए शिवराज मंत्री पद का इनाम दे सकते हैं। हालांकि शिवराज कैबिनेट में मंत्रियों के चयन प्रक्रिया में ज्योतिरादित्य सिंधिया की अहम भूमिका होगी। बागियों में उन्हें ही मंत्री बनाया जाएगा, जिन पर सिंधिया मुहर लगाएंगे। ऐसे में अब देखना है कि 22 में से कितने नेताओं को मंत्री बनाया जाता है।

मध्य प्रदेश में 15 महीनों से सत्ता से दूर भाजपा में भी मंत्री पद के दावेदारों की फेहरिस्त अच्छी खासी लंबी है। कमलनाथ सरकार गिराने में बेहद अहम भूमिका निभाने वाले नरोत्तम मिश्रा का मंत्री बनना तय है। इसके अलावा पिछली शिवराज सरकार में मंत्री रहे नेता भी दौड़ में माने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष रहे गोपाल भार्गव, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, अरविंद सिंह भदौरिया, राजेंद्र

क्या चूक जाएंगे चौहान!

शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड तो बना लिया है लेकिन उनके सामने बड़ी चुनौती अगले 6 महीने में आने वाली है। 6 महीने के अंदर ही शिवराज सिंह चौहान के सामने उपचुनाव में भाजपा की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा का रुख करने वाले 22 विधायकों और दो अन्य रिक्त सीटों पर उपचुनाव होंगे। कुल 24 सीटों पर उपचुनाव मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार और खुद शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक जीवन की दिशा तय करेंगे। चौहान के सामने यह चुनौती होगी कि जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें कम से कम 10 सीटों पर भाजपा को जीत दिलाना होगा। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो शिवराज सिंह की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी और भाजपा के हाथ से आया हुआ राज्य निकल जाएगा। कर्नाटक में भाजपा ने यह करामात कर दिखाया था। वहां कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों और मंत्रियों के इस्तीफा देने से खाली हुए सीटों पर जब उपचुनाव हुए तब मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने भाजपा को जीत दिलाकर अपनी सरकार की स्थिरता को सुनिश्चित किया था। किंतु मध्यप्रदेश के मामले में स्थिति इतनी आसान नहीं है। मध्य प्रदेश में सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होता आया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 22 सीटों पर भाजपा को हराया था। यहां से कांग्रेस के जो प्रत्याशी जीते थे उनमें से ज्यादातर को इस बार भाजपा टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारेगी। इस वजह से भाजपा के कैडर की नाराजगी स्वाभाविक होगी। इन 22 सीटों पर 2018 के चुनाव में भाजपा के जो प्रत्याशी थे वह उपचुनाव के लिए दोबारा टिकट की उम्मीद में होंगे।

शुक्ला, विश्वास सारंग, संजय पाठक, कमल पटेल, हरिशंकर खटीक, गौरीशंकर बिसेन, अजय विश्नोई, मालिनी गौड़, मीना सिंह, नीना वर्मा जैसे भाजपा के कई विधायक हैं, जिनके मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के पूरी संभावना है।

शिवराज सिंह चौहान को सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल है। यही वजह है कि निर्दलीय विधायकों ने भी मंत्री पद के लिए अपने-अपने समीकरण सेट करने शुरू कर दिए हैं। प्रदीप जायसवाल ने तो पहले ही भाजपा सरकार में शामिल होने की बात कहकर माहौल गर्मा रखा है। बसपा और सपा के सदस्य भी दावेदारी में पीछे नहीं हैं। इसके अलावा अन्य निर्दलीय विधायक भी जुगाड़ लगाने में जुट गए हैं, जिनमें ठाकुर सुरेंद्र सिंह नवल सिंह (शेरा भैया) भी शामिल हैं।

वैश्विक महामारी कोरोना संकट के चलते देशभर में लॉकडाउन है। साथ ही सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने भी उपचुनाव एवं राज्यसभा चुनाव स्थगित कर दिए हैं। ऐसे में मप्र से भाजपा के टिकट पर राज्यसभा जाने वाले ज्योतिरात्यि सिंधिया, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का राज्यसभा सदस्य चुना जाना फिलहाल टल गया है। साथ ही कमलनाथ सरकार को गिराकर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले सिंधिया समर्थक 6 पूर्व मंत्रियों का भी फिर से मंत्री बनने के सपने पर लॉकडाउन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल का विस्तार कब करेंगे, यह तय नहीं हो पा रहा है।

शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद सिंधिया समर्थकों को उम्मीद थी कि वे भी एक हफ्ते के भीतर मंत्री बन जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार लॉकडाउन 31 मार्च तक किया था। तब ऐसी संभावना थी कि अप्रैल के पहले हफ्ते में मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। लेकिन लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल तक बढ़ाए जाने के बाद अब इससे पहले मंत्रिमंडल के गठन की संभावना कम ही है। ऐसे में सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्रियों को लंबा इंतजार करना पड़

सकता है। हालांकि वे अपने क्षेत्र में जाने की बजाय भोपाल में ही हैं। वहीं सिंधिया को भी राज्यसभा पहुंचने की उम्मीद थी। यदि चुनाव स्थगित नहीं होता तो वे राज्यसभा सदस्य बन गए होते। राज्यसभा सांसद प्रभात झा और सत्यनारायण जटिया अगले महीने 20 अप्रैल को अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। ऐसे में सिंधिया राज्यसभा सदस्य की शपथ लेते। इसके बाद उनके केंद्रीय मंत्री बनने की संभावना बनती। हालांकि मौजूदा हालात में सिंधिया और उनके समर्थकों के सपनों पर फिलहाल पानी फिरता दिखाई दे रहा है।

भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि पार्टी विधायक एवं सिंधिया समर्थकों को विभाग बांटने को लेकर दिल्ली में मंथन चल रहा है। जिस दिन शिवराज सिंह चौहान ने आनन-फानन में शपथ ली थी, उस समय हाईकमान यह तय नहीं कर पाया था कि कितने विधायकों को मंत्री बनाना है। क्योंकि सिंधिया समर्थक एक पूर्व मंत्री और भाजपा के एक वरिष्ठ विधायक को भी उपमुख्यमंत्री बनाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। फिलहाल कोरोना संकट के चलते देश 14 अप्रैल तक के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन है। ऐसे में भाजपा हाईकमान मंत्रिमंडल विस्तार की अनुमति नहीं दे रहा है। जिसकी वजह यह बताई जा रही है कि यदि लॉकडाउन के दौरान मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो फिर भाजपा पर सत्ता के लिए लॉकडाउन का उल्लंघन करने का आरोप लगेगा। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे राज्यों से मजूदरों के भीड़ के रूप में घर लौटने, शहरों में रोजमर्रा की चीजों के लिए लोगों के बाहर निकलने से लॉकडाउन का उल्लंघन होने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा है। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन खत्म होने तक मप्र में मंत्रिमंडल के गठन की संभावना कम ही है। कमलनाथ की सरकार गिराने वाले सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों के सपनों पर भी पानी फिरता दिखाई दे रहा है। बैंगलुरु से लौटने के बाद सिंधिया समर्थक पूर्व विधयाक अपने क्षेत्र में नहीं गए हैं। इस्तीफा देने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि वे छह महीने के भीतर फिर से विधायक बन जाएंगे। कोरोना संकट के चलते वे जनता के बीच भी नहीं जा पा रहे हैं। फिलहाल उपचुनाव कब होगा, यह भी तय नहीं है।

22 सीटों पर उपचुनाव भाजपा के लिए चुनौती

कांग्रेस के 22 बागी विधायकों की सदस्यता खत्म हो गई है और वे भाजपा में शामिल हो गए हैं। इन 22 सीटों पर उपचुनाव होंगे। लेकिन ये उपचुनाव भाजपा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं हैं। सबसे पहली चुनौती कि इन सभी 22 पूर्व विधायकों को कांग्रेस के नाम पर वोट मिला था। दूसरी चुनौती यह कि भाजपा इन सीटों पर अपने नेताओं को टिकट दे या इन बागियों को। अगर भाजपा 22 बागियों को टिकट देती है तो पार्टी में असंतोष बढ़ेगा। इसका खामियाजा प्रत्याशी को उठाना पड़ सकता है। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के ये 22 विधायक अपनी सीटों पर औसतन 15 प्रतिशत वोटों के अंतर से जीते थे। वहीं, इन 22 में से 20 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे। 22 में से 11 सीटों पर जीत और हार का अंतर 10 प्रतिशत से भी कम था। ऐसे में भाजपा यदि कांग्रेस के बागियों को टिकट देती है तो उसके पूर्व प्रत्याशी विरोध में मैदान में उतर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के 22 बागी विधायक अगर दोबारा चुनाव लड़ेंगे, तो वे उन्हीं सीटों से लड़ेंगे, जिससे वे 2018 के विधानसभा चुनाव में लड़े थे। पिछली बार तो ये विधायक कांग्रेस के टिकट पर खड़े हो गए थे, लेकिन इस बार उन्हें भाजपा की टिकट पर या भाजपा की मदद से लड़ना होगा। इसका मतलब हुआ कि इन सीटों से भाजपा के जो उम्मीदवार पिछली बार लड़े थे, उनका टिकट इस बार कटेगा। इससे इस बात की पूरी संभावना है कि जिन भाजपा नेताओं का टिकट कटेगा, वो सभी कांग्रेस से भाजपा में आए बागी विधायकों के लिए चुनौती बनेंगे ही बनेंगे। अब देखना यह है कि भाजपा इस चुनौती से किस रणनीति के साथ निपटती है। उधर, कांग्रेस भी इन सीटों को जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी की कोशिश है कि उपचुनाव में वह इन सीटों को जीतकर भाजपा से सत्ता वापस ले ले।

बदहाली के शिकार हैं सरकारी स्कूल

देश के 40 फीसदी से भी ज्यादा सरकारी स्कूलों में न तो बिजली है और न ही खेलने का मैदान। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबद्ध संसदीय समिति की ताजा रिपोर्ट से इसका पता चला है। समिति ने स्कूल शिक्षा विभाग के बजट में 27 फीसदी कटौती के लिए भी सरकार की आलोचना की है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि कोई दशक पहले शिक्षा का अधिकार कानून के लागू होने के बावजूद सरकारी स्कूलों की हालत इतनी दयनीय क्यों है और लाखों छात्र बीच में ही स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबद्ध संसदीय समिति ने बीते सप्ताह संसद में जो रिपोर्ट पेश की है वह देश में सरकारी स्कूलों की दयनीय हालत की हकीकत पेश करती है। इसमें कहा गया है कि देश के लगभग आधे सरकारी स्कूलों में न तो बिजली है और न ही छात्रों के लिए खेल-कूद का मैदान। समिति ने स्कूल शिक्षा विभाग के लिए बजट प्रावधानों की 27 फीसदी कटौती पर भी गहरी चिंता जताई है। स्कूली शिक्षा विभाग ने सरकार से 82,570 करोड़ रुपए मांगे थे। लेकिन उसे महज 59,845 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए। सर्वेक्षण के ताजा आंकड़ों के हवाले रिपोर्ट में कहा गया है कि महज 56 फीसदी स्कूलों में ही बिजली है। मध्यप्रदेश और मणिपुर की हालत तो सबसे बदतर है। इन दोनों राज्यों में महज 20 फीसदी सरकारी स्कूलों तक ही बिजली पहुंच सकी है। ओडिशा व जम्मू-कश्मीर के मामले में तो यह आंकड़ा 30 फीसदी से भी कम है।

रिपोर्ट के मुताबिक, देश में 57 फीसदी से भी कम स्कूलों में छात्रों के लिए खेल-कूद का मैदान है। रिपोर्ट के मुताबिक आज भी देश में एक लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो अकेले शिक्षक के दम पर चल रहें है। देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां इकलौते शिक्षक वाले ऐसे स्कूल न हों। यहां तक की राजधानी दिल्ली में भी ऐसे 13 स्कूल हैं। इन स्कूलों में इकलौते शिक्षक के सहारे पढ़ाई-लिखाई के स्तर का अनुमान लगाना कोई मुश्किल नहीं है। रिपोर्ट में सरकारी स्कूलों के आधारभूत ढांचे पर भी चिंता जताई गई है। इसमें सरकार की खिंचाई करते हुए कहा गया है कि हाल के वर्षों में हायर सेकंडरी स्कूलों की इमारत को बेहतर बनाने, नए कमरे, पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं बनाने की प्रगति बेहद धीमी है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2019-20 के लिए अनुमोदित 2,613 परियोजनाओं में से चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान महज **तीन परियोजनाएं** ही पूरी हो सकी हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इन परियोजनाओं में ऐसी देरी से सरकारी स्कूलों से छात्रों के मोहभंग की गति और तेज हो सकती है।

समिति ने कहा है कि 31 दिसंबर, 2019 तक किसी भी सरकारी हायर सेकंडरी स्कूल में एक भी नई कक्षा नहीं बनाई जा सकी है। यह हालत तब है जबकि वर्ष 2019-20 के लिए 1,021 नई कक्षाओं के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। इसी तरह 1,343 प्रयोगशालाओं के अनुमोदन के बावजूद अब तक महज तीन की ही स्थापना हो सकी है। पुस्तकालयों के मामले में **तो तस्वीर** और बदतर है। 135 पुस्तकालयों और कला-संस्कृति कक्षों के निर्माण का अनुमोदन होने के बावजूद अब तक एक का भी काम पूरा नहीं हुआ है। लगभग 40 फीसदी स्कूलों में चारदीवारी नहीं होने की वजह से छात्रों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लग रहे हैं। रिपोर्ट में सरकार को इन स्कूलों में चारदीवारी बनाने और तमाम स्कूलों में बिजली पहुंचाने की सलाह दी गई है। भारत में नरेंद्र मोदी सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग के और भी ज्यादा उत्कृष्ट संस्थान शुरू करने की घोषणा की है। आईआईएम जैसे प्रबंधन संस्थानों के केंद्र जम्मू-कश्मीर, बिहार, हिमाचल प्रदेश और असम में भी खुलने हैं। लेकिन बुनियादी ढांचे और फैकल्टी की कमी की चुनौतियां हैं। यहां सीट मिल भी जाए तो फीस काफी ऊंची है। इससे पहले एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकारी स्कूलों में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाले 55.8 फीसदी छात्र दूसरी कक्षा की पुस्तकें तक नहीं पढ़ सकते। इसी तरह आठवीं के 70 फीसदी छात्र ठीक से गुणा-भाग नहीं कर सकते। इससे इन स्कूलों में शिक्षा के स्तर का पता चलता है। वैसे, केंद्र की तमाम सरकारें शिक्षा के अधिकार पर जोर देती रही हैं। इस कानून में साफ कहा गया है कि सरकारी और निजी स्कूलों मे हर 30-35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में छात्र-शिक्षक अनुपात का औसत बीते एक दशक के दौरान काफी सुधरा है। लेकिन अहम सवाल यह है कि जब देश के लगभग 13 लाख में से एक लाख सरकारी स्कूल इकलौते शिक्षक के भरोसे चल रहे हों तो यह अनुपात बेमतलब ही है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

स्कूलों में आधारभूत ढांचे और शिक्षकों का भारी अभाव

शिक्षाविदों का कहना है कि तमाम सरकारें शिक्षा के कानून अधिनियम का हवाला देकर सरकारी स्कूलों के मुद्दे पर चुप्पी साध लेती हैं। अब तक किसी ने भी इन स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं की बेहतरी या शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की है। एक शिक्षाविद् प्रोफेसर रमापद कर्मकार कहते हैं, 'सरकारी स्कूलों में आधारभूत ढांचे और शिक्षकों का भारी अभाव है। महज मिड-डे मील के जरिए छात्रों में पढ़ाई-लिखाई के प्रति दिलचस्पी नहीं पैदा की जा सकती। लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है।' वह कहते हैं कि जब तक सरकारी स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं जुटाने और शिक्षकों के खाली पदों को भरने की दिशा में ठोस पहल नहीं होती, हालत दयनीय ही बनी रहेगी। यही वजह है कि निजी स्कूलों में छात्रों की भीड़ लगातार बढ़ रही है।

मौजूदा दलबदल कानून राजनीतिक और दलगत सुचिता की हिफाजत करने में नाकाम साबित हो रहा है। मौकापरस्ती और येन-केन-प्रकारेण सत्ता की मलाई खाने वाली राजनीति भारतीय समाज पर सिर चढ़कर बोल रही है। यह मतदाताओं के साथ छल है। ऐसी ठगी को रोकना संसद और सरकार की जिम्मेदारी है।

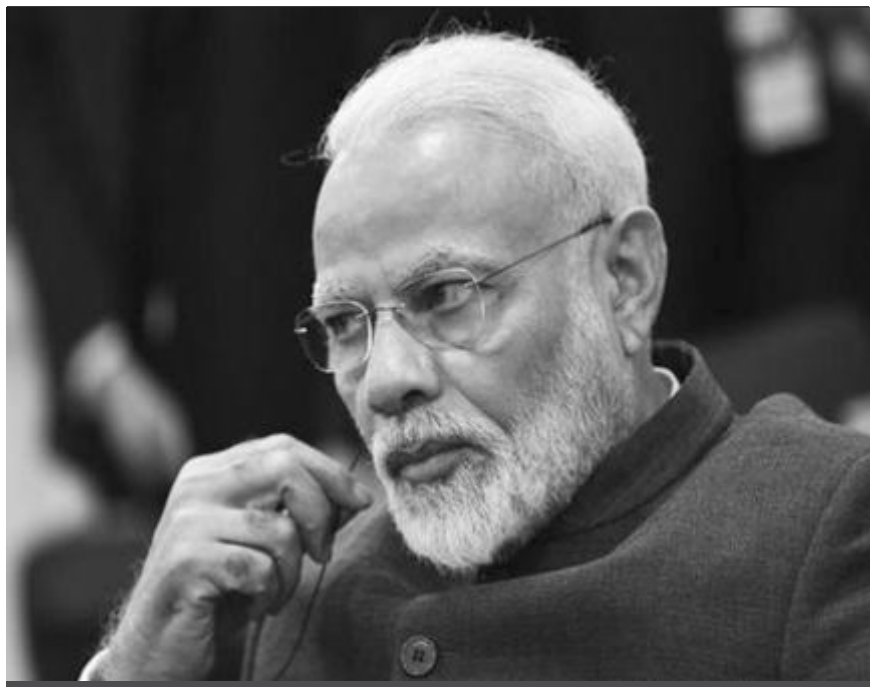

इंदिरा के नक्शेकदम

नरेंद्र मोदी क्या इंदिरा गांधी की तरह विपक्ष को नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं? इंदिरा गांधी के बाद मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूर्ण बहुमत से दोबारा सत्ता पाई है। रोजगार, आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर पिछड़ने के बाद भी नरेंद्र मोदी एक शक्तिशाली नेता के रूप में स्थापित हुए हैं। उन्होंने विपक्ष को इतना शक्तिहीन बना दिया है कि वह चुनौती देने के काबिल भी नहीं। बिखरे हुए विपक्ष को धराशायी करना मोदी के लिए और आसान हो गया है। संसद के मौजूदा बजट सत्र में नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के सारे सवालों का आत्मविश्वास से जवाब देकर एक बार फिर अपनी क्षमता साबित की है। वे विपक्ष की परवाह किए बिना उसी तरह सख्त फैसले ले रहे हैं जैसे कि इंदिरा गांधी लेती थीं।

नरेंद्र मोदी की राजनीतिक कुशलता के सामने राहुल गांधी टिक नहीं पाए। उनकी इस नाकामी से विपक्षी मोर्चाबंदी और कमजोर हो गई। प्रसिद्ध इतिहासकार और राजनीतिक विश्लेषक रामचंद्र गुहा नरेंद्र मोदी के कट्टर आलोचक हैं। लेकिन उन्हें भी कहने पर मजबूर होना पड़ा कि राहुल गांधी में मोदी को टक्कर देने की काबिलियत नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी को यूरोप में छुट्टियां मनाने वाला नेता बताया तो मोदी को बेहद मेहनती इंसान कहा। गुहा ने कहा था, मोदी के फैसलों को गलत ठहराया जा सकता है लेकिन उन्होंने शासन के लिए जो मेहनत और अनुशासन दिखाया है वह काबिले तारीफ है। अगर राहुल गांधी **जैसे नेता को मोदी का विकल्प बताया** जाएगा तो यह एक तरह से भाजपा को मजबूत करना होगा। राहुल गांधी वैसे सलाहकारों पर निर्भर हैं जिन्हें व्यवहारिक राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी पर व्यक्तिगत हमले की रणनीति बुरी तरह नाकाम रही। 'चौकीदार चोर है' और राफेल के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी औंधे मुंह गिर पड़े। संसद के मौजूदा बजट सत्र में भी राहुल गांधी अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। जब नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया तो कांग्रेस के राहुल गांधी और अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता निरुत्तर हो गए।

बढ़ती लोकप्रियता और सत्ता की ताकत शासक को निरंकुश बना देती है। इंदिरा गांधी भी 1971 में प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनी थीं। उन्होंने अपने तमाम विरोधियों के कस-बल ढीले कर दिए थे। नतीजा ये हुआ कि देश की जनता को आपातकाल में जुल्म सहने पड़े। नरेंद्र मोदी एक के बाद एक सख्त फैसले ले रहे हैं। उनको भी चुनौती देने वाला कोई नहीं। क्या सत्ता की परम शक्ति से एक दिन नरेंद्र मोदी भी डिक्टेटर बन जाएंगे? एक मजबूत विपक्ष ही किसी सरकार को निरंकुश होने से रोक सकता है। लेकिन मौजूदा राजनीति में विपक्ष की वही स्थिति है जो नेहरू काल में थी। आजादी के बाद कांग्रेस लोगों के दिलो-दिमाग में रची-बसी थी। इसकी वजह विपक्षी दलों को बहुत कम सीटें मिलती थीं। चार चुनावों तक हालत ये थी कि कोई नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाया। आजादी के 22 साल बाद भारत में किसी लीडर को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिला था। बिहार के सांसद रामसुभग सिंह 1969 में पहली बार नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठे थे। 2014 और 2019 में भी विपक्ष खस्ताहाल है। कांग्रेस इतनी भी सीटें नहीं जीत पाई कि वह नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हासिल कर सके। कमजोर विपक्ष लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान ने एक बार कहा था कि वो कमलनाथ सरकार को कभी भी गिरा सकते हैं। इसका जवाब में कमलनाथ ने चुनौती देते हुए कहा था कि भाजपा में हिम्मत है तो मेरी सरकार गिराकर दिखाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाते ही कमलनाथ सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में कांग्रेस की सरकार गिर

दलबदल से भाजपा भी महफूज नहीं

दलबदलू जमात से भाजपा भी महफूज नहीं है और यदि वो आज खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है, तो उसे नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र में कैसे 25 साल पुराने मित्र-दल शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा और चुनाव के बाद पाला बदल लिया। भाजपा के अलावा कांग्रेस और आरजेडी को भी नहीं भूलना चाहिए कि कैसे नीतीश कुमार ने जनादेश की अनदेखी कर उनको गच्चा दिया था। ये बात अलग है कि हाल के वर्षों में भाजपा को दलबदल रूपी ठगी का सबसे ज्यादा फायदा मिला है। अब मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ सरकार को गिराकर भाजपा ने कर्नाटक, गोवा, गोवा, मणिपुर और अरूणाचल की तरह अपनी सरकार बना ली, लेकिन ऐसा नहीं माना जा सकता है कि जैसे दिन आज कांग्रेस को देखने पड़ रहे हैं, वैसी ही नौबत कल को भाजपा को नहीं झेलनी पड़ेगी।

ही गई। इसके पूर्व एक तरफ भाजपा ने मध्यप्रदेश के अपने विधायकों को हरियाणा में ठहरा रखा था तो कांग्रेस ने अपने विधायक राजस्थान में। पिछले पखवाड़े से कमलनाथ सरकार के गिरने के कयासों वाली खबरों से पहले ही राष्ट्रीय अखबार भरे पड़े थे।

इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भाजपा नेताओं पर आरोप लगाते रहे कि वो कांग्रेस के विधायकों और नेताओं की खरीद-फरोख्त में **संलिप्त** हैं। लेकिन देश के राजनीतिक गलियारों में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। आया राम-गया राम से शुरू हुई होर्स ट्रेडिंग का ये राजनैतिक पैंतरा बड़े स्तर पर हो रहा है। ऐसी कई राजनीतिक घटनाएं हैं जब भाजपा ने राज्यों में सरकारें गिराईं और बड़े स्तर पर दूसरी पार्टी के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल किया।

साल 2016 में भाजपा अरुणाचल प्रदेश में कमल खिलाने में कामयाब रही, वो भी तब जब 60 सदस्यीय विधानसभा में उसके पास केवल 11 विधायक थे। दरअसल भाजपा ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व वाली पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (पीपीए) के 43 में से 33 विधायक तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। 44 विधायकों के बहुमत के साथ भाजपा ने प्रदेश में अपनी सरकार बना ली। लेकिन इसके पीछे भी कई राजनीतिक घटनाक्रम हुए थे। पीपीए अध्यक्ष काहफा बेंगिया ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए पेमा खांडू समेत अन्य पांच विधायकों को पार्टी की सदस्यता रद्द कर दी थी। जिसके बाद भाजपा ने खांडू और बाकी विधायकों को अपने पाले में ले लिया। नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार में सहयोगी पीपीए ने पहले टकाम पेरियो को मुख्यमंत्री के पद के लिए चुना लेकिन अगले ही दिन राजनीतिक समीकरण बदल गए। विधायकों ने टकाम की जगह खांडू को मुख्यमंत्री का चेहरा चुन लिया।

साल 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 16 सीटें जीतकर गोवा में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। भाजपा को इस चुनाव में केवल 14 सीटें हासिल हुईं लेकिन इसके बावजूद भाजपा निर्दलीय विधायकों की मदद से सरकार बनाने में कामयाब रही। इस बात की चौतरफा आलोचना हुई कि कायदे से बहुमत मिलने वाली पार्टी को सरकार बनाने का दावा पेश करने दिया जाना था। लेकिन वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने पार्टी के कदम को सही ठहराते हुए कहा था, 'सरकारिया कमीशन के मुताबिक कांग्रेस को पहले क्लेम करना चाहिए था। लेकिन गोवा में कांग्रेस रातभर सोई रही। 'गोवा की राजनीति में उथल-पुथल यहीं नहीं थमी। इसके ठीक दो साल बाद कांग्रेस के दो तिहाई विधायक (15 में से 10) भाजपा ने तोड़ लिए। इसके साथ ही भाजपा के विधायकों की संख्या 27 पहुंच गई। भाजपा का ये राजनीतिक पैंतरा सिर्फ गोवा तक ही सीमित नहीं रहा है।

2017 के मणिपुर विधानसभा चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हुआ था। मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 28 सीटें हासिल हुई थीं और भाजपा को 21 सीटें। बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 31 सीटों की जरूरत थी। मगर इसी बीच भाजपा ने 32 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। लेकिन इस पर भी भाजपा नेता रविशंकर ने टिप्पणी करते हुए कहा था, 'कांग्रेस ने आज तक मणिपुर में सरकार बनाने का दावा नहीं किया है।' मणिपुर में एन बीरेन सिंह को मणिपुर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। गौरतलब है कि वो एक साल पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। मणिपुर, गोवा और अरुणाचल के अलावा सबसे ज्यादा चर्चित अखबारों द्वारा छापी गई 'कर्नाटक में नाटक' थी जिसे देश के उदारवादी तबके ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाना भी कहा।

जुलाई 2019 में कर्नाटक की राजनीति में चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के साक्षी पूरे देश की जनता बनी। होर्स ट्रेडिंग ने नए आयाम भी छुए। गौरतलब है कि 2018 में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा को 104 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस को 80 सीटें मिली थीं और जेडीएस को 37 सीटें। दूसरे राज्यों में जनमत और बहुमत का उदाहरण देने वाली कांग्रेस पार्टी ने इस बार भाजपा से पहले ही सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। कांग्रेस ने ये जेडीएस के समर्थन से किया।

हालांकि गवर्नर ने भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण भेजा था। लेकिन भाजपा बहुमत नहीं साबित कर पाई। इस बीच कांग्रेस और जेडीएस सरकार बनाने में कामयाब रही। गठबंधन ने कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाया लेकिन कुछ दिन के बाद ही विधानसभा के 11 विधायकों (8 कांग्रेस और 3 जेडीएस) ने इस्तीफा दे दिया। कुमारस्वामी इस दौरान लगातार भाजपा पर विधायक खरीदने के आरोप लगाते रहे। आखिरकार कांग्रेस-जेडीएस की सरकार गिराकर भाजपा इस राज्य में भी सरकार बनाने में कामयाब रही।

साल 2019 में सिक्किम में पिछले 25 सालों से शासन चला रही सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) के 10 विधायक रातों-रात भाजपा में शामिल करा लिए गए। वो भी तब जब 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा यहां से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। लेकिन यहां भाजपा मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरी। हालांकि विधायकों के इस दल बदलू कदम की बड़े स्तर पर आलोचना हुई क्योंकि जनता ने भाजपा को केवल 1.62 प्रतिशत वोट देकर नकार दिया था।

● दिल्ली से रेणु आगाल

क्षेत्रिय क्षत्रप भी कमजोर

नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी और मायावती जैसी मजबूत क्षेत्रीय नेताओं के पांवों तले जमीन खिसका दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा अब दूसरी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। नरेंद्र मोदी से आर-पार की लड़ाई लड़ने वाली ममता के कमजोर होने से भाजपा के विस्तार की संभावना बढ़ गई है। पूर्वोत्तर में असम और त्रिपुरा में वह पहले से ही सत्ता में आ चुकी है। अगर पश्चिम बंगाल में भी भाजपा को सत्ता मिल गई तो मोदी की ताकत और बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश मिलकर भी मोदी को जवाब नहीं दे पाए। अब ये अलग-अलग लड़कर कौन-सा करिश्मा कर लेंगे? पूर्वी भारत में नवीन पटनायक ही कुछ हद तक भाजपा को रोक पाए हैं लेकिन वे मोदी के प्रति मध्यमार्ग अपनाते रहे हैं। कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि जिन राज्यों में उसकी सरकारें हैं वहां भी वे मोदी को रोक नहीं पा रहे हैं। लोकसभा चुनावों में सिर्फ दक्षिण के राज्य ही मोदी के लिए अवरोध हैं।

ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रकरण से कांग्रेस के अंदर मौजूद युवा मिलिंद देवड़ा, मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, राजीव शुक्ला और सुरजेवाला सहित कई दिग्गज राज्यसभा जाने की राह देख रहे थे लेकिन सपना टूटा। राहुल एंड टीम के ये सदस्य अब पांच साल इंतजार करने के मूड में नहीं दिख रहे। अब देखना यह है कि कांग्रेस अपने इन नेताओं को किस तरह संतुष्ट कर पाती है।

टूट रहा सब्र का बांध

देश की राजनीति के मौजूदा हालातों को देखते हुए यह लाख टके का सवाल है कि आखिर राहुल गांधी की टीम के सदस्य अब क्या करेंगे? राहुल के करीबी दूसरी पीढ़ी के ये नेता राज्यसभा न जाने का दंश मन में दबाए पूरे 5 साल क्या रह सकेंगे? वैसे तो इस टीम के कैप्टन और राहुल के सबसे निकट माने जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अन्य सभी को राह दिखा दी है। बीते दिनों सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का हाथ थाम लिया है। सिंधिया के इस फैसले से मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई है। अब निगाहें केवल राहुल एंड टीम सदस्यों के अगले कदम पर टिकी हैं कि ये सिंधिया की राह चलेंगे या फिर कुछ समय इंतजार करेंगे क्योंकि इन सभी के सब्र का बांध टूटता जा रहा है।

वैसे तो राजनीति में भी ये कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है लेकिन फिलहाल कांग्रेस में **मीठा फल** तो कम से कम मिलता नहीं दिख रहा। आम चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कुछ युवा नेताओं की नजरें राज्यसभा सीट पर थी, इनमें मुकुल वासनिक, शैलजा कुमारी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राजीव शुक्ला, मिलिंद देवड़ा, रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित लिस्ट में कई नाम हैं। इनमें से एक नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी था। उनकी भी कांग्रेस को लेकर पहली कुंठा यही थी कि मध्यप्रदेश से उनके राज्यसभा जाने की संभावना क्षणिक भर थी। जहां से पहले ही दिग्विजय सिंह का राज्यसभा जाना तय था। ऐसे में सिंधिया अगले पांच साल इंतजार नहीं करना चाहते थे, सो उन्होंने अपनी राह बदली और नाथ को छोड़ भाजपा के पास चले गए।

यही स्थिति कमोवेश राहुल की बाकी बची टीम की है। मुकुल वासनिक का नाम इस बार महाराष्ट्र से करीब-करीब तय माना जा रहा था लेकिन उनकी जगह राजीव सातव को राज्यसभा उम्मीदवार बना दिया गया। सातव पहली बार 2014 में मोदी लहर के बावजूद आम चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। उस समय लोगों की जुंबा पर उनका नाम आया और राहुल गांधी तो उन पर ऐसे मेहरबान हुए कि उन्हें गुजरात का प्रभारी तक बना दिया। राहुल गांधी से उनकी निकटता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी सातव राज्यसभा चले जाएंगे। छोटे से राजनीतिक करियर में सातव का राज्यसभा में जाना सिर्फ मुकुल वासनिक ही नहीं कई बड़े और दिग्गज नेताओं का दिल जलाने जैसा है। इनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राजीव शुक्ला, रजनी पाटिल और मिलिंद देवड़ा सबसे आगे हैं।

कांग्रेस को खुद से पूछना है

ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रकरण से कांग्रेस के अंदर मौजूद युवा और बुजुर्ग नेताओं के मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। यहां युवा का मतलब राहुल गांधी की टीम से है, जबकि बुजुर्ग यानी सोनिया गांधी के करीबी नेतागण। यह मनमुटाव तो तभी से कायम है, जब सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी की ताजपोशी करना चाहती थीं। सोनिया गांधी के इन करीबियों का मानना था कि राहुल गांधी के पार्टी प्रमुख बन जाने से उनकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी और वे किनारे कर दिए जाएंगे। इसीलिए उन्होंने बार-बार इसकी राह में बाधा डाली, फिर भी वे सोनिया गांधी को रोक न सके। मगर पिछले साल लोकसभा चुनाव में शिकस्त के बाद जब राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष की अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी, तब बुजुर्ग नेताओं की वही पुरानी टीम फिर से सक्रिय हो गई और उसने पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली। इससे युवा नेताओं को काफी तकलीफें हो रही थीं। साफ है, इन मुश्किलों से निजात पाने की शुरुआत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़कर की है।

ये सभी महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं में शामिल हैं और सभी राज्यसभा जाने वाले मजबूत दावेदारों में शामिल थे। मल्लिकार्जुन खड़गे तो इन सभी में सीनियर हैं और कहा जा रहा है कि जून महीने में राज्यसभा की कर्नाटक से खाली हो रही चार सीटों में एक से उनका उच्च सदन जाना पक्का है। लेकिन अन्य सभी के पास दो साल तक इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। दो साल बाद जब महाराष्ट्र से कुछ सीटें खाली होंगी तब इनका नंबर भी आएगा या इंतजार और लंबा होगा, ये कह पाना भी कंफर्म नहीं है। वहीं मिलिंद देवड़ा के बारे में तो काफी गर्मागर्म चर्चा है कि वे निश्चित तौर पर सिंधिया का रास्ता अपनाएंगे, तभी उनके मौजूदा राजनीतिक करियर को रफ्तार मिलेगी, वरना फिलहाल तो कांग्रेस में कुछ हासिल नहीं होना है। फिलहाल उनकी ओर से इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

इसी तरह रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम भी राज्यसभा जाने वाले संभावितों में शामिल था। उन्हें या तो राजस्थान या फिर अन्य किसी सीट से उच्च सदन भेजा जाना पक्का था। हालांकि वे न तो हरियाणा विधानसभा और न ही अन्य किसी सदन के सदस्य हैं लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस के तीखे हमलों की कमान वे और उनकी टीम बखूबी संभाल रही है, लेकिन राज्यसभा का मौका तो

उन्हें भी नहीं मिला। वजह रही कि हरियाणा में राज्यसभा की केवल एक ही सीट कांग्रेस के पास थी और यहां से पहले ही दो दावेदार मौजूद थे। जिसमें प्रमुख दावेदार मानी जा रही कुमारी शैलजा तक को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिद या यूं कहें पॉलिटिकल ब्लैकमिंग के चलते पीछे हटाना पड़ा।

अब बात करें उत्तरप्रदेश की, तो यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह भी कुछ न कुछ हासिल करने की फिराक में थे लेकिन हाथ उनके भी कुछ न लगा। हालांकि इस साल के अंत में उप्र से राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो रही हैं लेकिन यहां से करीब 8 सीटें भाजपा और एक सीट सपा के पास है। एक सीट पर लड़ाई है जिस पर कांग्रेस का दावा न के बराबर होगा।

बात करें बिहार की तो भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए एक्टर और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा यहां से राज्यसभा में घुसने की फिराक में थे। गठबंधन के चलते राजद ने एक सीट कांग्रेस को छोड़ने का वायदा लोकसभा चुनाव में कर भी दिया था लेकिन ऐन वक्त पर राजद ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर शत्रुघ्न को निराश कर दिया। बताया तो ये भी जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की मदद से भी उच्च सदन में जाने का जुगाड़ लगाया था लेकिन बात नहीं बनी।

फिर एक बार नजर डालें हरियाणा की राजनीति पर तो यहां से सोनिया गांधी की करीबी और पिछली बार की राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा का राज्यसभा टिकट पक्का था। हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष शैलजा की यहां मजबूत दावेदारी को देखते हुए ही सुरजेवाला ने अपना नाम आगे नहीं बढ़वाया। लेकिन पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने समर्थित विधायकों के दम पर अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा का टिकट फाइनल करा दिया और कुमारी शैलजा को सदन जाने से दूर कर दिया। पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियों के चलते राज्यसभा का सफर तय नहीं कर सकी।

क्या कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है?

सवाल है कि क्या कांग्रेस अब पूरी तरह खत्म हो जाएगी? नहीं, अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के अंदर और बाहर कई ऐसे नेता हैं, जो इसके अस्तित्व को बचाए रखने के हिमायती हैं। ममता बनर्जी, शरद पवार जैसे नेता तो यह मानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का विकल्प सिर्फ कांग्रेस बन सकती है। हां, यह जरूर है कि नेहरू-गांधी परिवार की छाया से इसकी मुक्ति का सपना सभी देख रहे होंगे। जाहिर है, यह पूरा प्रकरण कांग्रेस और इसके शीर्ष परिवार के लिए खतरे की घंटी है। पार्टी को इस पर जमकर मंथन करना होगा। इसका क्या नतीजा निकलेगा, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन संभव है कि पार्टी अब नेहरू-गांधी परिवार से बाहर निकलने की सोचे।

देखा जाए तो कांग्रेस के असंतुष्ट दिग्गजों की लिस्ट काफी लंबी है लेकिन सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद भी अभी तक इंतजार कर रहे हैं। उनके इंतजार की वजह मध्यप्रदेश भी है। इनमें से अधिकांश नेताओं ने लंबे समय तक पार्टी की भक्ति की है और कांग्रेसी विचारधारा में रचे बसे हैं, यही वजह है कि वे आगे का रास्ता तय करने में संकोच कर रहे हैं।

वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में जाने का फैसला अंगारों पर चलने जैसा है, ऐसे में राहुल एंड कंपनी के ये सदस्य केवल सिंधिया का भाजपा में हश्र देख रहे हैं। अगर उनके साथ सबकुछ अच्छा हुआ तो ये एक-एक कर 'महाराज' की राह पकड़ेंगे और अगर नहीं तो फिर आगामी कुछ साल इंतजार करने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है।

कांग्रेस में बुजुर्ग नेतागण किस कदर हावी हो चुके हैं, इसके कई उदाहरण हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कड़ी मेहनत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार थे, लेकिन तब जिम्मेदारी न सिर्फ कमलनाथ को सौंपी गई, बल्कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी सिंधिया को वंचित रखा गया। इसी तरह, पड़ोसी राज्य राजस्थान में सचिन पायलट को उप-मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा और अब खबर यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हें पर्याप्त तवज्जो नहीं दे रहे। आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा जैसे तमाम युवा नेताओं की भी कुछ यही कहानी है। युवा बनाम बुजुर्ग की यह तनातनी इतनी अधिक है कि मिलिंद देवड़ा खुलेआम संजय निरुपम से उलझ चुके हैं, तो पी चिदंबरम और शर्मिष्ठा मुखर्जी ट्विटर पर एक-दूसरे के सामने आ चुके हैं।

ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा का दामन थामना कांग्रेस के लिए **खतरे की घंटी** है। चूंकि पार्टी के तमाम दूसरे युवा नेता भी उनके संपर्क में हैं, इसलिए संभव है कि आने वाले दिनों में इस तरह की कुछ और टूट से पार्टी का सामना हो। **सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा के भाजपा नेताओं के संपर्क में रहने की खबरें** भी हैं। जाहिर है, गत दिनों घटनाक्रम के दो संदेश स्पष्ट हैं। पहला यह कि कांग्रेस टूट रही है और दूसरा, नेहरू-गांधी परिवार का यह निजी नुकसान है। यह सब जानते हैं कि माधवराव सिंधिया जिस तरह गांधी परिवार के करीबी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी वही नजदीकी रही है। यही वजह है कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को लोकसभा में पार्टी के उप-नेता पद से इस्तीफा दिलवाकर पंजाब भेजा गया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह पद देने की मांग उठी। मगर सोनिया गांधी ने इस आवाज को अनसुना कर दिया, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि इससे राहुल गांधी के कद पर असर पड़ सकता है। फिर भी, जिस तरह राहुल और ज्योतिरादित्य एक-दूसरे के करीब थे, उससे यही लगा कि ज्योतिरादित्य उन दिनों को भूल चुके हैं और पार्टी में अपने लिए नई जगह देख रहे हैं।

● **इन्द्र कुमार**

नक्सली नासूर

छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षाबलों पर नक्सली हमले से एक बार फिर इस समस्या से पार पाने की चुनौती रेखांकित हुई है। वहां नक्सली समूह लंबे समय से सक्रिय हैं और उन पर काबू पाने में सरकार के प्रयास प्रश्नांकित होते रहे हैं। अक्सर नक्सली वहां घात लगाकर या फिर सीधे मुठभेड़ में सुरक्षाबलों को चुनौती देते हैं। इससे पार पाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र के संयुक्त प्रयास चलते रहे हैं, पर इस दिशा में अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पाई है। अक्सर देखा जाता है कि खुफिया तंत्र और सुरक्षाबलों की तैयारी विफल साबित होती है। सुकमा में ताजा नक्सली हमला इसका एक और उदाहरण है। बीते दिनों जब सुरक्षाबलों को जानकारी मिली कि सुकमा जिले के एलमागुड़ा में नक्सली गतिविधियां सक्रिय हैं, तो विभिन्न बटालियनों के करीब 600 जवान वहां रवाना कर दिए गए। मगर करीब 250 की संख्या में नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया। इसमें 17 जवान मारे गए और करीब 15 गंभीर रूप से घायल हो गए। मारे गए जवानों के शवों को घने जंगल से तलाश कर निकाला जा सका। इस घटना ने एक बार फिर इस चिंता को गाढ़ा किया है कि नक्सली समस्या पर काबू पाने के लिए सुरक्षाबलों की तैयारियों को कैसे अधिक चाक-चौबंद किया जाए।

छत्तीसगढ़ में नक्सली समूह जंगलों पर आदिवासियों के अधिकार के मुद्दे पर लगातार संघर्ष करते रहे हैं। इस संबंध में कई बार सरकार की तरफ से उनसे बातचीत के प्रयास भी हुए। केंद्र ने वनभूमि पर आदिवासियों के मालिकाना हक को लेकर पुराने कानून में संशोधन किया और कंपनियों द्वारा उनकी अधिग्रहीत भूमि वापस लौटाने का अभियान चला। मगर अब भी नक्सली गतिविधियां नहीं रुक रही हैं, तो इस मामले में नए सिरे से रणनीति बनाने की दरकार स्वाभाविक है। पहले आरोप लगता रहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सली समूहों से संवाद स्थापित करने में नाकाम रही है। पर अब वहां सरकार बदली है और उसका दावा है कि उसने आदिवासी समूहों के हितों के लिए काफी व्यावहारिक कदम उठाए हैं, इससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आया है। मगर यह नक्सली हमला सरकार के ऐसे तमाम दावों और विज्ञापनों आदि के जरिए प्रचारों पर सवाल खड़े करता है। अगर सचमुच सरकार के प्रयासों से आदिवासी समूह और नक्सली संतुष्ट होते तो शायद इस तरह के संघर्ष की नौबत न आती।

छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियों पर काबू न पाए जा सकने के पीछे कुछ वजहें स्पष्ट हैं। छिपी बात नहीं है कि वहां नक्सली समूह स्थानीय लोगों के समर्थन के बिना लंबे समय तक नहीं टिक सकते। स्थानीय लोगों का प्रशासन पर विश्वास बहुत जरूरी है। इसी से सूचना तंत्र को पुख्ता बनाया जा सकता है। अगर स्थानीय स्तर पर खुफिया एजेंसियों और सुरक्षाबलों का सूचना तंत्र कारगर होता, तो नक्सलियों की साजिशों का समय पर पर्दाफाश होता और उन्हें मिलने वाली मदद, साजो-सामान को रोकने में कामयाबी मिल सकती थी। जबकि नक्सली इस मामले में अभी आगे देखे जा रहे हैं। जब तक सरकारें इन कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करने का प्रयास नहीं करेंगी, इस समस्या पर काबू पाना कठिन ही बना रहेगा। कब तक सुकमा नक्सलियों का अखाड़ा बनता रहेगा? कब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? ये कुछ सवाल हैं जो वर्षों से देशवासियों को असहनीय वेदना दे रहे हैं। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि नक्सलियों के क्रूर इरादों को कुचलने का वक्त आ गया है। सरकार के एक आदेश से भारतीय सेना कुछ ही दिनों में छत्तीसगढ़, उड़ीसा सहित समस्त राज्यों से नक्सलवाद को सदा के लिए निस्तनाबूत कर सकती है। जो भारतीय सेना कुछ घंटों में ही दुश्मन मुल्क में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकती है, वह नक्सलियों का क्या हश्र कर सकती है, इसका अंदेशा शायद ही हमें हो। अत: नक्सलियों से निपटने के लिए सरकार को साहसिक फैसले लेने की जरूरत है।

छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा से जुड़ी घटनाओं के आंकड़े लोकसभा के बजट सत्र में पेश किए गए हैं। बस्तर सांसद दीपक बैज के एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नक्सल समस्या के लिए जारी राशि का ब्यौरा दिया है। इसमें पिछले तीन सालों में नक्सली हिंसा से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को 706 करोड़ 78 लाख रुपए देने का दावा किया है। यह राशि अलग-अलग योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 से सत्र 2019-20 के बीच जारी की गई है। लोकसभा में पेश एक अन्य सवाल के जवाब में नक्सली हिंसा की वारदातों और उसमें हुई जनहानि के आंकड़े भी पेश किए गए हैं। इसके तहत छत्तीसगढ़ में तीन सालों में 1 हजार 28 नक्सली वारदातें हुईं। इनमें 284 नक्सली मारे जाने का दावा किया गया है। जबकि इन सालों में 137 जवानों की शहादत हुई है। इतना ही नहीं 223 आम लोगों को भी इन नक्सली वारदातों में अपनी जान गंवानी पड़ी है। बस्तर सांसद दीपक बैज के सवाल के जवाब में बताया गया है कि सत्र 2014-15 से सत्र 2016-17 के बीच नक्सल समस्यायों से निपटने के लिए राज्य सरकार को 224.63 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

इस साल कम हुई घटनाएं

लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में नक्सली हिंसा की घटनाएं पिछले तीन सालों की तुलना में कम हुई हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 में कुल 373 नक्सली वारदातें हुईं। इनमें 70 आम लोगों की जान गई। सुरक्षा बलों के 60 जवान शहीद हुए। जबकि 80 नक्सलियों को मारे व 796 को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। साल 2018 में कुल 392 नक्सली वारदातें हुईं। इनमें 98 आम लोगों की जानें गईं। सुरक्षा बलों के 55 जवान शहीद हुए। जबकि 125 नक्सलियों को मारे व 931 को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। जबकि बीते साल 2019 में कुल 263 नक्सली वारदातें हुईं। इनमें 55 आम लोगों की जानें गईं। सुरक्षा बलों के 22 जवान शहीद हुए। जबकि 79 नक्सलियों को मारे व 367 को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है।

सबकी थाली में थोड़ा-थोड़ा

महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने 6 मार्च को जब महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार का पहला बजट पेश किया तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वाभाविक तौर पर बेहद खुश नजर आ रहे थे। कृषि, शहरी विकास, परिवहन और पर्यटन सरीखे चार क्षेत्रों को बजट में खासी तवज्जो दी गई है। ठाकरे इन पर लंबे समय से अतिरिक्त ध्यान देते आ रहे हैं। राज्य के बजट में 1.15 लाख करोड़ रुपए के कुल खर्च का अनुमान लगाया गया है। इसमें से करीब 40 फीसदी यानी 42,588 करोड़ रुपए सामाजिक और सामुदायिक सेवा पर खर्च किए जाएंगे। 16,333 करोड़ रुपए कृषि और उससे जुड़ी सेवाओं के लिए आवंटित किए गए हैं, जबकि परिवहन विभाग (जिसकी देखरेख शिवसेना के अनिल परब करते हैं) के हिस्से में 16,846 करोड़ रुपए आए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जयंत पाटिल के नेतृत्व वाले महत्वपूर्ण जल संसाधन विभाग की तुलना में यह 800 करोड़ रुपए ज्यादा है। सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे, पिंपरी-चिंचवाड़ और नागपुर जैसे शहरी क्षेत्रों में दो साल के लिए स्टाम्प ड्यूटी में एक फीसदी रियायत का ऐलान किया है। उम्मीद की जाती है कि इससे रीयल एस्टेट क्षेत्र में कुछ हद तक बिक्री बढ़ेगी, जो शिवसेना के एकनाथ शिंदे के अधीन है।

ठाकरे का ध्यान सामाजिक कल्याण पर है, जो दो योजनाओं से स्पष्ट है। एक तो किसानों के कर्ज की माफी (जिसके लिए 22,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, 15,000 करोड़ रु. 2019-20 के लिए और 7,000 करोड़ रु. 2020-21 के लिए) और दूसरी, 10 रुपए में शिव भोजन योजना, जिसके लिए 150 करोड़ रु. दिए गए हैं। यह 26 जनवरी को शुरू होने के तुरंत बाद ही लोकप्रिय हो गई। सरकार ने राज्य के 148 केंद्रों पर रोजाना परोसी जाने वाली थालियों की संख्या 18,000 से बढ़ाकर दोगुनी यानी 36,000 कर दी है। योजना इसे 1,00,000 थाली रोजाना तक ले जाने की है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल का कहना है कि लोगों ने इसे हाथोहाथ लिया है। बिजली मंत्री नितिन राउत की घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना का विपक्ष ने मुफ्तखोरी की संस्कृति कहकर विरोध किया, लेकिन मंत्री आप सरकार से प्रेरित इस योजना को जारी रखने के लिए कमर कसे हुए हैं। इस संबंध में एक विस्तृत योजना बनाने के लिए तीन सचिवों की एक समिति गठित की गई है। शिवसेना की मुख्य मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए अब 10वीं कक्षा तक सभी बोर्डों में मराठी की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है। स्कूली शिक्षा मंत्री, कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ का कहना है, 'भविष्य में पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन हमारी प्राथमिकता होगी।' पर्यावरण का मुद्दा ठाकरे के लिए हमेशा बड़ी प्राथमिकता रहा है। मुख्यमंत्री के बेटे तथा पर्यावरण और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे के पास इस मामले में राज्य के लिए बड़ी योजनाएं हैं। इसी में एक है समर्पित हरित कोष, जो वन्यजीव अभयारण्यों से अलग दूसरे हरित क्षेत्रों में स्वतंत्र वन भ्रमण को बढ़ावा देता है। आदित्य कहते हैं, 'इसके अमल के लिए मैं वन महकमे के अफसरों से बात कर रहा हूं।' अपने निर्वाचन क्षेत्र वर्ली में 1,000 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय एक्वैरियम बनाने की भी उनकी योजना है। इसके अलावा मुंबई को पर्यटन से संबंधित बुनियादी ढांचों के विकास के लिए सालाना 100 करोड़ रुपए मिलेंगे।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दोहराया कि उनकी सरकार लोगों का जीवन आसान बनाने को प्रतिबद्ध है। हालांकि, विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस मानते हैं कि ठाकरे स्थगित सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार की कई परियोजनाएं रोक दी गई हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के पहले बजट में संसाधन जुटाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट को प्रति लीटर एक रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। वित्तमंत्री ने बताया कि इससे राज्य सरकार के खजाने में हर साल 1800 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्राप्ति होगी। बजट प्रस्तावों में कर रियायतों की घोषणा भी की गई है। इसमें मुंबई महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) और पुणे, पिंपरी-चिंचवड और नागपुर के नगर निगमों के तहत आने वाले क्षेत्रों में दस्तावेजों के पंजीकरण पर लगने वाले शुल्क में अगले दो वर्षों तक एक प्रतिशत की रियायत शामिल है। सरकार ने राज्य में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान बजट में किया है। वहीं राज्य में गरीबों के लिए सस्ती भोजन योजना को चलाने के लिए 150 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। पवार ने कहा कि उनके बजट प्रस्ताव आर्थिक सुस्ती की चुनौतियों का मुकाबला करने और रोजगार सृजन पर केंद्रित हैं। बजट में कहा गया है कि जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकार पर कुल 4,33,00,091 करोड़ रुपए का बकाया ऋण और देनदारी है। पिछले पांच साल के दौरान राज्य ने 2,82,448 करोड़ रुपए का कर्ज लिया।

● **बिन्दु माथुर**

एमवीए सरकार के बजट से क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होगाः भाजपा

वहीं दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए महाविकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार के बजट से विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होगा और इस बजट में राज्य के किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कुछ भी नया नहीं है। मुख्य विपक्षी दल ने कहा कि शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार के पहले बजट में किसानों को कर्ज मुक्त बनाने के प्रावधान का कोई जिक्र नहीं है, जैसा पिछले साल नवंबर में एमवीए ने वादा किया था। भाजपा नेता व विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने यहां विधान भवन परिसर के बाहर संवाददाताओं से कहा, 'इसमें किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कुछ भी नया नहीं है, विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र के लिए भी इसमें कुछ नहीं है।' उन्होंने कहा, 'बजट में कोंकण क्षेत्र के लिए प्रावधानों का उल्लेख जरूर किया गया है, लेकिन उसमें कुछ भी ठोस नहीं है।' एक अन्य भाजपा नेता और पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि बजट में न तो कोई 'अर्थ है और न ही कोई संकल्प' है।

क्या पायलट करेंगे विद्रोह?

जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ा है, सियासी गलियारों में ये चर्चा छिड़ गई है कि युवा नेता सचिन पायलट भी कांग्रेस से दूरी बना सकते हैं। सिंधिया के करीबी माने जाने वाले राजस्थान के उप-मुख्यमंत्री पायलट के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी जल्द ग्वालियर के 'महाराजा' की तरह बागी तेवर अपना सकते हैं। बड़ा सवाल ये है क्या पायलट भी सिंधिया की तरह पार्टी से विद्रोह कर भाजपा में शामिल हो जाएंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि पायलट और सिंधिया में कई सारी समानताएं हैं। यूपीए के समय में ये दोनों राहुल गांधी की 'यंग ब्रिगेड' का सबसे जरूरी हिस्सा थे। दोनों ना सिर्फ तेज तर्रार और बेहतरीन वक्ता हैं, बल्कि कांग्रेस के दो लोकप्रिय और दिग्गज नेता-राजेश पायलट और माधवराव सिंधिया के बेटे हैं। इनकी सियासी वंशावली की वजह से दोनों को मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में मंत्री बनाया गया था और 2018 में दोनों ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए जबरदस्त कैंपेनिंग की थी। माना जा रहा था कि दोनों राज्यों में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो उसकी कमान सिंधिया और पायलट के हाथों में ही सौंपी जाएगी, लेकिन पार्टी हाईकमान ने दो पुराने कांग्रेसी नेताओं को दोनों सूबे का मुख्यमंत्री बना दिया।

अगर मध्य प्रदेश में सिंधिया कमलनाथ-दिग्विजय की जोड़ी से नाराज हैं, तो पायलट और अशोक गहलोत के बीच की दूरियां भी राजस्थान में किसी से छिपी नहीं है। असल में, मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री के बीच की ये खींचतान पिछले 15 महीने से राजस्थान की कांग्रेस सरकार की अनचाही और अनवरत हिस्सा बन गई है। कई बार राज्य में कानून और व्यवस्था (गहलोत राज्य के गृहमंत्री भी हैं) से नाराज पायलट ने सरेआम सीएम पर वार किए हैं। हाल की बात करें तो करीब दो महीने पहले ही कोटा के सरकारी अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत पर उन्होंने गहलोत को आड़े हाथों लिया। दोनों नेताओं में समानताओं के बावजूद कई ऐसी असमानताएं भी हैं जिसकी वजह से पायलट सिंधिया के रास्ते जाएं इसकी संभावना बहुत कम है। पहली बात ये कि पायलट मध्यप्रदेश में सिंधिया की तरह अलग-थलग और सत्ताहीन नहीं हैं। सचिन पायलट के पास उप-मुख्यमंत्री और राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष जैसे दो बड़े पद हैं, जिसके जरिए वो और उनके समर्थक सरकार और पार्टी दोनों में गहरी पैठ रखते हैं।

राज्य के बड़े अधिकारी इस बात की पुष्टि करते हैं कि पायलट के विभाग की फाइल मुख्यमंत्री के कार्यालय में नहीं जाती और गहलोत ने कभी भी पायलट के विभागों की समीक्षा नहीं की है, जबकि वो दूसरे सभी विभागों की बराबर समीक्षा करते रहते हैं। हो सकता है पायलट जितना चाहते हैं उतनी ताकत उनके पास ना हो, लेकिन सत्ता में पायलट की मौजूदगी ने राजस्थान में दो पावर सेंटर जरूर बना दिया है जबकि गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा का सियासी गणित भी पायलट को सिंधिया के नक्शे कदम पर जाने से रोकता है।

200 सदस्यों की विधानसभा में, कांग्रेस के पास 107 विधायक हैं, इसके अलावा गहलोत सरकार को 12 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल है। जबकि भाजपा के पास सिर्फ 73 विधायक हैं। गहलोत सरकार को गिराने के लिए सचिन पायलट को कांग्रेस विधायकों के एक बड़े हिस्से को तोड़ना पड़ेगा। पार्टी के अंदरूनी जानकारों का मानना है कि अपने विधायकों पर गहलोत की पकड़ बहुत मजबूत है, और पायलट अगर कोशिश भी करें तो पार्टी में बड़ी तादाद में विधायकों के बागी होने की कोई संभावना नहीं है।

हैरानी की बात नहीं है कि पायलट लगातार छह सालों से राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और अपने पिता की तरह वो भी ऐसा नेता बनना चाहते हैं जिसकी ताकत जनता से होती है, पार्टी हाईकमान से नहीं। इसके अलावा पायलट का जनाधार (गुर्जर जनजाति) भी ऐसे लोगों से है जो भाजपा के बदले कांग्रेस के साथ ज्यादा सहज हैं। जहां सिंधिया शाही फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, पायलट की सादगी और उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि उन्हें आम जनता से जोड़ती है, अपने पिता के लोकप्रिय अंदाज में वो भी 'राम-राम सा' करते हुए लोगों से मिलते हैं। जहां सिंधिया दिल्ली-सर्किट में आराम फरमाते रहे, पायलट 2014 के बाद बने हालात में आम लोगों का नेता बनकर उभरे और अपनी मेहनत से हासिल की गई हैसियत को वो किसी मामूली फायदे के लिए बर्बाद नहीं करेंगे।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

सचिन पायलट भाजपा के जाल में नहीं फंसेंगे

जाहिर है किसी भी दूसरे माहिर राजनेता की तरह, पायलट भी आखिरी फैसला लेने से पहले हर विकल्प पर पूरी तरह सोच विचार करेंगे। पायलट जानते हैं कि गहलोत के बाद वो कांग्रेस की दूसरी पसंद हैं और राजस्थान में वो कांग्रेस के भविष्य के तौर पर देखे जाते हैं। पायलट सिंधिया से करीब 8 साल छोटे हैं, इसलिए अभी उनके पास मुख्यमंत्री का पद हासिल करने के लिए काफी वक्त भी है। कांग्रेस का हाथ छोड़ने के बजाय, पायलट इस नए मौके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और पार्टी हाईकमान पर देर-सवेर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का दबाव बना सकते हैं। साफ है पायलट भारतीय राजनीति में अपने लिए आम जनता के नेता की खास पहचान बनाना चाहते हैं, ऐसे में वो नहीं चाहेंगे कि उनकी इमेज एक ऐसे राजनेता की बने जिसके लिए विचारधारा कोई खास मायने नहीं रखता हो और वो मौकापरस्ती की राजनीति करता हो। जहां भाजपा के लिए पायलट बड़ी मछली साबित हो सकते हैं, वो इतनी जल्दी किसी जाल में नहीं फंसने वाले हैं।

उप्र में भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार के तीन साल तो पूरे हो गए लेकिन जिस उत्तर प्रदेश की जनता को बड़े-बड़े वादे और सपने दिखाकर भाजपा सत्ता में आई थी वह अभी भी अधूरे हैं।

कागजी शेर

उप्र की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ प्रदेश में भाजपा को कमान सौंपी थी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तीन साल के कार्यकाल को देखें तो वे कागजी शेर साबित हुए हैं। किसानों, शिक्षकों व महिलाओं को लेकर 2017 में जो वादे किए थे वो अधूरे ही दिख रहे हैं। सरकार ने इनके लिए अधिकतर इनीशिएटिव की प्रतीकात्मक शुरुआत करके पीछा छुड़ा लिया। चाहे वह उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार, प्रदेश में भयमुक्त माहौल देने की बात हो या फिर महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की, प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त करने की बात हो या किसानों के बकाए भुगतान और कर्जमाफी सहित आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने की, ये सभी बातें और वादे जमीन पर उतरते दिखाई नहीं दिए हैं। भाजपा ने 2017 के चुनावी घोषणा पत्र में औद्योगिक पार्कों, आईटी पार्कों, दवाओं के लिए फार्मा पार्क और निर्यात के लिए ड्राई पोर्ट की बात की थी लेकिन यह फ्लैगशिप कार्यक्रम भी किताबी साबित हुए हैं। तीन साल बाद उत्तर प्रदेश का आम नागरिक सरकार की कार्यशैली को भलीभांति समझ चुका है, वैसे भी गांव में एक कहावत है पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं फिर अब तो सरकार का आधे से ज्यादा कार्यकाल हो चुका है अब ऐसे में देखना है कि भाजपा सरकार क्या करती है?

बेसिक शिक्षा में 1.5 लाख, उच्च शिक्षा में 50 हजार से ज्यादा शिक्षकों की कमी है, भाजपा ने सरकार बनने के 90 दिन के अंदर विज्ञप्ति जारी कर शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी शिक्षकों की कमी जस की तस बनी हुई है। कहा गया था कक्षा 12वीं तक गरीब परिवारों से आए छात्र-छात्राओं को सभी पुस्तकें, स्कूल यूनिफार्म और जूते व स्कूल बैग मुफ्त दिए जाएंगे लेकिन हकीकत इससे इतर है। तीन साल बीत जाने के बाद भी सरकार को इस पर ध्यान देने का समय तक नहीं मिला है। चुनाव से पहले शिक्षा मित्रों से जो वादा किया था वो भी नहीं निभाया। प्रदेश के सभी युवाओं को लैपटॉप देने का वादा सरकार के तीन साल पूरे होने के बाद भी परवान नहीं चढ़ पाया। नौकरियों के लिए जो परीक्षाएं हुईं उनमें अधिकांश के पेपर लीक हुए और यहां तक कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष को इस्तीफा तक देना पड़ा।

'न गुंडाराज-न भ्रष्टाचार' का नारा भाजपा की हर चुनावी सभा मे गूंजा था लेकिन सत्ता में आने के बाद से लगातार अपराध बढ़ता चला गया। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में 43 प्रतिशत हत्या, डकैती और सुपारी किलिंग और महिला अपराधों के मामलों में वृद्धि हुई है। हाल ही में रायबरेली में एक परिवार की नृशंस हत्या, मथुरा में डकैती, गोरखपुर में परिवार को जिंदा जलाने और इलाहाबाद में परिवार की सामूहिक हत्या सहित तमाम घटनाओं से उत्तर प्रदेश में फैलते जंगलराज का नजारा पूरे देश ने देखा है। भ्रष्टाचार के मामले में सरकार ने नए आयाम बनाए और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी, सरकार बनने के 15 दिन में मंत्रियों और अधिकारियों से उनकी संपत्ति का विवरण मांगा गया था लेकिन शान से तीन साल बिताने वाले योगी सरकार के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री द्वारा 3-3 रिमाइंडर भेजे जाने के बाद भी अधिकांश मंत्रियों ने अपना ब्यौरा नहीं दिया।

घोटाले से जुड़े मुद्दों पर कई बार सत्ताधारी पार्टी के विधायक-सांसद सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे और सरकार के मंत्रियों ने भ्रष्टाचार की शिकायतों से भरे पत्र भी लिखे लेकिन सरकार जांच कराने और जिम्मेदार भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर कार्यवाही करने के बजाय सिर्फ पर्दा डालती रही, यहां तक कि मिर्जापुर में मिड-डे मील में गड़बड़ी की खबर दिखाने वाले पत्रकार पर मुकदमा तक लिख दिया गया।

कृषि विकास और किसानों को भाजपा ने 2017 में अपने संकल्प पत्र में तो प्राथमिकता दी लेकिन सरकार बनने के बाद से अब तक वह प्राथमिकता धूल खा रही है। सभी लघु एवं सीमांत किसानों का फसली ऋण माफ करने की बात करने वाली भाजपा ने 2 रुपए, 3 रुपए और 80 रुपए माफ कर मजाक उड़ाया और चुनाव के समय स्वयं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसानों का कर्जमाफ करने की बात कही गई लेकिन बाद में इसे राज्य के ऊपर डाल दिया गया। सरकार बनने के 14 दिन के अंदर गन्ना बकाए का ब्याज सहित भुगतान का वादा किया था लेकिन आज भी किसानों का करोड़ों से ज्यादा बकाया ही है। तीन साल बीत जाने के बाद भी आवारा पशुओं की भी समस्या कम नहीं हुई है, प्रदेश में किसानों द्वारा प्रदर्शन किए जाने पर उन पर मुकदमे भी किए गए, प्रतीकात्मक तौर पर गौशालाओं का निर्माण हुआ लेकिन कोई ठोस काम होता दिखाई नहीं दिखाई दिया।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं बढ़ी

महिलाओं के लिए भाजपा का नारा सशक्त नारी समान अधिकार भी पूरी तरह कागजी साबित हुआ महिला अपराधों पर कई मौकों पर सरकार कोई कार्यवाही करने के बजाय बलात्कारियों के साथ खड़ी दिखाई दी, यहां तक महिला अपराधों के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बीजेपी सरकार को फटकार लगाई ।उन्नाव रेप केस और शाहजहांपुर की घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकजोर दिया और उत्तम प्रदेश बनाने का दावा करने वाली बीजेपी सरकार नाकाम साबित हुई अपराध रोकने और अपराधियों में डर महसूस कराने में असफल रही, तीन साल पूरे होने के बावजूद तीन नई महिला बटालियन - अवंती बाई बटालियन, झलकारी बाई बटालियन और ऊदा देवी बटालियन वादा संकल्प पत्र में ही गुम हो गया।

जातिगत राजनीति का सच

बिहार की सियासत में जाति एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन पूरी तरह नहीं। जातीय जनगणना के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने वाले बिहार की राजनीति में जातियों के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। बिहार में सवा दो सौ से ज्यादा जातियां हैं, लेकिन इनमें मुख्य तौर पर 10-12 ही सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेती हैं। टिकट के लिए मारामारी भी इन्हीं के बीच होती है। अन्य जातियों का स्थान दर्शक दीर्घा में होता है। एक सच यह भी है कि आजादी से अब तक राज्य की 20 जातियों के प्रतिनिधि ही संसद तक पहुंच सके हैं। बाकी को सांसद बनने का मौका तक नहीं मिला है। हां, विधानसभा में यह फलक थोड़ा ही बड़ा है।

जातीय जनगणना के सहारे अपने वोट बैंक में इजाफे की उम्मीद लगाने वाले दलों को यह आंकड़ा सबक देगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी बड़े दलों ने सिर्फ 21 जातियों को ही टिकट के लायक समझा। यह बिहार में जातियों की कुल संख्या का महज 10 फीसदी है। यानि 90 फीसदी को टिकट का हकदार नहीं माना गया। करीब 200 जातियां हैं, जिनका प्रतिनिधित्व अभी तक किसी सदन में नहीं हो सका है। राजनीतिक विश्लेषक अजय कुमार कहते हैं कि बिहार को जातीय चश्मे से देखने वाले अपने फलक को बड़ा कर लें। अगर ऐसा होता तो जॉर्ज फर्नांडीज, मीनू मसानी, जेबी कृपलानी और मधु लिमये जैसे बाहरी नेताओं को बिहार से संसद जाने का मौका नहीं मिल पाता। बिहार के वोटरों ने उनकी जाति नहीं, संभावनाएं देखकर अपना प्रतिनिधि चुना। श्रीकांत की पुस्तक बिहार में चुनाव, जाति और बूथ लूट के आंकड़े बताते हैं कि 1952 से अब तक यादव, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमिहार, कुर्मी, कोइरी, बनिया, कहार, नाई, धानुक, नोनिया, मल्लाह, विश्वकर्मा, पासवान, मांझी, पासी, रविदास, मुस्लिम और ईसाई समुदाय से ही सांसद चुने गए हैं। बाकी को इंतजार है।

बिहार की राजनीति हमेशा से अलग रही है। यहां की राजनीति में जाति का गणित काफी अहम है और एक कड़वी सच्चाई है कि चुनाव के अंतिम दिन विकास पर जाति का समीकरण भारी पड़ता है। इसलिए राजनीतिक दल इसी जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर उम्मीदवार उतारते हैं। बिहार की राजनीति का विश्लेषण करने वालों के मुताबिक हर दशक में अलग-अलग जातियां चुनावी दिशा को तय करती हैं। 1977 तक बिहार की सियासत में सवर्णों का बोलबाला रहा लेकिन बाद के वर्षों में सवर्णों की जगह दलित और पिछड़ी जातियों ने ले ली और अब राजनीति भी दलित और पिछड़ों के इर्द-गिर्द तक सिमट कर रह गई है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि कभी राजनीति के शीर्ष में अहम भूमिका निभाने वाला सवर्ण समुदाय अब राजनीति में सिर्फ रस्म अदायगी भर की होकर गई है। श्रीकृष्ण सिंह, दीप नारायण सिंह, बिनोदानंद झा, केदार पांडेय, बिंदेश्वरी दूबे, भागवत झा आजाद, जगन्नाथ मिश्र वो नाम हैं जिन्होंने बिहार में मुख्यमंत्री पद के तौर पर राज किया और ये सभी सवर्ण समुदाय से हैं।

अप्रैल 1946 से 1977 तक बिहार में (कुछ समयों को छोड़कर) सवर्ण जाति के मुख्यमंत्री रहे। इसी से समझा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में सवर्ण तबका कितना प्रभावशाली था और कैसे सत्ता का चक्र इनके इशारों पर चलता रहा। 1977 के बाद बिहार की राजनीति से सवर्ण समुदाय का वर्चस्व खत्म होने लगा और मंडल कमीशन के बाद सवर्ण समुदाय की भूमिका काफी सीमित हो गई। जगन्नाथ मिश्रा बिहार के सवर्ण जाति से अंतिम मुख्यमंत्री थे।

1990 में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने और तब से लेकर अब तक बिहार में पिछड़ी या ओबीसी समुदाय से ही मुख्यमंत्री हैं। जहां लालू प्रसाद यादव की पहचान सामाजिक न्याय के मसीहा के तौर पर होती है वहीं नीतीश कुमार की पहचान बिहार को विकास की नई पहचान देने वाले सीएम के तौर पर होती है। राष्ट्रीय जनता दल में सवर्ण चेहरा माने जाने वाले शिवानंद तिवारी का कहना है कि ऐसा नहीं है कि बिहार में सवर्ण कोई फैक्टर नहीं हैं और उदारीकरण के दौर में जातियों का बंधन टूटा। सवर्ण जातियों को छोड़कर दूसरी जातियों में ये बात घर करने लगी है कि जिसकी जितने भागेदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। शिवानंद तिवारी के मुताबिक, मध्यम वर्ग में अधिकतम संख्या सवर्ण समुदाय की होती है और जैसे-जैसे उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण का प्रभुत्व बढ़ता गया सवर्ण समुदाय ने खुद को ड्राइंग रूम की राजनीति में समेट लिया। बिहार में फिलहाल जनता दल यूनाइटेड, एलजेपी और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार है।

जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन के मुताबिक, बिहार में जातिगत राजनीति जितना लालू यादव ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि, नीतीश कुमार सामाजिक न्याय के साथ विकास की बात करते हैं। दूसरी ओर आंकड़ें बताते हैं कि सवर्ण समुदाय का परंपरागत रूझान कांग्रेस से शिफ्ट होकर भाजपा की तरफ हो गया है और ये आज की तारीख में भाजपा का बड़ा राजनीतिक आधार है। हालांकि भाजपा प्रवक्ता अजीत चौधरी के मुताबिक, पार्टी जातिगत राजनीति में भरोसा नहीं करती है।

● **विनोद बक्सरी**

बिहार को लेकर नजरिया बदलने की जरूरत

चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एडीआर के बिहार प्रमुख राजीव कुमार जाति के आधार पर वोट की तलाश करने वाले दलों को आगाह करते हैं। वे कहते हैं कि बिहार को लेकर नजरिया बदलने की जरूरत है। जाति सबसे ऊपर होती तो कर्पूरी ठाकुर, श्रीबाबू और नीतीश कुमार को इतनी प्रतिष्ठा नहीं मिलती, क्योंकि उक्त तीनों नेता जिस-जिस जाति का प्रतिनिधित्व करते आए हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। लालू प्रसाद को कुछ हद तक इसलिए कामयाबी मिल गई कि उन्होंने जातियों का समीकरण बनाया था। लेकिन वोटरों की मानसिकता बदली तो उन्हें भी हाशिये पर जाते देर नहीं लगी। जाहिर है, सबको सड़क, बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाएं चाहिए। सुशासन चाहिए ताकि बेटियां घर से पढ़ने निकलें तो समय से सकुशल लौटें।

अस्तित्व के लिए संघर्ष

अपनी खोई हुई स्थिति को फिर से पाने के लिए आईएसआईएस ने हाल ही में अपनी महिला टुकड़ी का इस्तेमाल करते हुए सीरिया के अल होल कैंप स्थित हसाका में आगजनी और श्रृंखलाबद्ध हिंसा को अंजाम दिया। यह एक निराशा भरा और बिना सोचा-विचारा गया कदम था। हिंसा के परिणाम स्वरूप दो बच्चों की मौत हो गई और कई महिलाओं को गंभीर चोंटें आईं जिनमें ज्यादातर घायल बच्चों की मां थीं। इस हमले के दो मकसद थे। पहला, महिलाओं पर कथित ज्यादतियों के बहाने नाटो बलों की छवि खराब करना और दूसरा, दुनियाभर में इस्लामी खलीफा के विश्वासियों की सहानुभूति प्राप्त करना। लेकिन इस घटना से आईएसआईएस के हमदर्दों में उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं पनपी। इसके विपरीत, सीरियाई बलों की समय पर कार्रवाई से, संगठन की योजना समय से पहले ही ध्वस्त हो गई। इसे दूसरा झटका तब लगा जब, आईएसआईएस के धार्मिक नेता और उपदेशक, जिसे शफिया अल-नामा उर्फ अबु अब्द-अल बारी नाम से जाना जाता है, को स्थानीय नागरिकों की मदद से मोसुल से गिरफ्तार किया गया। वह विद्वानों को कैद-फांसी देने से संबंधित क्रूर फतवों, 2014 में जोनाह की कब्र पर बमबारी, उत्तेजक भाषण देने और सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। स्थानीय लोगों की मदद से उसकी गिरफ्तारी से पता चलता है कि क्षेत्र में आईएसआईएस की स्वीकार्यता घटी है और लोकप्रियता में कमी आई है।

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह आईएसआईएस कैडर के लिए एक बड़ा झटका है, जो अपने संस्थापक और प्रमुख रहे अल बगदादी की हत्या के बाद से अपने एजेंडे को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी से संबंधित एक और घटना में फिलिस्तीन ने अमेरिकी शांति समझौते की निंदा की। आईएसआईएस इसे पूरी दुनिया में यहूदियों को लक्षित कर खुद को पुनर्जीवित करने के लिए नए अवसर के रूप में देख रहा है। फिलिस्तीन का समर्थन करके आईएसआईएस का नया नेतृत्व मीडिया का ध्यान खींचने के साथ फिलिस्तीनियों का भी सहयोग हासिल करना चाहता है। साथ ही वह इस बात का प्रचार करना चाहता है कि विश्व के बड़े हिस्से में उसका प्रभाव है और यहूदियों से सहानुभूति रखने वालों पर रासायनिक हथियारों का उपयोग कर दुनियाभर में यहूदियों के खिलाफ जिहाद छेड़ना चाहिए। शुरू में इस तरह के आक्रामक प्रचार को वास्तविकता के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन भविष्य में इस गुब्बारे के फूटने के पूरे आसार हैं।

यहां एक बात महत्वपूर्ण है। आईएसआईएस जहां भी अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहा है, वहां जनता ने उसकी आतंकवादी गतिविधियों की तीखी आलोचना की है। पश्चिमी अफ्रीका के लोगों का अब उस संगठन की विचारधारा से मोहभंग हो रहा है, क्योंकि आईएसआईएस के पश्चिम अफ्रीका प्रांत (आईएसडब्लूएपी) नामक संगठन ने अफ्रीका के बुर्किना फासो, नाइजीरिया और साहेल क्षेत्र में भीषण हमले किए थे। इस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए थे। दुनिया के अन्य हिस्सों में अपनी उपस्थिति, ताकत और गढ़ पर कब्जा दिखाने की आईएसआईएस की चाल का परिणाम, संगठन के लिए पूरी तरह विफल रहा है। साथ ही जनता की हतोत्साहित करने वाली प्रतिक्रिया की वजह से भी इसे भारी झटका लगा है। यही वजह है कि आईएसआईएस की गतिविधियों में गिरावट आ रही है। इसलिए अब आईएसआईएस के वीभत्स चेहरे को हटाने के लिए नए सिरे से आक्रामक होने की जरूरत है।

इस बीच, एक गैर-कुरैश 'आमिर मोहम्मद अब्दुल रहमान अल-मावली अल-सल्बी' को नया आईएस नेता नियुक्त किया गया। चर्चा है कि यह वही अब्दुल्ला कर्दाश है जो अक्टूबर 2019 में मारा गया था। इस संगठन के दूसरे लोगों में असंतोष बढ़ गया है। इससे भविष्य में संगठन पर गंभीर असर हो सकता है, क्योंकि माना जाता है कि कुरैशी जनजाति का कोई व्यक्ति ही अपने समुदाय (उम्माह) का नेतृत्व कर सकता है।

आईएस के खातों पर अंकुश लगने से भी संगठन की स्थिति कमजोर हो रही है। इसमें नए कैडर की भर्ती में गिरावट आ रही है। अब आईएस को जिहादी प्रचार जारी रखने में भी परेशानी आ रही है। यह जिहादी प्रचार को गुमनाम तरीके से जारी रखने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। इसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा सकता है। आईएस की टेक्नोलॉजी इकाई एएफएक्यू (इलेक्ट्रॉनिक होराइजंस फाउंडेशन) नई वेबसाइट और नए दिशा-निर्देश, वीडियो उपलब्ध करा रही है। यह बता रही है कि रॉयट्स, कनवर्सेशन, श्रीमा, टम-टम, टेलीग्राम, मस्टोडोन, मीवी, ब्लॉक चेन मैंसेजर (बीसीएम), माइंड्स, नंदबॉक्स, पिंगल, हूप, लाइकी, टिक-टॉक, मैट्रिक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कैसे ठीक ढंग से इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट के बारे में सचेत भी कर रहे हैं।

● **बिन्दु माथुर**

आईएसआईएस पतन की ओर

जमीनी समर्थन में कमी और हाल ही में टेलीग्राम द्वारा आईएस खातों को अलग-थलग करने के कारण, आईएसआईएस अपने अस्तित्व को बचाए रखने के महत्वपूर्ण चरण से गुजर रहा है। फिलहाल वह इस स्थिति में नहीं है कि 12 अलग-अलग एप पर करीब 300 चैनल्स, समूहों, चैट आदि को जारी रख सके। यहां यह बताना उचित होगा कि नवगठित आईएसडब्ल्यूएपी को नाइजीरिया के बोर्नो-माली के स्थानीय लोगों की तरफ से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। सुरक्षा बलों ने भी इस क्षेत्र में उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। दूसरे शब्दों में कहें तो लोगों ने आईएसडब्ल्यूएपी के गेम प्लान को समझ लिया है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस्लामिक खलीफा की स्थापना के नाम पर साइबर स्पेस में अपने आक्रामक प्रचार के बावजूद आईएसकेपी अफगानिस्तान में विलुप्त होने के कगार पर है। हाल ही में, कुनार प्रांत के रूप में एक मजबूत क्षेत्र भी उसके हाथ से निकल गया है।

ऑयल वॉर

इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस से लड़ रहा है। लेकिन इस स्थिति में भी चीन और अमेरिका ट्रेड वॉर के बाद दुनिया सऊदी अरब व रूस के ऑयल वॉर से जूझ रही है। इससे कच्चे तेल की कीमत औंधे मुंह गिर गई है। खाड़ी युद्ध के बाद पहली बार तेल के मूल्य में इस कदर गिरावट आई है। जनवरी से अब तक कच्चे तेल के मूल्यों में 45 फीसदी की कमी आ चुकी है। तेल की कीमतों को ये झटका ऐसे वक्त लगा है, जब दुनिया कोरोना संकट का सामना कर रही है। वर्तमान में भारत को जरूर इसका लाभ मिलता दिख रहा है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होगी।

दिसंबर 2016 में रूस और सऊदी अरब ने वियना में 11 गैर ओपेक देशों और ओपेक देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते का उद्देश्य था कि तेल की कीमतों को स्थिर रखा जाए। शुरुआत में यह डील छह माह के लिए की गई थी, लेकिन बाद में समय सीमा बढ़ती चली गई। इसे ही 'ओपेक प्लस' कहा गया। इसमें ओपेक और रूस के नेतृत्व वाले गैर ओपेक देश तेल उत्पादन को लेकर संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार सहयोग करते रहते थे।

ओपेक प्लस की नींव वर्ष 2014 और 2016 में तेल की कीमतों में नाटकीय गिरावट ने रखी थी। दिसंबर 2019 में इस समझौते को 20 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया था और उम्मीद की जा रही थी कि यह आगे भी जारी रहेगा। इस बीच रूस और सऊदी अरब ने अपने-अपने आर्थिक हितों के हिसाब से समझौतों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन छह मार्च को अप्रत्याशित घटना सामने आई। वियना में सऊदी अरब ने रूस के सामने तेल उत्पादन में कटौती का प्रस्ताव रखा, जिससे मांग के हिसाब से कीमत को स्थिर रखा जा सके। रूस ने न केवल इस मांग को खारिज कर दिया, बल्कि उसने घोषणा कर दी कि अब वह पहले की तरह वियना समझौते से बंधा नहीं रहेगा। इसका नतीजा यह हुआ कि ओपेक प्लस खत्म हो गया। यहीं से रूस और सऊदी अरब में तेल को लेकर विवाद शुरू हुआ जिसे अब ऑयल वॉर कहा जा रहा है। सऊदी अरब और रूस के बीच तेल की कीमतों को लेकर तनाव और बढ़ता जा रहा है। हालांकि रूस के इस कदम के बाद सऊदी अरब ने तेल सस्ता कर आपूर्ति बढ़ाने की बात कही है।

रूस और सऊदी अरब के इस विवाद का सबसे गहरा प्रभाव अमेरिका पर होगा। शेल ऑयल की वजह से अमेरिका तेल आयातक देश से अब तेल उत्पादक देश बन चुका है। एक नई तकनीक जिसे 'फ्रेंकिंग' कहा जाता है, इसका इस्तेमाल कर अमेरिका वर्ष 2018 में दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश बन गया। अमेरिका ने अपनी कूटनीतिक ताकत का प्रयोग करके अपने यहां से तेल आयात करने वाले देशों की संख्या भी बढ़ा ली है।

दरअसल इस विवाद के द्वारा रूस और सऊदी अरब अपने तेल वर्चस्व में वृद्धि करना चाहते हैं, वहीं अमेरिका के शेल ऑयल इंडस्ट्री को तबाह भी करना चाहते हैं। अमेरिकी शेल ऑयल की कीमत 50 डॉलर प्रति बैरल से कम करना संभव नहीं है। जाहिर है सस्ता तेल अमेरिका के इस उद्योग को तबाह कर देगा। रूस का मानना है कि तेल की कीमतों में इजाफा और उत्पादन में कटौती के कारण अमेरिकी शेल ऑयल को उत्पादन बढ़ाने का मौका मिला। रूस का अनुमान है कि वर्तमान तेल मूल्यों पर अमेरिकी शेल ऑयल कंपनियां डूब जाएंगी या फिर उन्हें नए तरीके से संवारना होगा। शेल तेल का उत्पादन अमेरिका में कुटीर उद्योग के तहत होता है।

सऊदी अरब के पास इतना बजट है कि अगर तेल की कीमतें कम रहती हैं तो अर्थव्यवस्था को संभाल ले। हालांकि उसका बजट घाटा पहले ही 50 अरब डॉलर है। अगर तेल की कीमतें गिरती रहीं तो उसे 70 से 120 अरब डॉलर वार्षिक का नुकसान हो सकता है। सऊदी अरब ने उत्पादन और निर्यात में बढ़त बना ली है, इसलिए उसे बहुत अधिक नुकसान होता नहीं दिख रहा है। वहीं रूस ने बीते पांच वर्षों में अपने बजट को इस तरह नियंत्रित किया है कि वो 550 अरब डॉलर अपने खजाने में जुटाने में सफल रहा है, ताकि भविष्य में एक दशक तक भी तेल की कीमतें गिरकर 25 से 30 डॉलर प्रति बैरल रहीं, तो भी उसे बहुत नुकसान न झेलना पड़े।

बीते सप्ताह कच्चे तेल की कीमत 30 डॉलर प्रति बैरल थीं। अगर ये घटकर 27 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया, तो रूस को अपना बजट पूर्ववत बनाए रखने के लिए हर साल फंड से 20 अरब डॉलर निकालने होंगे। रूस ने हाल के वर्षों में विकास पर स्थिरता लाने पर जोर दिया है और कई मायनों में वर्तमान हालत पहले के मुकाबले बेहतर हैं। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था 90 प्रतिशत तेल पर निर्भर है, जबकि रूस की अर्थव्यवस्था में तेल का योगदान केवल 16 प्रतिशत है। इस तरह इस संकट से सऊदी अरब ज्यादा नुकसान में है।

● **अक्स ब्यूरो**

भारत को संतुलन बनाए रखने की जरूरत

यूरोप अभी इस स्थिति में नहीं है कि वह एक संगठित समूह के रूप में आचरण कर सके। उसकी ऊर्जा सुरक्षा को अमेरिका किस तरह सुरक्षित रखेगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस संकट के कारण पिछली सदी के नौवें दशक के बाद से नॉर्वे की मुद्रा में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मेक्सिको की मुद्रा पैसो में भी 8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण की योजना को पलीता लग सकता है। मोहम्मद बिन सलमान की ज्यादातर योजनाओं के लिए पैसा आरामको के शेयरों की बिक्री से आ रहा है। लेकिन दांव पर दूसरे तेल उत्पादक देशों का भी बहुत कुछ लगा हुआ है। इस संकट का दूरगामी परिणाम पूरी दुनिया के लिए नकारात्मक ही होंगे। इसलिए भारत के लिए भी यही अच्छा होगा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था ठीक रहे, जिसमें खाड़ी देशों सहित अमेरिका की भी अर्थव्यवस्था शामिल है। जब तक तेल के मूल्य कम हो रहे हैं, उसके कुछ हिस्से का हस्तांतरण सरकार द्वारा जनता को भी किया जाना है, जबकि कुछ हिस्से का प्रयोग सरकार द्वारा राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए भी किया जाना चाहिए। भारत सरकार को इन दोनों में संतुलन बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि तेल मूल्यों में कटौती से जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, जो अर्थव्यवस्था के चक्र को गति प्रदान करेगी।

देश में अब महिलाएं कई क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। कई निजी संस्थान तो ऐसे हैं जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है।

महिलाओं की एक और बड़ी जीत

थलसेना और वायुसेना के बाद नौसेना की महिला अधिकारियों को भी अब स्थायी कमीशन मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में महिला अधिकारियों को नौसेना में स्थाई कमीशन देने पर अपनी मुहर लगा दी है। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने नौसेना में पुरुष और महिला अधिकारियों के साथ समान व्यवहार किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि सैन्य बलों में महिलाओं को लैंगिक समानता नहीं देने के बहाने नहीं चल सकते। उनके लिए समान अवसर देने की जरूरत है।

ऐसे पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य हैं, जिनसे पता चलता है कि नौसेना में महिला अधिकारियों ने ढेरों उपलब्धियां प्राप्त की हैं। अदालत ने इस संबंध में केंद्र को जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए तीन महीने का समय दिया है। अदालत के इस आदेश के बाद महिला अधिकारियों को भी स्थायी कमीशन मिलेगा और वे अपने पुरुष सहयोगियों की ही तरह नौसेना से सेवानिवृत्त होंगी। उन्हें पेंशन आदि लाभ भी मिलेंगे। अभी तक नौसेना में महिलाओं को केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन ही मिलता था और उनकी तैनाती प्रशासनिक, चिकित्सा और शैक्षणिक विभागों में ही की जाती थी।

थलसेना और वायुसेना की महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन मिलने के बाद, नौसेना की 19 महिला अफसरों ने अपना हक पाने के लिए, दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने अदालत से नौसेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिलाने का अनुरोध किया ताकि उन्हें भी पेंशन जैसे सेवानिवृत्ति लाभ मिल पाएं। बहरहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2010 में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में महिला अधिकारियों को शार्ट टर्म कमीशन के बाद, जबरन सेवानिवृत्त करने के सरकार के निर्णय को गलत ठहराते हुए, रक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता महिला अधिकारियों को जल्द से जल्द स्थाई कमीशन प्रदान किया जाए।

केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय चली गई। अदालत में उसने दलील दी कि नौसेना में महिला अधिकारियों को समुद्र में जाने की ड्यूटी नहीं दी जा सकती क्योंकि, रूस निर्मित जहाजों में उनके लिए अलग से स्नानागार नहीं हैं। इसके अलावा महिलाओं की शारीरिक स्थिति और पारिवारिक दायित्व जैसी बहुत-सी बातें उन्हें कमांडिंग अफसर बनाने में बाधक हैं। उस वक्त भी शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि वह अपने दृष्टिकोण और मानसिकता में बदलाव लाए। उसकी यह सोच, अतार्किक और समानता के अधिकार के खिलाफ है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की इस बेतुकी दलील को स्पष्ट तौर पर खारिज करते हुए कहा कि ऐसी दलीलें केंद्र की साल 1991 और 1998 की नीति के खिलाफ हैं। अदालत ने इसके साथ ही साल 2008 से पहले नौसेना में शामिल की गई महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने पर पड़ने वाले प्रभाव को भी निरस्त कर दिया। अदालत ने सेवानिवृत्त हो चुकी उन महिला अधिकारियों को पेंशन का लाभ भी प्रदान किया, जिन्हें स्थायी कमीशन नहीं दिया गया था। अदालत ने केंद्र सरकार को उन पांच महिला अधिकारियों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया, जिन्हें दोबारा बहाल नहीं किया गया।

नौसेना में अफसर चाहे पुरुष हों या महिलाएं, उनकी नियुक्ति शॉर्ट टर्म कमीशन में यानी चौदह साल के लिए की जाती है। अभी तक होता यह रहा है कि चौदह साल के बाद पुरुष अफसरों को तो स्थायी कमीशन दे दिया जाता है, लेकिन महिला अफसरों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अलग फैसले में सेना के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आने वाली महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने को सही ठहराया था। नौसेना में शार्ट सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती होने वाली महिलाओं को अभी चार शाखाओं में स्थायी कमीशन के लिए विचार होता है। इनमें शिक्षा, कानून, नौसेना पोत निर्माण और नौसेना हथियारों के रखरखाव से जुड़ी शाखाएं शामिल हैं। ये शाखाएं ऐसी हैं, जहां महिला अधिकारियों को समुद्र के भीतर पोतों में तैनात नहीं होना पड़ता। लेकिन अदालत के हालिया फैसले के बाद, यह रुकावट दूर होगी। जंगी पोतों पर अब महिला अफसरों की तैनाती का रास्ता साफ होगा। अगर सरकार और सेना दोनों, महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने को तैयार हुए हैं, तो वह भी अदालत के दखल के बाद ही मुमकिन हो पाया है।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

महिलाओं के भरोसे

भारतीय सेनाओं में महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार पद और प्रतिष्ठा तो मिल ही रही है, निजी संस्थानों में भी महिलाओं को अधिक महत्व दिया जा रहा है। खासकर बैंकिंग और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तो महिलाएं ही फ्रंट लाइन पर हैं। कई संस्थान तो महिलाओं के भरोसे ही चल रहे हैं। इसलिए आज सरकारी और गैर सरकारी हर जगह महिलाओं को महत्व दिया जा रहा है। यह भारत के विकास की दिशा में क्रांतिकारी पहल है। वह दिन दूर नहीं जब पुरुषों को किसी बड़े पद को पाने के लिए महिलाओं से मुकाबला करना पड़ेगा।

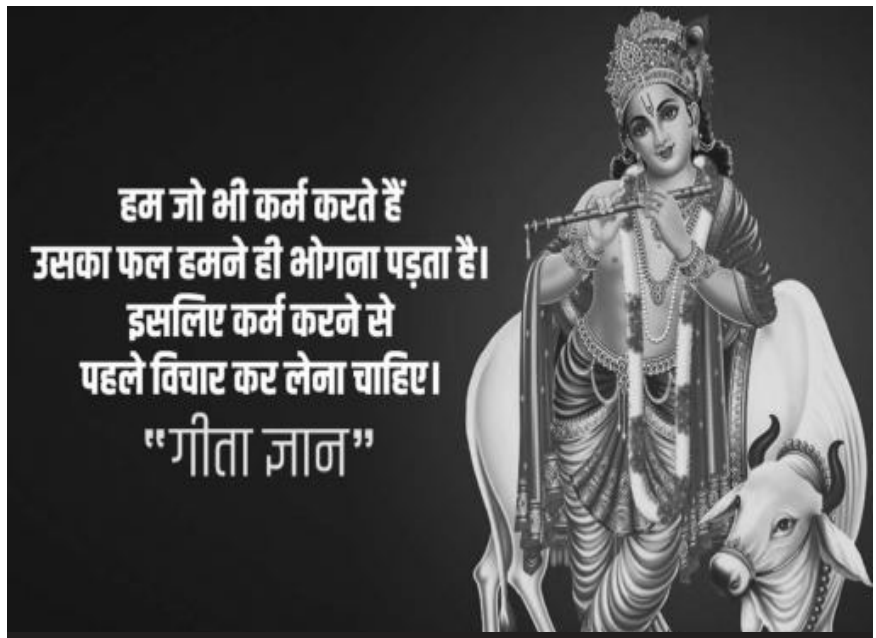

क्रोध सबसे बड़ा शत्रु

श्रीमद्भगवत गीता में जीवन का सार छिपा है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ का अध्ययन करने से व्यक्ति को अपने जीवन की सभी समस्याओं का हल मिल सकता है। महाभारत युद्ध में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश किसी के लिए भी प्रेरणा का स्त्रोत साबित हो सकते हैं। श्रीकृष्ण की कही गईं बातों का प्रभाव अर्जुन पर ऐसा पड़ा कि वह युद्ध भूमि में फिर से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ अग्रसर हो गया। वैसे तो गीता में जीवन-मरण से संबंधित बहुत सी बातें बताई गई हैं लेकिन यहां आप जानेंगे गीता की कुछ ऐसी बातें जो आपको अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर काम आ सकती हैं।

नाम, पद, प्रतिष्ठा, संप्रदाय, धर्म, स्त्री-पुरुष हम नहीं हैं और न यह शरीर हम हैं। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा स्थिर है और हम आत्मा हैं। आत्मा कभी नहीं मरती है। न इसका जन्म है और न मृत्यु! आत्मभाव में रहना ही मुक्ति है। परिवर्तन संसार का नियम है। यहां सब बदलता रहता है। इसलिए सुख-दु:ख, लाभ-हानि, जय-पराजय, मान-अपमान आदि में भेदों में एक भाव में स्थित रहकर हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। अपने क्रोध पर काबू रखो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। इससे स्मृति का नाश होता है और इस प्रकार व्यक्ति का पतन होने लगता है। क्रोध, कामवासना और भय ये हमारे शत्रु हैं। हमें अपने देखने के नजरिए को शुद्ध करना होगा और ज्ञान व कर्म को एक रूप में देखना होगा, जिससे हमारा नजरिया बदल जाएगा। श्रीमद्भगवत गीता में सफलता का राज छुपा है। जो व्यक्ति गीता के सार को अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है वह हर प्रकार के दुखों से मुक्ति पा लेता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन दुविधा में फंस गए तब कुरूक्षेत्र में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया था। श्रीमद्भगवत गीता के उपदेश में जीवन को जीने की कला छिपी हुई है ये कहना गलत नहीं होगा। गीता पढ़ने से मन को शांति मिलती है। गीता अच्छे और बुरे का भेद बताती है। गीता के अनुसार क्रोध व्यक्ति का नाश कर देता है। श्रीमद्भगवत गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में व्यक्ति अपना नियंत्रण खो देता है। आवेग में उसके द्वारा अनैतिक कर्म भी हो जाता है। क्रोध से दूर रहने के लिए व्यक्ति को प्रेम, ज्ञान और अध्यात्म की शरण में जाना चाहिए। अध्यात्म की शक्ति से व्यक्ति क्रोध पर काबू पा सकता है। प्रेम व्यक्ति को निर्मल बनाता है। जिसने प्रेम की शक्ति को पहचान लिया समझो उसने प्रभु को पा लिया। प्रभु को पाने का एकमात्र सरल रास्ता प्रेम ही है। क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। क्रोध करने से लोग दूर होने लगते हैं। क्रोधी व्यक्ति समाज में अकेला रह जाता है। क्रोध मनुष्य को मानव से दानव की श्रेणी में ले जाता है।

जो लोग कार्य करने से पहले ही परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं वह कभी सफल नहीं होते हैं। व्यक्ति को सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए। परिणाम की लालसा मन में नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति को पूरी ईमानदारी और नैतिकता से अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। जब कार्य को अनुशासन, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से पूर्ण किया जाता है तो उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। इसलिए व्यक्ति को कार्य की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वह कभी दुखी नहीं रहते हैं। क्रोध करने से बचना चाहिए। क्योंकि क्रोध करने से व्यक्ति असुर बन जाता है। क्रोध करने पर वह अच्छे बुरे का अंतर भूल जाता है। क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने क्रोध पर नियंत्रण करना सीख लिया वही महानता की ओर अग्रसर हुआ है।

जो व्यक्ति सदैव दूसरों की वस्तुओं पर ललचाता रहता है ऐसा व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता है। लालच का परित्याग करना चाहिए। यह एक मानसिक बीमारी है जो एक दिन व्यक्ति के सामाजिक पतन का कारण बन जाती है। जो आया है वह जाएगा। जिसने जन्म लिया है उसके मृत्यु का भी दिन सुनिश्चित है। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद भी मेरा तेरा, अपना पराया में जो लोग फंसे रहते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्राप्त हुआ है। जिसने इसके महत्व को पहचान लिया वही अमर हो गया। जो व्यक्ति सभी को साथ लेकर चलते हैं ऐसे लोग समाज में सम्मान तो पाते ही हैं साथ ही साथ उनका अनुसरण भी किया जाता है। यह भाव निस्वार्थ होना चाहिए। इसमें कोई लालच नहीं होना चाहिए। लालच में यह भाव बदल जाएगा। जिसके चलते वह परिणाम नहीं आएंगे जिसकी कल्पना की है। स्वच्छता शरीर के बाहर की नहीं अंदर की भी होनी चाहिए। मन की स्वच्छता बहुत जरूरी है। जब तक मन साफ नहीं है, सोच अच्छी नहीं और भाव सुंदर नहीं है तब तक पूरी तरह से स्वच्छ नहीं माने जाओगे।

श्रीमद्भगवत गीता में जीवन का सार छुपा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतार ले तो वो किसी भी परिस्थिति का सामना डटकर कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता है। गीता के पूर्ण ज्ञान को अपने जीवन में उतारना हर किसी के बस की बात नहीं है लेकिन गीता के कुछ उपदेश ऐसे हैं जिन्हें हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। अगर व्यक्ति गीता के इस प्रमुख उपदेशों को अपने जीवन में शामिल कर लेता है तो उसे जीवन की हर समस्या का हल मिल जाता है और उसका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है।

● ओम

साक्षात्कार

पिता की मृत्यु के पश्चात, घर की तंगहाली और बड़ी होने का फर्ज निभाने की खातिर नौकरी करना स्वर्णा की मजबूरी बन गया था।

'आज उसका पहला साक्षात्कार था'

पहले कभी कोई काम किया है?, मैनेजर बोला!

जी नहीं, यह मेरी पहली नौकरी हैं! स्वर्णा बोली!

आपको क्यों लगता है कि आप इस नौकरी के काबिल हैं?, मैनेजर बोला!

'मैं जिंदगी में कुछ करके दिखाना चाहती हूं और मुझे लगता है कि यहां मेरे लिए पर्याप्त अवसर है!' वह विश्वास से बोली!

'किस प्रकार के अवसर?' मैनेजर के नजरों की छुअन उसके शरीर पर रेंगने लगी थी!

कुछ और प्रश्नों के बाद वह अपनी औकात पर आ गया! 'आप जैसी कर्मठ कर्मचारी इस कंपनी में बहुत तरक्की कर सकती है! बस, कुछ फुरसत के पल हमारे साथ बिताने होंगे!' उसका हाथ बढ़ कर स्वर्णा के हाथों को छू रहा था!

स्वर्णा घबराई, पर अगले ही पल, 'तड़ाक' की आवाज के साथ मैनेजर के गालों पर एक पुरानी राजनीतिक पार्टी की छाप छप गई!

बाहर आकर स्वर्णा ने नोटपैड पर नजर डाली और एक बार फिर से वह, पूरे आत्मविश्वास के साथ दूसरे साक्षात्कार पर जाने के लिए तैयार थी!

— अंजु गुप्ता

विधवा होना कोई कलंक नहीं

विमला की शादी को अभी 4 वर्ष पूरे भी नहीं हुए थे कि अचानक एक दिन उसको अशुभ समाचार प्राप्त हुआ कि उसके पति देव अशोक अब इस दुनिया में नहीं रहे। विमला अपने मन में यह सोच रही थी कि मैं कितनी मनहूस स्त्री हूं जो इतने कम समय में विधवा हो गई हूं।

और रोने लगी तभी विमला की नंद, ससुर और सास आ गई और कहने लगी कि बेटा तुम चिंता क्यों करती हो।

हम उनमें से नहीं जो तुम्हें ताना मारेंगे। जब तुम इस घर में आई थी तभी से हमने तुम्हें अपनी बेटी माना है बहू तो कभी माना ही नहीं। रही बेटे के जाने की बात यह तो ऊपर वाले की इच्छा थी जो बेटा अब इस दुनिया में नहीं है।

विमला यह सब सुनकर नरम आंखों से रोने लगी और कहने लगी यदि आप जैसे माता-पिता समान सास-ससुर, नंद सबको मिल जाए तो विधवा को मनहूस कहने वाले लोगों की जबान बंद हो जाए।

मैं बहुत ही भाग्यवान हूं जो मुझे आप जैसे सास-ससुर मिले।

— अमित राजपूत

चूल्हे में जलती रोटी

देख उबलती खिचड़ी मन की हांडी में
आज तवे पर जल बैठी फिर से रोटी

एक तरफ चूल्हे में ये रोती लकड़ी
आधी गीली कलमूई आधी सूखी
ऊपर से ये लंगड़ा चिमटा दुखदाई
और फूंकनी मेरी सांसों की भूखी
मन में घूमे कितने हाय हिंडोले ये
और समस्या घर की ये छोटी मोटी
आज तवे पर जल बैठी फिर से रोटी

जबसे इसने खोले हैं कुछ वातायन
छत की टंकी रहती है हर दम खाली
रोज टपकते हैं पापड़ दीवारों से
हुई ठसाठस शौचालय की है नाली
कभी नहीं जाती है अपने पाले में
मेरी किस्मत के कैरम की ये गोटी
आज तवे पर जल बैठी फिर से रोटी

बबलू की टीशर्ट बगल से फटी हुई
आंखों की कमजोर हुई है बीनाई
सास-ससुर को घेर लिया बीमारी ने
टॉमी भी करता फिरता है उबकाई
बिजली का बिल भरा नहीं था कट ही गई
अंधियारा भी नोचे है बोटी-बोटी
आज तवे पर जल बैठी फिर से रोटी

दरवाजे भी खूब सिसकते रातों में
जब से तुम अपनों से रिश्ता तोड़ गए
जर्जर घर में मकड़ी और छिपकलियां हैं
मुझको ये कैसी दुनिया में छोड़ गए
पहले लगता था यह रब की मर्जी है
अब लगता है मेरी किस्मत ही खोटी
आज तवे पर जल बैठी फिर से रोटी

— राजेश कुमारी राज

एक मां की महत्वाकांक्षा की देन साइना नेहवाल जैसा अनमोल रत्न

भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल अपने लगभग हर साक्षात्कार में एक बात जरूर कहती हैं, 'मैं अपने माता-पिता अपने कोच और अपने देश के लिए खेलती हूं।' कोर्ट से बाहर भी ये तीन चीजें उनके लिए सबसे ज्यादा महत्व रखती हैं। लेकिन, शायद ही कुछ लोग इस बात को जानते हों कि अगर आज साइना जैसी खिलाड़ी देश को मिली है तो इसका सबसे ज्यादा श्रेय उनकी मां ऊषा रानी को जाता है। किसी बच्चे के जन्म के बाद उसकी मां को उसका प्रथम शिक्षक कहा जाता है। लेकिन, साइना के मामले में उनकी मां उनकी प्रथम शिक्षक के साथ-साथ उनकी पहली कोच भी थीं। एक साक्षात्कार में अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताते हुए साइना कहती हैं कि उनके पिता हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक के पद पर काम करते थे जबकि मां राज्य स्तर की बैडमिंटन खिलाड़ी थीं। उनकी मां का नाम हिसार जिला बैडमिंटन संघ में भी दर्ज है और उन्होंने क्लब स्तर पर भी काफी बैडमिंटन खेला है। साइना के मुताबिक उनकी मां ने उनके जन्म के बाद आधिकारिक तौर पर खेलना छोड़ दिया था। फिर भी वे रोज शाम को शौकिया तौर पर कृषि विश्वविद्यालय के क्लब में बैडमिंटन जरूर खेलने जाया करती थीं। इस दौरान साइना और उनकी बड़ी बहन भी उनके साथ होती थीं।

मां के दिमाग में उन्हें एक बड़ा खिलाड़ी बनाने के लक्ष्य के बारे में साइना कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहतीं। लेकिन, जिस तरह से उनकी मां ने उन्हें लेकर फैसले लिए या जिस तरह की घटनाएं उनके बचपन में हुईं, उनसे साफ हो जाता है कि मां ने साइना के लिए कुछ बड़ा सोच रखा था। साइना कहती भी हैं कि उनके जीवन के लगभग सभी बड़े फैसले उनकी मां ने लिए और घर में उनकी मां ही सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी भी रहीं। साइना को लेकर उनकी मां की महत्वाकांक्षा का एक अंदाजा इससे भी मिलता है कि उनकी मां ने जन्म से पहले ही उनका नाम 'स्टेफी' रखने के बारे में सोच लिया था। स्टेफी ग्राफ उस समय टेनिस की दुनिया में छाई हुई थीं। साइना बताती हैं कि हिसार में 8 साल की उम्र तक सभी लोग उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। इसके बाद जब उनके पिता का तबादला हैदराबाद हो गया तब उन्हें उनके आधिकारिक नाम साइना से बुलाया जाने लगा, लेकिन मां आज भी उन्हें स्टेफी ही बुलाती हैं।

1998 में पिता के तबादले के बाद हैदराबाद पहुंचने पर साइना के पिता को पता चला कि आंध्रप्रदेश खेल प्राधिकरण बैडमिंटन का एक समर कैंप आयोजित करने जा रहा है। उन्होंने 8 वर्षीय साइना को करीब एक महीने के लिए इस कैंप में भेजने का निर्णय लिया। साइना के मुताबिक हैदराबाद में यह कैंप लालबहादुर स्टेडियम में आयोजित होता था, जो कि उनके पिता को मिले सरकारी क्वार्टर से करीब 25 किलोमीटर दूर था। अपनी किताब 'मेरा रैकेट मेरी दुनिया' में वे लिखती हैं कि कैंप पहुंचने के लिए उनकी मां सुबह 5 बजे उठा करती थीं और उन्हें लेकर स्टेडियम जाती थीं। कैंप में उन्हें कई तरह के व्यायाम कराए जाते थे। साथ ही हर रोज 4 से 5 किलोमीटर दौड़ाया जाता था। उनकी मां इस ट्रेनिंग को करीब से देखती थीं। वे उनकी ट्रेनिंग को लेकर इतनी ज्यादा गंभीर थीं कि अक्सर वे उनके कोचों को भी समझाने लगती थीं। साइना की मां ट्रेनिंग के बाद घर पर भी उन्हें जमकर अभ्यास और व्यायाम कराती थीं।

साइना यह भी लिखती हैं कि एक महीने बाद इस समर कैंप की समाप्ति पर इसमें शामिल हुए सभी बच्चों में से एक को आगे की ट्रेनिंग के लिए चुने जाने की बात कही गई। इसके लिए उनका चयन किया गया। उनके मुताबिक कैंप के दौरान उन्हें लगता था कि मम्मी ने सिर्फ गर्मी की छुट्टियों की वजह से उन्हें इस कैंप में भेजा है। लेकिन, उनकी मां उनके खेल को लेकर काफी ज्यादा गंभीर थीं और उन्होंने स्कूल खुलने के बाद भी उनकी ट्रेनिंग को जारी रखने का फैसला किया। साइना के करीबियों की मानें तो समर कैंप में साइना के शानदार प्रदर्शन से उनकी मां समझ चुकी थीं कि उनकी बेटी लंबी रेस का घोड़ा साबित होने की काबिलियत रखती है।

● **आशीष नेमा**

मेरी मां हमेशा साथ खड़ी रही

2015 में विश्व की नंबर एक बैडमिंटन खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल कर चुकी साइना नेहवाल मानती हैं कि उनमें सपने देखने और आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति भी मां के कारण ही आई। वे एक घटना का जिक्र करते हुए बताती हैं कि जब वे 10 साल की थीं तब उन्होंने पहली बार अपनी मां से पूछा था कि दुनिया के सबसे अच्छे बैडमिंटन खिलाड़ी और उनमें क्या अंतर है? तब उनकी मां ने उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे कहा था कि उनकी मेहनती बेटी से कोई कैसे अच्छा हो सकता है। साइना के मुताबिक यह उनके लिए अचंभित करने वाला था क्योंकि उन्होंने 10 वर्ष की उम्र में यह प्रश्न मां से पूछा था और उनकी मां ने इस पर बिना हंसे इसे काफी गंभीरता से लिया था। वे कहती हैं कि इस प्रश्न का जवाब देते हुए मां के हाव-भाव ने उनमें पहली बार एक बड़ा खिलाड़ी बनने का विश्वास जगाया। साइना की मानें तो जिलास्तर पर खेल की शुरुआत करने से लेकर उनके अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बनने तक उनकी मां साए की तरह उनके साथ लगी रहीं। वे आधिकारिक कोच मिलने के बावजूद देश-विदेश में लगभग हर टूर्नामेंट में उनके साथ जाती थीं। साइना कहती हैं कि जहां मेरे पिता मेरा लाइव मैच देखने से घबराते रहते थे वहीं उनकी मां दृढ़ता के साथ मैच के दौरान सबसे आगे की पंक्ति में बैठा करती थीं। इस दौरान वे चिल्ला-चिल्लाकर उन्हें निर्देश दिया करती थीं। वे मैच के दौरान होने वाली गलतियों को देखती और बाद में साइना से इन पर लंबी चर्चा किया करती थीं। साइना नेहवाल हमेशा कहती हैं कि इस खेल के गुण उन्हें मां से ही मिले। साथ ही दृढ़ता, विश्वास, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य न खोना और एक चैंपियन की तरह सोचने जैसी खूबियां भी उन्हें मां से ही मिली हैं।

विदेश से आते ही प्रभास ने खुद को 14 दिन के लिए किया घर में बंद

कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी है। विदेश से शूटिंग करके लौटे बाहुबली फेम प्रभास ने भी खुद को घर में बंद कर लिया है। प्रभास ने सोशल मीडिया के जरिए खुद यह जानकारी दी। साथ ही फैंस से भी अपील की कि वे भी खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखें।

बता दें कि कोरोना वायरस के कारण दुनिया के कई देश बुरी तरह प्रभावित हैं। ऐसे में भारत सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि विदेश से आने वाला हर नागरिक खुद को कम से 14 दिन के लिए आइसोलेट करे। इस नियम का पालन करते हुए साउथ के मेगास्टर प्रभास ने खुद को अपने घर में बंद कर लिया है। बता दें कि प्रभास जॉर्जिया से लौटे हैं। उनके साथ पूजा हेगड़े और पूरी टीम मौजूद थी। पूजा हेगड़े ने भी सरकार के निर्देश का पालन करते हुए खुद को 14 दिन के लिए आइसोलेट कर लिया है।

फैंस से भी अपील

प्रभास ने एक लिखित पोस्ट शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने फैंस से भी अपील की है कि वे भी इस भयावह स्थिति में देश का साथ दें और खुद को सुरक्षित बनाए रखें। बता दें कि बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के स्टार्स इस समय कोरोना के कारण अपना काम बंद कर चुके हैं। सभी अपने परिवार के साथ समय बीता रहे हैं।

अब फिल्म नहीं चली तो बॉलीवुड छोड़ गांव में खेती करूंगा: शरमन जोशी

गॉड मदर, लज्जा, स्टाइल, गोलमाल, रंग दे बसंती और 3 इडियट्स जैसी बेहतरीन फिल्मों में अपने शानदार और जानदार अभिनय से बॉलीवुड में एक खास जगह बनाने वाले शरमन जोशी की पिछले कुछ सालों में कई सोलो फिल्में रिलीज़ हुईं, लेकिन उनकी सोलो फिल्मों को सफलता नहीं मिली। इन दिनों शरमन अपनी अगली रिलीज फिल्म बबलू बैचलर के प्रमोशन में जुटे हैं और इसी दौरान एक इंटरव्यू में शरमन ने कहा कि जब उनकी फिल्म नहीं चलती तो वह बॉलीवुड छोड़ अपने गांव में शिफ्ट होने का मन बना लेते हैं। फिल्म मिशन मंगल के पहले भी वह गांव जाकर खेती-बाड़ी करने का मन बना चुके थे, लेकिन मिशन मंगल सफल हो गई और फिलहाल

उन्होंने गांव शिफ्ट होने के प्लान को टाल दिया है।

जब मेरी कोई भी फिल्म नहीं चलती है तो ऐसा लगता है कि अपने गांव वापस लौट जाऊं, लगता वहीं गांव में अपना बसेरा रेडी रखूं, सपरिवार छोटी सी प्यारी सी जिंदगी व्यतीत करूं, गांव में खेती-बाड़ी करूं और कभी-कभार गांव वालों के मनोरंजन के लिए वहीं नाटक करूं और अपने अंदर जो आर्टिस्ट है, उसका भड़ास निकालूं।

ऋषि कपूर ने शेयर किया इटली का वीडियो बोले- ऐसे ही अनुशासन की जरूरत

ऋषि कपूर ने अपने ट्विटर हैंडल पर इटली का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें लॉकडाउन के दौरान के एक आदमी सड़क पर टहलता नजर आया। उसको देखते ही वहां की पुलिस आती है और उसे किक मारकर गिरा देती है। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लेती है। इस वीडियो के साथ ऋषि कपूर ने लिखा, हमें ऐसे ही अनुशासन की जरूरत है।

आइसोलेशन की खबरों पर रवि किशन ने कहा-

परिवार के साथ हूं, सेफ हूं

पिछले काफी दिनों दुनियाभर में कोरोना वायरस कहर बनकर छा गया है। कोरोना के असर अब भारत में भी दिखाई दे रहा है। कुछ हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ऐक्टर और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी कोरोना के डर से खुद को सेल्फ-आइसोलेशन में रखा है। हालांकि इन सभी रिपोर्ट्स को रवि ने बिल्कुल गलत बताते हुए खारिज किया है। दरअसल पहले बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर के साथ एक पार्टी में शामिल हुए थे जिसके बाद उन्होंने खुद को बाकी दुनिया से अलग कर लिया था। कनिका कपूर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद कहा जा रहा था कि दुष्यंत सिंह से मुलाकात करने के कारण रवि किशन ने खुद को सेल्फ-आइसोलेट कर लिया है।

अफवाह फैलाई जा रही... रवि ने बताया, मैं तो मुंबई स्थित अपने घर में हूं। न ही कोई टेस्ट करवाया, न किसी पार्टी में गया। मैंने कोई भी टेस्ट नहीं करवाया है। अफवाह फैलाई जा रही है। मैं अपने परिवार के साथ हूं, सुरक्षित और सेफ हूं।

एक शानदार व्यापार

मैडम जी नमस्कार! क्या हाल है? सब ठीक है न? अच्छा आपके बेरोजगार बेटे के लिए एक बढ़िया काम लाया हूं।

एक ही सांस में रस्तोगी जी ने कहा।

उषा मैडम रस्तोगी जी की बातों को सुनकर मुस्कुरा दीं। 'लगता है आपके बेटे की कोई लॉटरी लग गई है। नहीं तो आप मुझे देखते ही अपने बेरोजगार बेटे के लिए कोई रोजगार बताने को कहतीं। अब जब कोई ढंग की नौकरी आपके बेटे के लिए तलाशा हूं तो मोहतरमा बैठीं मुस्कुरा रही हैं।' रस्तोगी जी ने बेतकल्लुफ होकर कहा।

उषा मैडम ने कहा, 'जी हां रस्तोगी जी, लॉटरी लग गई समझो। मेरे बेटे का बिजनेस बहुत शानदार ढंग से चल रहा है। उसने इन दो महीनों में कई लाख कमा लिए हैं।'

रस्तोगी जी ने आश्चर्य से देखते हुए पूछा- 'अच्छा! किस चीज का बिजनेस कर रहा है आपने मुझे पहले नहीं बताया?'

उषा मैडम ने कहा, 'अरे! रस्तोगी जी, यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें न हींग लगे न फिटकरी, फिर भी रंग चोखा।'

रस्तोगी जी ने कहा,-'मैडम जी, आप यूं न पहेलियां बुझाइए। आखिर बताइए भी की ऐसा कौन सा बिजनेस है?'

'अरे, क्या बताऊं? इतना जबरदस्त कि पूछो मत।' उषा मैडम ने हंसते हुए कहा।

ओहो, अब बताइए भी तो? रस्तोगी जी बैचनी से बोले।

'एक शानदार बिजनेस और वो है साहित्य का धंधा।'

'ओह! साहित्य का बिजनेस मतलब साहित्य की किताबों की दुकान। उसमें तो आजकल कुछ लाभ नहीं है। पुस्तकों की ठेला लगाने वाले लोग अब मक्खी मारते बैठे रहते हैं। ऊंह! साहित्य की किताबें भला अब कौन पढ़ता है? सब तो फेसबुकिया हो गए हैं। सारा साहित्य सारा ज्ञान अब वाट्सएप और फेसबुक पर मिल रहा है। आजकल फेसबुकिया साहित्यकारों की तो भरमार है।' रस्तोगी जी ने चिंतित स्वर से कहा।

यह सुनकर उषा मैडम ने कहा, 'आपने ठीक कहा कि अब फेसबुकिया साहित्यकारों की भरमार है। बस यही हमारा बिजनेस है। ऐसे फेसबुक और वाट्सएप पर लिखने वाले साहित्यकारों को हम लोग ऑनलाइन पुरस्कार और सम्मान देते हैं।'

'मतलब'? रस्तोगी जी आश्चर्य से पूछा।

मतलब यह है कि ऐसे साहित्यकारों को फेसबुक और वाट्सएप पर फलाना ढिकाना सम्मान देने का प्रलोभन दिया जाता है। इसके लिए शर्त यह होता है कि हजार-पांच सौ की राशि पंजीयन आदि के नाम पर मांगी जाती है। हम लोग अपना खाता नंबर दे देते हैं और घर बैठे कमाई हो जाती है। अब सम्मान किसे नहीं चाहिए? भले ही पैसे से खरीदा हुआ हो। भई आजकल तो सम्मान खरीदे ही जा रहे हैं। साहित्यकार भी सम्मान पाकर फूले नहीं समाते और हम तो खुश ही हैं कि शिकार हमारी मुट्ठी में फंस जाता है। जैसे कोई शिकारी चिड़िया पकड़ने के लिए दाना डालता है वैसे ही हम लोग साहित्यकारों के लिए सम्मान का दाना डाल देते हैं फिर क्या सम्मान के लालच में साहित्यकार आ जाते हैं। अब तो ऐसे साहित्यकारों की संख्या बहुत बढ़ गई है। सभी सम्मान की होड़ में आगे निकलना चाहते हैं। हम लोग बस सम्मान पत्र थोक के भाव प्रिंट करवा लेते हैं बस। इधर खाते में रुपए आते हैं, उधर सम्मान दे दिया जाता है बाकि हमें कोई मतलब नहीं। अब बताइए है कि नहीं यह तगड़ा बिजनेस? फिर यह सिलसिला तो रुकता ही नहीं। दिनोंदिन सम्मान पत्रों की संख्या में इजाफा हो रहा है। देखा रस्तोगी जी साहित्य के इस उद्योग में कुछ खास करना नहीं पड़ता। मेरा बेटा तो बहुत खुश है। अब तो एक बड़े उद्योगपति के घर से उसके लिए रिश्ता भी आया है। अब तो बेटा इस बिजनेस को बढ़ाने की भी सोच रहा है।'

'वो कैसे?' रस्तोगी जी ने पूछा।

'वो ऐसे की आज साझा संग्रह निकालने का चलन हो गया है। इस सांझा संकलन के लिए कुछ रचनाएं मंगवा लें साथ ही साहित्यकारों से इस संकलन के लिए तीन-चार हजार ऐंठ ले। इसमें ऐसे साहित्यकार तुरंत शामिल हो जाते हैं जिनकी रचनाएं कभी कहीं भी नहीं छपतीं। ऐसे लोग झटपट अपनी रद्दी लाकर फेंक देते हैं। हमें उनकी रचनाओं से क्या मतलब हमें तो नकद नारायण चाहिए बस। आजकल तो बहुत से लोग ऐसे ही बिजनेस में लगे हुए हैं।'

यह सुनकर रस्तोगी जी ने कहा, 'सही फरमा रही हैं आप। आजकल साहित्यकार कुकुरमुत्ते की तरह गांव-शहर सभी जगह उग आए हैं। फेसबुक, वाट्सएप, इंस्टाग्राम से लेकर हर ग्रुप में कवि मिल जाएंगे जो अपनी बेतुकी कविताएं हर जगह फेंक जाते हैं। चाहे कोई पढ़े या न पढ़े। चलो ठीक है भगवान करे आपके बेटे का यह रोजगार खूब फले-फूले। अब तो शासन को भी चाहिए कि साहित्य के इस बिजनेस का रोजगार कार्यालय में पंजीयन करवाएं। इस धंधे में मैं भी हाथ आजमाना चाहता हूं।' यह कहते हुए रस्तोगी जी प्रफुल्लित मन से वहां से चले गए।

● **डॉ. शैल चन्द्रा**

वाटर हार्वेस्टिंग कराएं, जल सकंट से मुक्ति पाएं

बादल अमृत-सा जल लाता
अपने घर आंगन बरसाता
आओ करें इसका संग्रहण
बह ने जाए अमृत कलश
नदी नहर नल झील सरोवर
वापी कूप कुंड नद निर्झर
सर्वोत्तम सौन्दर्य प्रकृति का
कल-कल ध्वनि संगीत मनोहर
जल से अन्न पत्र फल पुष्पित सुन्दर उपवन है ।
जल पीकर जीते सब प्राणी जल ही जीवन है ।।

सौजन्य से : राष्ट्रीय पाक्षिक अक्स

विश्वसनीय खबरों के लिए पढ़ते रहिए

In Pursuit of Truth

पाक्षिक अक्स

www.akshnews.com

लॉगऑन करें

www.akshnews.com

वार्षिक सदस्यता के लिए संपर्क करें, 150, जोन-1, एम.पी.नगर भोपाल
फोन:0755-4017788,2575777

D-17008